

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 31]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 1, 1970/श्रावण 10, 1892

No. 31]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 1, 1970/SRAVANA 10, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नोटिस

NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 29 जून, 1970 तक प्रकाशित किये गये :—

The unmentioned Gazettes of India Extraordinary were published up to the 29th June 1970 :—

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
203	S.O. 1983 dated 30th May, 1970.	Ministry of Finance	Exemption of classes of claims mentioned in the Schedule.
	एस० ओ० 1983 दिनांक 30 मई, 1970	वित्त मंत्रालय	केन्द्रीय सरकार उक्त अनुसूची में वर्णित दावों के वर्गों को छूट देती है।
204	S.O. 1984 dated 1st June, 1970.	Ministry of Industrial Development Internal Trade and Company Affairs.	Appointment of persons to investigate the Closure of Standard Motor products of India Ltd., Madras, by the Central Government.
	एस० ओ० 1984 दिनांक 1 जून, 1970	औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और कम्पनी कार्य मंत्रालय	केन्द्रीय सरकार स्टैंडर्ड मोटर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, मद्रास के बन्द होने के कारण का अन्वेषण करने के लिए व्यक्तियों को नियुक्त करती है।

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
205	S.O. 1985 dated 2nd June, 1970.	Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation.	Schemes made by the Central Government for the Calcutta Dock Workers (Regulations of Employment) Scheme, 1970.
206	S.O. 2052/15/IDRA/70 dated the 2nd June, 1970.	Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs.	Appointment of persons to investigate the economic conditions of Seksaria Cotton Mills Ltd., Bombay (Maharashtra) by the Central Government.
	एस० ओ० 2062/15/ आई० डी० आर० ए०/ 70, दिनांक 2 जून, 1970	औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय	केन्द्रीय सरकार सेक्सेरिया काटन मिल्स लिमिटेड, बम्बई (महाराष्ट्र) की आर्थिक स्थिति के अन्वेषण के लिए व्यक्तियों को नियुक्त करती है।
207	S.O. 2063/15/IDRA/70 2nd June 1970.	Ditto.	Appointment of persons to investigate the economic conditions of the Jaya Shankar Mills, Barsi Ltd., Barsi Distt. Sholapur (Maharashtra) by the Central Government.
	का० आ० 2063/15/आई० डी० आर० ए०/70 दिनांक 2 जून 1970	तदैव	केन्द्रीय सरकार दि जयशंकर मिल्स बारसी लि०, बारसी, जिला शोलापुर (महाराष्ट्र) की आर्थिक स्थिति के अन्वेषण के लिए व्यक्तियों को नियुक्त करती है।
	का० आ० 2064, दिनांक 3 जून, 1970	वित्त मंत्रालय	वित्त मंत्रालय (राजस्व और वित्त विभाग) के असाधारण राज- पत्र, भाग 2, खण्ड 3, उप- खण्ड (II), तारीख 23 फरवरी, 1970 में कुछ संशोधन।
209	S.O. 2065 dated 9th June, 1970.	Ministry of Foreign Trade.	Amendment of notification of the Late Ministry of Commerce No. S.O. 1616 dated the 7th May, 1968.
	का० आ० 2065 दिनांक 4 जून, 1970	विदेशी व्यापार मंत्रालय	भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय की अधि- सूचना सं० का० आ० 1616 तारीख 7 मई, 1968 में कुछ संशोधन।
210	S.O. 2066 dated 4th June, 1970.	Election Commission of India.	Amendment of Notification No. 56/69-II (S.O. 89) dated the 4th January, 1969

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
	एस० आ० 2066 दिनांक 4 जून, 1970	भारत निर्वाचन आयोग	अधिसूचना सं० 56/69-II (का० आ० 89) दिनांक 4 जनवरी, 1969 में कुछ संशोधन ।
211	S.O. 2067 dated 4th June, 1970.	Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation.	Declaration of variety of seeds specified in the corresponding entry in column (2) of the Table thereto by the Central Government.
	एस० आ० 2067 दिनांक, 4 जून, 1970	खाद्य, कृषि, सामुदायिक केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय बीज विकास और सहकारिता मंत्रालय	समिति के परामर्श के बाद, तालिका के स्तम्भ (2) की तदनुरूपी किस्म को अधिसूचित किस्म घोषित करती है ।
	S.O. 2068 dated 4th June, 1970.	D to.	Declaration of minimum limits of germination and Purity of seeds as shown in the table thereto by the Central Government.
	एस० आ० 2068 दिनांक 4 जून, 1970	तदैव	केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय बीज समिति बीजों के अंकुरण और शुद्धता की न्यूनतम सीमा के रूप में विनिश्चित करती है ।
212	S.O. 2069 dated 5th June, 1970.	Ministry of Irrigation and Power.	Declaration of generation, storage or transmission of electrical energy as an essential service by the Central Government in the state of Bihar.
	का० आ० 2069 दिनांक 5 जून, 1970	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय	केन्द्रीय सरकार बिहार राज्य में विद्युत शक्ति की आपूर्ति के प्रयोजनार्थ विद्युत शक्ति के उत्पादन भंडारकरण या संचरण से सम्बन्धित ऐसी हर सेवा को आवश्यक सेवा घोषित करती है ।
	S.O. 2070 dated 5th June, 1970.	Dirto.	Prohibition of strikes by the Central Government in the state of Bihar for essential services.
	का० आ० 2070 दिनांक 5 जून, 1970	तदैव ]	केन्द्रीय सरकार बिहार राज्य में हड़तालों का प्रतिषेध करती है ।

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
213	S.O. 2071 dated 5th June, 1970.	Ministry of Information and Broadcasting	Approval of Films specified in column 2 of the schedule thereto
	एस० आ० 2071 दिनांक 5 जून, 1970	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों को स्वीकृत करना ।
	S.O. 2072 dated 5th June, 1970.	Ditto.	Approval of Films specified in column 2 of the schedule thereto.
	एस० आ० 2072 दिनांक 5 जून, 1970	तदैव	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों को स्वीकृत करना ।
	S.O. 2073 dated 5th June, 1970.	Ditto.	Approval of Films specified in column 2 of the schedule thereto
	एस० आ० 2073 दिनांक 5 जून, 1970	तदैव	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों को स्वीकृत करना ।
214	S.O. 2074 dated 5th June, 1970.	Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs.	Constitution of a Commission for recommendation of the fair selling prices of passengers car i.e. Ambassador, Fiat and Standard.
	का० आ० 2070 दिनांक 5 जून, 1970	औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और कम्पनी कार्य मंत्रालय	एम्बेसेडर, फिएट और स्टैण्डर्ड कारों के उचित विक्रय कीमतों के प्रयोजनार्थ एक आयोग गठित किया गया है ।
215	S.O. 2137 dated 5th June, 1970.	Ministry of Foreign Trade.	Quality Control and preshipment Inspection of dried Fish
	का० आ० 2137 दिनांक 5 जून, 1970	विदेशी व्यापार मंत्रालय	निर्यात से पूर्व सूखी मछलियों का गुण नियंत्रण और निरीक्षण
	S.O. 2138 dated 5th June, 1970.	Ditto.	Export of dried Fish (Inspection) Rules, 1970.
	का० आ० 2138 दिनांक 5 जून, 1970	तदैव	सूखी मछलियों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1970

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
216	S.O. 2139 dated 10th June, 1970.	Ministry of Information and Broadcasting.	Approval of Films specified in column 2 of the schedule thereto.
	एस० आ० 2139 दिनांक 10 जून, 1970	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों को स्वीकृत करना ।
	S.O. 2140 dated 10th June, 1970.	Ditto.	Approval of Films specified in column 2 of the schedule thereto.
	एस० आ० 2140 दिनांक 10 जून, 1970	—तदैव—	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों को स्वीकृत करना ।
217	S.O. 2141 dated 10th June, 1970.	Ministry of Foreign Trade.	Coir Retting (Licensing) Amendment Order, 1970.
218	S.O. 2142 dated 11th June, 1970.	Ministry of Law	Bye-election to the House of the People from the 51-Kunti Parliamentary Constituency in the State of Bihar.
	का० आ० 2142 दिनांक 11 जून, 1970	विधि मंत्रालय	बिहार राज्य में 51 खूटी संसदीय क्षेत्र से लोक सभा के लिए उप-निर्वाचन ।
219	S.O. 2143 dated 12th June, 1970	Ministry of Home Affairs.	Declaration as active duty by every person in the State of Assam by the Central Government.
	सा० नि० 2143 दिनांक 12 जून, 1970	गृह मंत्रालय	केन्द्रीय सरकार द्वारा असम प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति के लिए सक्रिय ड्यूटी घोषित ।
	S.O. 2144 dated 12th June, 1970.	Ditto.	Declaration as active duty by every person in the State of Tripura by the Central Government.
	सा० नि० 2144 दिनांक 12 जून, 1970	—तदैव—	केन्द्रीय सरकार द्वारा त्रिपुरा में प्रत्येक व्यक्ति के लिए सक्रिय ड्यूटी घोषित ।
	S.O. 2145 dated 12th June, 1970.	Ditto.	Declaration as active duty by every person in Gujarat by the Central Government.
	सा० नि० 2145 दिनांक 12 जून, 1970	—तदैव—	केन्द्रीय सरकार द्वारा गुजरात में प्रत्येक व्यक्ति के लिए सक्रिय ड्यूटी घोषित ।

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
	S.O. 2146 dated 12th June, 1970.	Ministry of Home Affairs	Declaration as active duty by every person in Chandigarh by the Central Government.
	सा० नि० 2146 दिनांक 12 जून, 1970	गृह मंत्रालय	केन्द्रीय सरकार द्वारा चण्डीगढ़ में प्रत्येक व्यक्ति के लिए सक्रिय ड्यूटी घोषित ।
	S.O. 2147 dated 12th June, 1970.	Ditto.	Declaration as active duty by every person in Jammu and Kashmir by the Central Government.
	सा० नि० 2147 दिनांक 12 जून, 1970	—तदैव—	केन्द्रीय सरकार द्वारा जम्मू तथा काश्मीर में प्रत्येक व्यक्ति के लिए सक्रिय ड्यूटी घोषित ।
	S.O. 2148 dated 12th June, 1970.	Ditto.	Declaration as active duty by every person in Punjab by the Central Government.
	सा० नि० 2148 दिनांक 12 जून, 1970	—तदैव—	केन्द्रीय सरकार द्वारा पंजाब में प्रत्येक व्यक्ति के लिए सक्रिय ड्यूटी घोषित ।
220	S.O. 2192 dated 15th June, 1970.	Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals.	Amendment of S.O. No. 1875 of 18th May, 1970 by the Central Government.
	S.O. 2193 dated 15th June, 1970.	Ditto.	Drugs (Prices Control) Amendment Order, 1970.
	S.O. 2193-A dated 15th June, 1970.	Ditto.	Corrigendum to S.O. No. 1752 of 16th May, 1970.
221	S.O. 2194 dated 16th June, 1970.	Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation.	Fixation of tariff value of cashew kernel by the Central Govt.
	एस० ओ० 2194 दिनांक 16 जून, 1970	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सह-कारिता मंत्रालय	केन्द्रीय सरकार द्वारा काजू की गिरी का टैरिफ मूल्य नियत करना ।
222	S.O. 2195 dated 17th June, 1970.	Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals.	Further amendment of S.O. No. 1873 of 18th May, 1970 by the Central Government.
223	S.O. 2196 dated 18th June 1970.	Ministry of Irrigation and Power.	Declaration of generation, storage or Transmission of electric energy as an essential service in the State of Assam.

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
	का० आ० 2196 दिनांक 18 जून, 1970	सिचाई और विद्युत मंत्रालय	केन्द्रीय सरकार आसाम राज्य में विद्युत शक्ति की आपूर्ति के प्रयोजनार्थ विद्युत शक्ति के उत्पादन, भंडारकरण या संचरण से संबंधित ऐसी हर सेवा को आवश्यक घोषित करती है ।
	S.O. 2197 dated 18th June, 1970.	Ditto.	Prohibition of strikes by the Central Government in the state of Assam for essential services.
	का० आ० 2197 दिनांक 18 जून, 1970	—तदैव—	केन्द्रीय सरकार आसाम राज्य में हड़तालों का प्रतिरोध करती है ।
224	S.O. 2198 dated 18th June, 1970.	Ministry of Information and Broadcasting.	Approval of Films specified in column 2 of the Schedule thereto.
	एस० ओ० 2198 दिनांक 18 जून, 1970	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों को स्वीकृत करना ।
	S.O. 2199 dated 18th June, 1970.	Ditto.	Approval of Films specified in column 2 of the schedule thereto.
	एस० ओ० 2199 दिनांक 18 जून, 1970	—तदैव—	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों को स्वीकृत करना ।
225	S.O. 2200 dated 19th June, 1970.	Ministry of Law	Bye-election to the House of the People from the 18-Durg Parliamentary Constituency in the State of Madhya Pradesh.
	का० आ० 2200 दिनांक 19 जून, 1970	विधि मंत्रालय	मध्य प्रदेश राज्य में 18-दुर्ग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिये उपनिर्वाचित ।
226	S.O. 2201 dated 20th June, 1970.	Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation.	Fixation of Tariff value specified in column 4 of the schedule by the Central Government.
	एस० ओ० 2201 दिनांक 20 जून, 1970	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सह-कारिता मंत्रालय	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूची के कालम 4 में दी गई चीजों का टैरिफ मूल्य निश्चित करना ।

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
227	S.O. 2202/18-A/IDRA/70, dated 20th June, 1970.	Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs.	Taking over of Rajkot Spg. & Wvg Mills Ltd., Rajkot by the Gujarat State Textile Corporation Ltd., Ahmedabad.
	का० आ० 2202/18 ए०/ आई० डी० आर० ए०/ 70, दिनांक 20 जून, 1970	औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय	(गुजरात राज्य कपड़ा निगम लि० गुजरात स्टेट टेक्स्टाइल कार्प पोरेशन) अहमदाबाद द्वारा राजकोट स्पिनिंग एण्ड वीविंग मि० लिमिटेड, राजकोट को अपने अधिकार में लेना।
228	S.O. 2203, dated 22nd June, 1970.	Ministry of Finance	Notification by the Central Govt. for the Market Committee.
	एस० आ० 2203 दिनांक वित्त मंत्रालय 22 जून, 1970		केन्द्रीय सरकार द्वारा बाजार समितियों को अधिसूचित करना।
229	S.O. 2204 dated 22nd June, 1970.	Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation.	Fixation of maximum prices of vegetable oil products.
	का० आ० 2204 दिनांक 22 जून, 1970	खाद्य, कृषि, सामु- दायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय	वनस्पति तेल उत्पादकों का अधिकतम मूल्य निश्चित करना।
230	S.O. 2241 dated 26th June, 1970.	Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs.	Declaration by the Central Govt. as essential commodities for the purpose of manufacture of Electrical Cables and wires.
	एस० आ० 2241 दिनांक 26 जून, 1970	औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और कम्पनी कार्य मंत्रालय	केन्द्रीय सरकार द्वारा विद्युत कैबल और तारों को विनिर्माण के लिए आवश्यक वस्तुएं घोषित करना।
231	S.O. 2242 dated 26th June, 1970.	Cabinet Secretariat	Govt of India (Allocation of Business) (Eighty-Second Amendment) Rules, 1970.
232	S.O. 2243 dated 27th June, 1970.	Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation.	Direction by the Central Govt. bearing S.O. 5060 of 27th Dec. 1969 to remain in force.
	का० आ० 2243 दिनांक 27 जून, 1970	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सह- कारिता मंत्रालय	केन्द्रीय सरकार द्वारा 27 दिस- म्बर, 1969 का आदेश का० आ० 5060 को प्रवृत्त करना।

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
233	S.O. 2244 dated 27th June, 1970. एस० ओ० 2244 दिनांक 27 जून, 1970	Ministry of Information and Broadcasting. सूचना और प्रसारण मंत्रालय	Approval of films specified in column 2 of the Schedule thereto. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों को स्वीकृत करना।
234	S.O. 2245 dated 27th June, 1970. एस० ओ० 2245 दिनांक 27 जून, 1970	Ministry of Information and Broadcasting. सूचना और प्रसारण मंत्रालय	Approval of film specified in column 2 of the schedule thereto. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों को स्वीकृत करना।
235	S.O. 2246 dated 27th June, 1970. एस० ओ० 2246 दिनांक 27 जून, 1970	Election Commission of India. भारत निर्वाचन आयोग	Amendment of Notification No. 56/69 II (S.O.89) of 4th January, 1969. अधिसूचना संख्या 56/69=II (एस० ओ० 89) तारीख 4 जनवरी, 1969 में कुछ संशोधन।
236	S.O. 2247 dated 27th June, 1970.	Cabinet Secretariat	Govt. of India (Allocation of Business) (Eighty-third Amendment) Rules, 1970.
237	S.O. 2248 dated 29th June, 1970. का० आ० 2248 दिनांक 29 जून, 1970	Ministry of Finance वित्त मंत्रालय	Amendment of S.O. 1206 of 24th May, 1961 by the Central Govt. केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना का० आ० 1206 दिनांक 24 मई, 1961 में कुछ संशोधन।
238	S.O. 2249 dated 29th June, 1970. का० आ० 2249 दिनांक 29 जून, 1970	Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation. श्रम, रोजगार और पुनर्वासि मंत्रालय	Appointment of a Administrative Body for Calcutta Shipping and Painting Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970 by the Central Govt. केन्द्रीय सरकार द्वारा कलकत्ता छंटाई और रंगाई कारगराये (नियोजन का विनियमन), स्कीम, 1970 के प्रतिदिन के प्रशासन को चलाने के लिये प्रशासनिक निकाय नियुक्त करना।

ऊपर लिखे प्रसारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबंधक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांगपत्र भेजने पर भेजी जाएंगी। मांगपत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख से 10 दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिए।

Copies of the Gazettes Extraordinary mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

**भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)**

**PART II—Section 3—Sub-section (ii)**

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ क्षेत्र प्रशासन को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकरणों द्वारा जारी किये गये विधिक आदेश और अधिसूचनाएं ।

**Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).**

**VICE PRESIDENT'S SECTT.**

*New Delhi, the 9th July 1970*

**S.O. 2540.**—The Vice-President of India, in his capacity as the Chancellor of the Panjab University, Chandigarh, has in exercise of his powers under Sub-Section (1) of Section 17, of the Panjab University Act has accepted the resignation of Shri S. D. Vashist from the Ordinary Fellowship of the Panjab University, Chandigarh.

Further, in exercise of his powers under Sub-Section (1)(i) of Section 13, of the Panjab University Act, the Chancellor is pleased to nominate Shri R. C. D. Kaushik, Principal, Technological Institute of Textiles, Bhiwani, as Ordinary Fellow vice Shri S. D. Vashist.

[No. VPS/PU/70.]

V. PHADKE, Secy.

**उपराष्ट्रपति सचिवालय**

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 1970।

**एस०ओ० 2540.**—भारत के उपराष्ट्रपति, पंजाब विश्वविद्यालय, चंदीगढ़ के कुलाधिपति की हैसियत से पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री एस० डी० वशिष्ठ का पंजाब विश्वविद्यालय चंदीगढ़ की साधारण पार्षद के पद से त्याग पत्र स्वीकार करते हैं।

अग्रिम, पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) (जे) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कुलाधिपति, वस्त्र प्रौद्योगिक संस्थान (टेक्नीकल इन्स्टीट्यूट आफ टेक्स्टायल), भिवानी, के प्राचार्य, श्री आर० सी० डी० कौशिक को श्री एस० डी० वशिष्ठ के स्थान पर साधारण पार्षद मनोनीत करते हैं।

[सं० वी०पी०एस०/पी०यू०/70]

वी० फडके, सचिव ।

**ELECTION COMMISSION OF INDIA**

**ORDERS**

*New Delhi, the 27th June 1970*

**S.O. 2541.**—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Sewak Singh, r/o village Marchi, P.O. Marchi, District Patna (Bihar), a contesting candidate for the mid-term election to the Bihar Legislative Assembly held in 1969 from 204-Patna South, Assembly Constituency, has failed to lodge an account of his election

expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Sewak Singh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[BR-LA/204/69(100).]

## भारत निर्वाचन आयोग

### आदेशों

दिल्ली, 27 जून, 1970

**एस० आ० 2541.**—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि बिहार विधान सभा के लिए 1969 में हुए मध्यवर्धि निर्वाचन के लिए 204-पटना साउथ निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रामसेवक सिंह, निवासी ग्राम—मरची, प्पो 0 मरची, जिला पटना (बिहार), लोक-प्रतिनिध्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है ; तथा निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री रामसेवक सिंह के सदस्य के दोनों सदनों से किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कलावधि के लिए निरहित घोषित करता है ।

[सं० बिहार वि० सं०/204/69 (100)]

**S.O. 2542.**—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Nand Keshwar Prasad, r/o. village Uprawan, P.O. Biharsharif, District Patna (Bihar), a contesting candidate for the mid-term election to the Bihar Legislative Assembly held in 1969 from 197-Ekangersarai Assembly Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Nand Keshwar Prasad, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/197/69(101).]

By Order,

ROSHAN LAL, Secy.

एन० ओ० 2542.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि बिहार विधान सभा के लिए 1969 में मध्यवर्षी निर्वाचन के लिए 197-एंगरमराय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री नन्दकेश्वर प्रसाद, निवासी ग्राम उधरावाँ, पो०—बिहार मरीफ, जिला, पटना (बिहार) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, तथा निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री नन्दकेश्वर प्रसाद को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है ।

[सं०—बिहार वि० सं०/197/69(101)]

आदेश से,

रोशन लाल,

सचिव, भारत निर्वाचन आयोग ।

#### ORDERS

New Delhi, the 29th June 1970

S.O. 2543.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Vibekananda Biswas, Village Hatishala, P.O. Dignagar, District Nadia, a contesting candidate for the mid-term election held in February, 1969, to the West Bengal Legislative Assembly from 80-Galgghata constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Vibekananda Biswas to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. WB-LA/80/69/(23A).]

आदेशों

नई दिल्ली, 29 जून, 1970

एस०ओ० 2543.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि पश्चिमी बंगाल विधान सभा के लिए फरवरी, 1969 में हुए मध्यवर्षी निर्वाचन के लिए 80—गायघाट निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री विवेकानन्दा विश्वास, ग्राम—हाथीशाला, पो०—दिगनगर, जिला नदिया, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उस सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है ; तथा निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री विवेकानन्दा विश्वास को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के या किसी राज्य को विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० प०ब०-वि०स०/80/69.(23क)]

*New Delhi, the 4th July 1970*

**S.O 2544.**—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Gadadhar Das, Village & P.O. Indus, District Bankura (West Bengal), a contesting candidate for the mid-term election held in February, 1969, to the West Bengal Legislative Assembly from 242, Indus constituency, has failed to lodge an account of election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Gadadhar Das to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. WB LA/242/69/(28).]

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 1970

एस०ओ० 2544 .—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि पश्चिमी बंगाल विधान सभा के लिए फरवरी, 1969 में हुए मध्यावधि निर्वाचन के लिए 242—इन्दाम निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री गदाधर दाम, ग्राम एवं पो०—इन्दाम, जिला—बांकुरा (पश्चिमी बंगाल) लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, तथा निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्याय्य चिन्त्य नहीं है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री गदाधर दास को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० प०ब०-वि०स० 242/69 (28)]

*New Delhi, the 7th July 1970*

**S.O. 2545.**—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Azizur Rahaman Mondal, Village Masia, P.O. Nayabastia, District 24-Parganas, West Bengal, a contesting candidate for the mid-term election held in February, 1969, to the West Bengal Legislative Assembly from Swarupnagar constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Azizur Rahaman Mondal to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of State for a period of three years from the date of this order.

[No. WB-LA/86/69(29).]

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 1970

एस०ओ० 2545.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि पश्चिमी बंगाल विधान सभा के लिए फरवरी, 1969 में हुए मध्यावधि निर्वाचन के लिए स्वरूप नगर निर्वाचन-क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अज़ी-जुर रहमान मंडल, ग्राम एवं मौजा पो० नयाबस्तिथा, जिला—24—परगना, पश्चिमी बंगाल, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है ; तथा निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुवर्णन में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री अज़ी-जुर रहमान मंडल को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करना है।

[मं०-प०-ब०-वि०स०/86/69 (29)]

New Delhi, the 8th July 1970

S O. 2546.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Sachinandan Baidya, Village Palta, P.O. Katiahat, District 24-Parganas (West Bengal), a contesting candidate for the mid term election held in February, 1969, to the West Bengal Legislative Assembly from 87, Baduria constituency, has failed to lodge an account of his election expenses within time and in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, after considering the representation made by the said candidate, the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Sachinandan Baidya to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. WB-LA/87/69/(30).]

नई दिल्ली, 8 जुलाई 1970

एस०ओ० 2546.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि पश्चिमी बंगाल विधान सभा के लिए फरवरी, 1969 में हुए मध्यावधि निर्वाचन के लिए 87—ब्रदुरिया निर्वाचन-क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सचिनन्दन बैद्य, ग्राम—पलटा, पो०—कटियाहाट, जिला 24—परगना (पश्चिमी बंगाल), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति या समय अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है ; तथा निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री सचिनन्दन वैद्य को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं०प०ब०-वि०स०/87/69 (30)]

**S.O. 2547.**—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Baldau, S/o Shri Ram Raj, R/o Village and Post Office Pali, District Gorakhpur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly from 192 Sahjanwan Assembly Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Baldau, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No UP-LA/192/69(54).]

By Order,

V NAGASUBRAMANIAN, Secy.

**एस० ओ० 2547.**—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिये 192 सहजनवा-सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बलदाउ सुपुत्र श्री रामराज, निवासी गांव तथा डा० पाली जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है ; तथा निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायीचित्य नहीं है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री बलदाउ को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं०उ०प्र०-वि०स०/192/69/(54)]

आदेश से,

वी० नागसुब्रमन्यन, सचिव।

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 15th July 1970

**S. O 2548** — Where arrangements have been made by the Central Government with the Government of Sweden for taking the evidence of witnesses residing in Sweden in relation to criminal matters pending in courts in India, the Central Government, in pursuance of sub-section(3)

of section 504 of the Code of Criminal Procedure, 1898 (5 of 1898), hereby directs that Commissions for the examination of witnesses in Sweden shall be issued by the Courts in India in the form annexed hereto, to the following courts, namely:—

<i>Name of Court</i>	<i>Name of place where situated</i>
I	2
1. Falu domsaga . . . . .	Falun
2. Gotlands domsaga . . . . .	Visby
3. Gästriklands västra domsaga . . . . .	Storvik
4. Gästriklands östra domsaga . . . . .	Gavle
5. Hedemora domsaga . . . . .	Hedemora
6. Karlaskoga domsaga . . . . .	Karlaskoga
7. Lindes och Nora domsaga . . . . .	Lindesberg
8. Livgädingens domsaga . . . . .	Eskilstuna
9. Mellersta Roslags domsaga . . . . .	Norrköping
10. Nedansiljans domsaga . . . . .	Leksand
11. Norra Roslags domsaga . . . . .	Osthammar
12. Nyköpings domsaga . . . . .	Nyköping
13. Näs och Malungs domsaga . . . . .	Malung
14. Oppunda och Villåttinge domsaga . . . . .	Katrineholm
15. Övansiljans domsaga . . . . .	Mora
16. Sollentuna och Färentuna domsaga . . . . .	Solna
17. Solna domsaga . . . . .	Solna
18. Stockholms län västra domsaga . . . . .	Stockholm
19. Svartlösa domsaga . . . . .	Huddinge
20. Södertörns domsaga . . . . .	Stockholm
21. Södra Roslags domsaga . . . . .	Stockholm
22. Uppsala län norra domsaga . . . . .	Uppsala
23. Uppsala län södra domsaga . . . . .	Uppsala
24. Västbergslags domsaga . . . . .	Ludvika
25. Västernärkes domsaga . . . . .	Örebro
26. Västmanlands mellersta domsaga . . . . .	Västeraås
27. Västmanlands västra domsaga . . . . .	Köping
28. Västmanlands östra domsaga . . . . .	Sala
29. Östernärkes domsaga . . . . .	Örebro
30. Aska, Dals och Böbergs domsaga . . . . .	Motala
31. Brälgrens och Finspångs län domsaga . . . . .	Norrköping
32. Fölkungabygdens domsaga . . . . .	Mjölby
33. Hammarkinds, Stegeborgs och . . . . .	Söderköping
34. Skarvinds domsaga . . . . .	Lidköping
35. Kinnefjärdings, Kinne och Kallands domsaga . . . . .	Lidköping
36. Linköpings domsaga . . . . .	Linköping
37. Mellersta Värmds domsaga . . . . .	Vaxjö
38. Njudungs domsaga . . . . .	Vetlanda
39. Norra och Södra Veddö domsaga . . . . .	Eksjö
40. Oskarshamns domsaga . . . . .	Oskarshamn
41. Skarabygdens domsaga . . . . .	Skara
42. Skövde domsaga . . . . .	Skövde
43. Sunnerbo domsaga . . . . .	Ljungby
44. More och Ölands domsaga . . . . .	Kalmar
45. Tverå, Vista och Mo domsaga . . . . .	Jönköping
46. Vadsbo domsaga . . . . .	Maricstad
47. Vartofta och Frökindens domsaga . . . . .	Falköping
48. Västra Värmds domsaga . . . . .	Alvesta
49. Västerviks domsaga . . . . .	Västervik
50. Åse, Viste, Barne och Laske domsaga . . . . .	Vara
51. Östbo och Västbo domsaga . . . . .	Värnamo
52. Östra Värmds domsaga . . . . .	Vaxjö
53. Bräcke och Karlshamns domsaga . . . . .	Karlshamn
54. Fröå och Eslovs domsaga . . . . .	Eslov
55. Ingelstads och Järrestads domsaga . . . . .	Simrishamn
56. Kristianstads domsaga . . . . .	Kristianstad
57. Lister och Solvesborgs domsaga . . . . .	Solvesborg
58. Luggude domsaga . . . . .	Helsingborg
59. Norra Åsbo domsaga . . . . .	Klippan
60. Öxi och Skytts domsaga . . . . .	Malmö

61. Landskrona domsaga	Landskrona
62. Sodra Asbo och Bjare domsaga	Angelholm
63. Torna och Bara domsaga	Lund
64. Vastra Goinge domsaga	Hassleholm
65. Ystads domsaga	Ystad
66. Ostra och Medelsta domsaga	Ronneby
67. Askims och Molndals domsaga	Goteborg
68. Boras domsaga	Boras
69. Flundre, Vane och Bjarke domsaga	Trollhattan
70. Fryksdas domsaga	Sunne
71. Hallands mellersta domsaga	Falkenberg
72. Hallands norra domsaga	Kungsbacka
73. Hollands sodra domsaga	Halmstad
74. Hisinge, Savedals och Kungälv's domsaga	Goteborg
75. Jösse domsaga	Arvika
76. Kins och Redvags domsaga	Ulricehamn
77. Marks domsaga	Skene
78. Mellansysslets domsaga	Kerlstad
79. Vännerborgs domsaga	Vännersborg
80. Nordmarka domsaga	Arjang
81. Norrvikens domsaga	Stromstad
82. Orusts, Tjorns och Inlands domsaga	Stenungsund
83. Sunnervikens domsaga	Uddevalle
84. Sodersysslets domsaga	Saffle
85. Tossbo och Vedbo domsaga	Amal
86. Vattle, Ale och Kullings domsaga	Alingsas
87. Alvdals och Nyeds domsaga	Karlstad
88. Ostersysslets domsaga	Kristinehamn
89. Bollns domsaga	Bollnas
90. Harjedalens domsaga	Sveg
91. Jamtlands norra domsaga	Ostersund
92. Jamtlands vstra domsaga	Ostersund
93. Jamtlands ostra domsaga	Ostersund
94. Medelpads domsaga	Sundsvall
95. Norra Halsinglands domsaga	Hudiksvall
96. Sydostre Halsinglands domsaga	Soderhamn
97. Vstra Halsinglands domsaga	Ljusdal
98. Solleftea domsaga	Solleftea
99. Angermanlands norra domsaga	Ornskoldsvik
100. Angermanlands sodra domsaga	Harnosand
101. Gallivare domsaga	Gallivare
102. Kalix domsaga	Kalix
103. Bodens domsaga	Boden
104. Pitea domsaga	Pitea
105. Tornea domsaga	Haparanda
106. Skelleftea domsaga	Skelleftea
107. Vasterbottens mellersta domsaga	Umea
108. Vasterbottens vstra domsaga	Lycksele
109. Vasterbottens sodra domsaga	Umea
110. Radhusratten i Eskilstuna	Eskilstuna
111. Radhusratten i Gavle	Gavle
112. Radhusratten i Stockholm	Stockholm
113. Radhusratten i Sodertalje	Sodertalje
114. Radhusratten i Uppsala	Uppsala
115. Radhusratten i Vasteras	Vasteras
116. Radhusratten i Orebro	Orebro
117. Radhusratten i Jonkoping	Jonkoping
118. Radhusratten i Kalmar	Kalmar
119. Radhusratten i Linkoping	Linkoping
120. Radhusratten i Motala	Motala
121. Radhusratten i Norrkoping	Norrkoping
122. Radhusratten i Vaxjo	Vaxjo

123. Radhusratten i Borås . . . . .	Borås
124. Radhusratten i Göteborg . . . . .	Göteborg
125. Radhusratten i Halmstad . . . . .	Halmstad
126. Radhusratten i Karlstad . . . . .	Karlstad
127. Radhusratten i Uddevalla . . . . .	Uddevalla
128. Radhusratten i Varberg . . . . .	Varberg
129. Radhusratten i Östersund . . . . .	Östersund
130. Radhusratten i Malmö . . . . .	Malmö
131. Radhusratten i Karlskrona . . . . .	Karlskrona
132. Radhusratten i Lund . . . . .	Lund
133. Radhusratten i Sundsvall . . . . .	Sundsvall
134. Radhusratten i Malmö . . . . .	Malmö
135. Radhusratten i Umeå . . . . .	Umeå
136. Radhusratten i Luleå . . . . .	Luleå

2. The Central Government further directs that such Commissions shall be sent to the Ministry of External Affairs, Government of India, New Delhi, for transmission to the Court concerned.

### IN THE COURT OF

Commission to examine witness outside India

[Section 504(3) of the Code of Criminal Procedure, 1898]

To

Through the Ministry of External Affairs, Government of India, New Delhi.

Whereas it appears to me that the evidence of \_\_\_\_\_ is necessary for the ends of justice in case No. \_\_\_\_\_ Vs. \_\_\_\_\_ in the court of \_\_\_\_\_ and that such witness is residing within the local limits of your jurisdiction and his attendance cannot be procured without un-reasonable delay, expense or inconvenience, I \_\_\_\_\_ have the honour to request and do hereby request that for the reasons aforesaid and for the assistance of the said Court you will be pleased to summon the said witness to attend at such time and place as you shall appoint and that you will cause such witness to be examined upon the interrogatories which accompany this commission (for *viva voce*).

Any party to the proceeding may appear before you by his counsel or agent or if not in custody, in person and may examine, cross examine or re-examine (as the case may be) the said witness.

And I further have the honour to request that you will be pleased to cause the answers of the said witnesses to be reduced into writing and all books, letters, papers, and documents produced upon such examination to be duly marked for identification and that you will be further pleased to authenticate such examination by your official seal (if any) and by your signature and to return the same together with this commission to the undersigned through the Ministry of External Affairs, Government of India, New Delhi.

Given under my hand and the seal of the Court this day of \_\_\_\_\_ 19

Judge,

District Magistrate, Presidency Magistrate.

[No. F. 5/1/70-Jud.I.I.]

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1970

सं० फा० नि० 2548.—जबकि केन्द्रीय सरकार ने स्वीडन सरकार के साथ, भारतीय न्यायालयों में प्रतिनिधित्व मामलों में उस राज्य में वासी गवाहों के साक्ष्य प्राप्त करने के लिये प्रबंध है

केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रक्रिया संहिता 1898 (1898 का 5) की धारा 504 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा निदेश देती है कि स्वीडन में गवाहों से पूछताछ के लिये भारतीय न्यायालय निम्नलिखित न्यायालयों के मंगल प्रपत्र में आयोग पत्र जारी करेंगे, अर्थात् :—

न्यायालय का नाम	न्यायालय के स्थान का नाम
1. Falu domsaga	Falun
2. Gotlands domsaga	Visby
3. Gästriklands Västra domsaga	Storvik
4. Gästriklands östra domsaga	Gävle
5. Hedemora domsaga	Hedemora
6. Karlaskoga domsaga	Karlaskoga
7. Lindes och Nora domsaga	Lindesberg
8. Livgedingets domsaga	Eskilstuna
9. Mellersta Roslags domsaga	Norrälja
10. Nedansiljans domsaga	Leksand
11. Norra Roslags domsaga	Osthammar
12. Nyköpings domsaga	Nyköping
13. Nas och Malungs domsaga	Malung
14. Öppunda och Villattinge domsaga	Katrineholm
15. Övansiljans domsaga	Mora
16. Sollentuna och Färentuna domsaga	Solna
17. Solna domsaga	Solna
18. Stockholms län västra domsaga	Stockholm
19. Svalövs domsaga	Huddinge
20. Södertörns domsaga	Stockholm
21. Södra Roslags domsaga	Stockholm
22. Uppsala län norra domsaga	Uppsala
23. Uppsala län södra domsaga	Uppsala
24. Västbergslags domsaga	Ludvika
25. Västernärkes domsaga	Örebro
26. Västmanlands mellersta domsaga	Västeraås
27. Västmanlands västra domsaga	Köping
28. Västmanlands östra domsaga	Sala
29. Östernärkes domsaga	Örebro
30. Åska, Dals och Bobergs domsaga	Motala
31. Bräbygdens och Finspanga län domsaga	Norrköping
32. Folkungsbygdens domsaga	Mjölby
33. Hammarkinds, Stegeborgs och	Söderköping
34. Skarvinds domsaga	
35. Kinnefjärdings, Kinne och Kallands domsaga	Linköping
36. Linköpings domsaga	Linköping
37. Mellersta Värmdö domsaga	Vaxjö
38. Njudungs domsaga 2	Vetlanda
39. Norra och Södra Veddö domsaga	Eksjö
40. Öskarshamn's domsaga	Öskarshamn
41. Skarabygdens domsaga	Skara
42. Skövde domsaga	Skövde
43. Sunnerbo domsaga	Ljungby
44. More och Ölands domsaga	Kalmar
45. Tveta, Vista och Mo domsaga	Jönköping
46. Badsbo domsaga	Mariefred
47. Vårtofta och Frökind's domsaga	Falköping
48. Västra Värmdö domsaga	Alvesta
49. Västerviks domsaga	Västervik
50. Åre Viste, Barne och Laske domsaga	Vara
51. Östbo och Västbo domsaga	Värnamo
52. Östra Värmdö domsaga	Vaxjö
53. Bräcke och Karlshamn's domsaga	Karlshamn
54. Frösta och Eslövs domsaga	Eslöv
55. Ingelstads och Järrestads domsaga	Simrishamn
56. Kristianstads domsaga	Kristianstad
57. Lister och Solvesborg's domsaga	Sölvesborg
58. Luggude domsaga	Hälsingborg
59. Norra Åsbo domsaga	Klippan
60. Ölle och Skytt's domsaga	Malmö

## न्यायालय का नाम

## न्यायालय के स्थान का नाम

61.	Landskrona domsaga	Landskrona
62.	Sodra Asbo och Bjare domsaga	Angelholm
63.	Torna och Bara domsaga	Lund
64.	Vastra Goinge domsaga	Hassleholm
65.	Ystads domsaga	Ystad
66.	Ostra och Medelsta domsaga	Ronneby
67.	Ask ms och Molndals domsaga	Goteborg
68.	Boras domsaga	Boras
69.	Flundre, Vane och Bjarke domsaga	Trollhattan
70.	Fryksdals domsaga	Sunne
71.	Hallands mellersta domsaga	Falkenberg
72.	Hallands norra domsaga	Kungsbacka
73.	Hollands sodra domsaga	Halmstad
74.	Hisinge, Savedals och Kungalvs domsaga	Goteborg
75.	Josse domsaga	Arvika
76.	Kinds och Redvags domsaga	Ulricehamn
77.	Marks domsaga	Skene
78.	Mellansvsslets domsaga	Kerlstad
79.	Vaneraborgs domsaga	Vanersborg
80.	Nordmarka domsaga	Arjang
81.	Norrvikens domsaga	Stromstad
82.	Orusts, Tjorns och Inlands domsaga	Stenungsund
83.	Sunnervikens domsaga	Uddevalla
84.	Sodersyslets domsaga	Saffte
85.	Tossho och Vedbo domsaga	Amal
86.	Vattle, Ale och Kullings domsaga	Alingsas
87.	Alvdals och Nyeds domsaga	Karlstad
88.	Ostersyslets domsaga	Kristinehamn
89.	Bollnas domsaga	Bollnas
90.	Harjedalens domsaga	Sveg
91.	Jamtlands norra domsaga	Ostersund
92.	Jamtlands vastra domsaga	Ostersund
93.	Jamatlands ostra domsaga	Ostersund
94.	Medelpads domsaga	Sundsvall
95.	Norra Halsinglands domsaga	Hudiksvall
96.	Sydostra Halsinglands domsaga	Soderhamn
97.	Vastra Halsinglands domsaga	Ljusdal
98.	Solleftea domsaga	Solleftea
99.	Angermanlands norra domsaga	Ornskoldsvik
100.	Angermanlands sodra domsaga	Harsonasnd
101.	Gallivare domsaga	Gallivare
102.	Kalix domsaga	Kalix
103.	Bodens domsaga	Boden
104.	Pitea domsaga	Pitea
105.	Tornea domsaga	Haparanda
106.	Skelleftea domsaga	Skelleftea
107.	Vasterbottens mellestra domsaga	Umea
108.	Vasterbottens vastra domsaga	Lycksele
109.	Vasterbottens sodra domsaga	Umea
110.	Radhusratten i Eskilstuna	Eskilstuna
111.	Radhusratten i Gavle	Gavle
112.	Radhusratten i Stockholm	Stockholm
113.	Radhusratten i Sodertalje	Sodertalje
114.	Radhusratten i Uppsala	Uppsala
115.	Radhusratten i Vasteras	Vasteras
116.	Radhusratten i Orebro	Orebro
117.	Radhusratten i Jonkoping	Jonkoping
118.	Radhusratten i Kalmar	Kalmar
119.	Radhusratten i Linkoping	Linkoping
120.	Radhusratten i Motala	Motala
121.	Radhusratten i Norrkoping	Norrkoping
122.	Radhusratten i Vaxjo	Vaxjo
123.	Radhusratten i Boras	Boras
124.	Radhusratten i Goteborg	Goteborg

	Name of Court	Name of place where situated
125.	Radhusratten i Halmstad . . . . .	Halmstad
126.	Radhusratten i Karlstad . . . . .	Karlstad
127.	Radhusratten i Uddevalla . . . . .	Uddevalla
128.	Radhusratten i Varberg . . . . .	Varberg
129.	Radhusratten i Ostersund . . . . .	Ostersund
130.	Radhusratten i Halsingborg . . . . .	Halsingborg
131.	Radhusratten i Karlskrona . . . . .	Karlskrona
132.	Radhusratten i Lund . . . . .	Lund
133.	Radhusratten i Sundsvall . . . . .	Sundsvall
134.	Radhusratten i Malmo . . . . .	Malmo
135.	Radhusratten i Umea . . . . .	Umea
136.	Radhusratten i Lulea . . . . .	Lulea

2. केन्द्रीय सरकार यह भी निदेश देती है कि ऐसे आयोग पत्र, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली को भेजे जायेंगे ताकि उन्हें सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित किया जा सके।

-----न्यायालय में  
भारत से बाहर गवाहों की पूछ-ताछ के लिए आयोग पत्र

सेवा में

द्वारा विदेश मंत्रालय,  
भारत सरकार, नई दिल्ली

जबकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि-----

-----न्यायालय में मुकदमा संख्या-----

-----बनाम-----

में

न्यायहित की दृष्टि से श्री-----

का साक्ष्य लिया जाय और जबकि यह गवाह आपके क्षेत्राधिकार में रह रहा है, तथा उसकी उपस्थिति अनुचित विलम्ब, व्यय और श्रमविधा के बिना प्राप्त नहीं हो सकती, मैं-----

सादर निवेदन एवं अनुरोध करता हू कि पूर्वोक्त कारणों से, तथा उक्त न्यायालय की सहायतार्थ, आप उक्त गवाह को ऐसे समय तथा स्थान पर जिसे आप निर्धारित करें, आह्वान करने की कृपा करेंगे तथा उस गवाह की इस आयोग पत्र के साथ संलग्न प्रश्न माला के अनुसार पूछ-ताछ (मीखिक) की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे।

उक्त गवाह की पृच्छा, प्रतिपृच्छा, या पुनः पृच्छा (जैसी भी स्थिति हो) करने के लिए इस बाद से सम्बन्धित कोई भी पक्ष आपके समक्ष अपने वकील, अथवा एजेंट द्वारा या स्वयं, यदि हिरासन में न हो, उपस्थित हो सकता है। सादर मेरा यह भी निवेदन है कि आप उक्त गवाह के उत्तरों को लिखित रूप देने की कृपा करेंगे तथा इस पूछ-ताछ के दौरान प्रस्तुत किये गये सभी पुस्तको, पत्रों, कागजात एवं दस्तावेजों पर उचित रूप से पहिचान चिन्ह अंकित कराने की कृपा करेंगे, तथा इस पूछ-ताछ को अपने कार्यालय की (मुहर यदि कोई हो) तथा अपने हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित करने तथा उसे इस आयोग पत्र के साथ विदेश मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा मुझे भेजने की कृपा भी करेंगे।

मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुहर से अंकित आज-----

तारीख----- 19-----को जारी किया गया।

न्यायाधीश

जिला मजिस्ट्रेट/प्रिसिडेन्सी मजिस्ट्रेट

[संख्या 5/1/70 ज्युडिशियल-1]

**S.O. 2549.**—In pursuance of clause (b) of sub-section (2) of section 508-A of the Code of Criminal Procedure, 1898 (5 of 1898), the Central Government hereby specifies the following courts exercising jurisdiction in Sweden and having authority under the law in force in that country to issue Commissions for the examination of witnesses in relation to Criminal matters, as the Courts by which Commissions for the examination of witnesses residing in India may be issued, namely:—

Name of Court	Name of place where situated
1. Falu domsaga	Falun
2. Gotlands domsaga	Visby
3. Gästriklands västra domsaga	Storvik
4. Gästriklands östra domsaga	Gävle
5. Hedemora domsaga	Hedemora
6. Kerlskoga domsaga	Karlskoga
7. Lindes och Nora domsaga	Lindesberg
8. Livgedingets domsaga	Eskilstuna
9. Mellersta Roslags domsaga	Norrälje
10. Nedansiljans domsaga	Leksand
11. Norra Roslags domsaga	Osthammar
12. Nyköpings domsaga	Nyköping
13. Nas Och Malungs domsaga	Malung
14. Oppunda och Villattinge domsaga	Katrineholm
15. Övansiljans domsaga	More
16. Sollentuna och Färentuna domsaga	Solna
17. Solna domsaga	Solna
18. Stockholms län västra domsaga	Stockholm
19. Svartlösa domsaga	Huddinge
20. Södertörns domsaga	Stockholm
21. Södra Roslags domsaga	Stockholm
22. Uppsala län norra domsaga	Uppsala
23. Uppsala län södra domsaga	Uppsala
24. Västbergslags domsaga	Ludvika
25. Västernärkes domsaga	Orebro
26. Västmanlands mellersta domsaga	Vasteras
27. Västmanlands västra domsaga	Köping
28. Västmanlands östra domsaga	Sala
29. Östernärkes domsaga	Orebro
30. Aska, Dals och Böbers domsaga	Motala
31. Bråbygdens och Finspanga län domsaga	Norrköping
32. Folkungsbygdens domsaga	Mjölby
33. Hammarkinds, Stegeborgs och	
34. Skarkinds domsaga	Söderköping
35. Kinnefjärdens, Kinne och Kallands domsaga	Linköping
36. Linköpings domsaga	Linköping
37. Mellersta Värmds domsaga	Vaxjö
38. Njudungs domsaga	Vetlanda
39. Norra och Södra Veddö domsaga	Eksjö
40. Oskarshamns domsaga	Oskarshamn
41. Skarabygdens domsaga	Skara
42. Skövde domsaga	Skövde
43. Sunnerbo domsaga	Ljungby
44. More och Ölands domsaga	Kalmar
45. Tveta, Vista och Mo domsaga	Jonköping
46. Vadsbo domsaga	Mariestad
47. Vartofta och Frökinds domsaga	Falköping
48. Västra Värmds domsaga	Alvesta
49. Västerviks domsaga	Västervik
50. Åse, Viste, Barne och Lasse domsaga	Vara
51. Östbo och Västbo domsaga	Värnamo
52. Östra Värmds domsaga	Vaxjö
53. Bräkne och Karlshamns domsaga	Karlshamn
54. Frosta och Eslovs domsaga	Eslov
55. Ingelstads och Järrestads domsaga	Simrishamn
56. Kristianstads domsaga	Kristianstad
57. Listers och Solvesborgs domsaga	Sövesborg
58. Luggude domsaga	Hälsingborg

Name of Court	Name of place where situated
59. Norra Asbo domsaga	Klippan
60. Oxie och Skytts domsaga	Malmö
61. Landskrona domsaga	Landskrona
62. Södra Asbo och Bjäre domsaga	Ängelholm
63. Torna och Bara domsaga	Lund
64. Västra Göinge domsaga	Hässleholm
65. Ystads domsaga	Ystad
66. Östra och Medelsta domsaga	Ronneby
67. Askims och Mölndals domsaga	Goteborg
68. Borås domsaga	Borås
69. Flundre, Vane och Bjarke domsaga	Trollhattan
70. Fryksdals domsaga	Sunne
71. Hallands mellersta domsaga	Falkenberg
72. Hallands norra domsaga	Kungsbacka
73. Hallands södra domsaga	Halmstad
74. Hisinge, Sövedals och Kungälv's domsaga	Goteborg
75. Josse domsaga	Arvika
76. Kinds och Redvägs domsaga	Ulricehamn
77. Marks domsaga	Skene
78. Mellansysslets domsaga	Karlstad
79. Värnersborgs domsaga	Värnersborg
80. Nordmarks domsaga	Ärjäng
81. Norrvikens domsaga	Strömstad
82. Orusts, Tjörns och Inlands domsaga	Stenungsund
83. Sunnervikens domsaga	Uddevalla
84. Södersysslets domsaga	Säffle
85. Tossbo och Vedbo domsaga	Ämål
86. Vattle, Ale och Kullings domsaga	Älvsås
87. Älvdals och Nyeds domsaga	Karlstad
88. Östersysslets domsaga	Kristinehamn
89. Bollnäs domsaga	Bollnäs
90. Härjedalens domsaga	Sveg
91. Jämtlands norra domsaga	Östersund
92. Jämtlands Västra domsaga	Östersund
93. Jämtlands östra domsaga	Östersund
94. Medelpads domsaga	Sundsvall
95. Norra Hälsinglands domsaga	Hudiksvall
96. Sydöstra Hälsinglands domsaga	Söderhamn
97. Västra Hälsinglands domsaga	Ljusdal
98. Sollefteå domsaga	Sollefteå
99. Ångermanlands norra domsaga	Örnsköldsvik
100. Ångermanlands södra domsaga	Härnösand
101. Gällivare domsaga	Gällivare
102. Kalix domsaga	Kalix
103. Bodens domsaga	Boden
104. Piteå domsaga	Piteå
105. Torneå domsaga	Haparanda
106. Skellefteå domsaga	Skellefteå
107. Västerbottens mellersta domsaga	Umeå
108. Västerbottens västra domsaga	Lycksele
109. Västerbottens södra domsaga	Umeå
110. Rådhusrätten i Eskilstuna	Eskilstuna
111. Rådhusrätten i Gävle	Gävle
112. Rådhusrätten i Stockholm	Stockholm
113. Rådhusrätten i Södertälje	Södertälje
114. Rådhusrätten i Uppsala	Uppsala
115. Rådhusrätten i Västerås	Västerås
116. Rådhusrätten i Örebro	Örebro
117. Rådhusrätten i Jönköping	Jönköping
118. Rådhusrätten i Kalmar	Kalmar
119. Rådhusrätten i Linköping	Linköping
120. Rådhusrätten i Motala	Motala
121. Rådhusrätten i Norrköping	Norrköping
122. Rådhusrätten i Växjö	Växjö
123. Rådhusrätten i Borås	Borås
124. Rådhusrätten i Goteborg	Goteborg

I

2

125.	Radhusratten i Halmstad . . . . .	Halmstad
126.	Radhusratten i Karlstad . . . . .	Karlstad
127.	Radhusratten i Uddevalla . . . . .	Uddevalla
128.	Radhusratten i Varberg . . . . .	Varberg
129.	Radhusratten i Ostersund . . . . .	Ostersund
130.	Radhusratten i Halsingborg . . . . .	Halsingborg
131.	Radhusratten i Karlskrona . . . . .	Karlskrona
132.	Radhusratten i Lund . . . . .	Lund
133.	Radhusratten i Sundsvall . . . . .	Sundsvall
134.	Radhusratten i Malmo . . . . .	Malmo
135.	Radhusratten i Umea . . . . .	Umea
136.	Radhusratten i Lulea . . . . .	Lulea

[No. F. 5/1/70/-Judl. 1]

M. N. WALWEKAR, Dy. Secy.

सं० आ० 2549.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1890 (1898 का 5) की धारा 508—ए की उपधारा (2) के खण्ड (बी) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, स्वीडन सरकार के क्षेत्राधिकार में कार्यरत तथा उस राज्य में लागू कानून के अधीन दण्डनीय मामलों में गवाहों से पूछताछ हेतु आयोग-नपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत निम्नलिखित न्यायालयों को एतद्वारा ऐसे न्यायालयों के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिनके द्वारा भारत में रह रहे गवाहों की पूछताछ हेतु आयोग-नपत्र जारी किये जा सकते हैं, अर्थात् :—

न्यायालय का नाम

न्यायालय के स्थान का नाम

1	2
1. Falu domsaga . . . . .	Falun
2. Gotlands domsaga . . . . .	Visby
3. Gastriklands Vstra domsaga . . . . .	Storvik
4. Gastriklands ostra domsaga . . . . .	Gevale
5. Hedemora domsaga . . . . .	Hedemora
6. Karlskoga domsaga . . . . .	Karlskoga
7. Lindes och Nora domsaga . . . . .	Lindesberg
8. Livgedingets domsaga . . . . .	Eskilstuna
9. Mellersta Roslags domsaga . . . . .	Norrtalje
10. Nedansiljans domsaga . . . . .	Leksand
11. Norra Roslags domsaga . . . . .	Osthammar
12. Nykopings domsaga . . . . .	Nykoping
13. Nas Och Malungs domsaga . . . . .	Malung
14. Oppunda och Villattinge domsaga . . . . .	Katrineholm
15. Ovasiljans domsaga . . . . .	Mora
16. Sollentuna och Farentuna domsaga . . . . .	Solna
17. Solna domsaga . . . . .	Solna
18. Stockholms lns vstra domsaga . . . . .	Stockholm
19. Svalofsa domsaga . . . . .	Huddinge
20. Sodertorns domsaga . . . . .	Stockholm
21. Sodra Roslags domsaga . . . . .	Stockholm
22. Uppsala lns norra domsaga . . . . .	Uppsala
23. Uppsala lns soda domsaga . . . . .	Uppsala
24. Vasterbergslags domsaga . . . . .	Ludvika
25. Vastermarkes domsaga . . . . .	Orebro
26. Vastmanlands mellersta domsaga . . . . .	Vasteras
27. Vastmanlands vstra domsaga . . . . .	Koping
28. Vastmanlands ostra domsaga . . . . .	Sala
29. Ostermarkes domsaga . . . . .	Orebro
30. Aska, Dala och Bobergs domsaga . . . . .	Motala
31. Brabydens och Finspanga lns domsaga . . . . .	Norrkoping

32. Folkungsbygdens domsaga	Mjölby
33. Hammarkinds, Stegeborgs och	
34. Skarkinds domsaga	Söderköping
35. Kinnefjärdings, Kinne och Kallands domsaga	Linköping
36. Linköpings domsaga	Linköping
37. Mellersta Varends domsaga	Vaxjö
38. Njudungs domsaga	Vetlanda
39. Norra och Södra Vedbo domsaga	Eksjö
40. Oskarshamns domsaga	Oskarshamn
41. Skarabygdens domsaga	Skara
42. Skövde domsaga	Skövde
43. Sunnerbo domsaga	Ljungby
44. More och Olands domsaga	Kalmar
45. Tveta, Vista och Mo domsaga	Jonköping
46. Vadsbo domsaga	Mariestad
47. Vartofta och Frökinds domsaga	Falköping
48. Västra Varends domsaga	Alvesta
49. Västerviks domsaga	Västervik
50. Åse, Viste, Barne och Laske domsaga	Vara
51. Östbo och Västbo domsaga	Värnamo
52. Östra Varends domsaga	Vaxjö
53. Bräkne och Karlshamns domsaga	Karlshamn
54. Frösta och Eslovs domsaga	Eslova
55. Ingelstads och Järrestads domsaga	Simrishamn
56. Kristianstads domsaga	Kristianstad
57. Listers och Solvesborgs domsaga	Sövesborg
58. Luggude domsaga	Halsingborg
59. Norra Åsbo domsaga	Klippan
60. Oxie och Skytte domsaga	Malmö
61. Landskrona domsaga	Landskrona
62. Södra Åsbo och Bjäre domsaga	Ängelholm
63. Torpa och Bara domsaga	Lund
64. Västra Göinge domsaga	Hässleholm
65. Ystads domsaga	Ystad
66. Östra och Medelsta domsaga	Ronneby
67. Askims och Mölndals domsaga	Göteborg
68. Borås domsaga	Borås
69. Flundre, Vane och Bjarke domsaga	Trollhättan
70. Fryksdals domsaga	Sunne
71. Hallands mellersta domsaga	Falkenberg
72. Hallands norra domsaga	Kungsbacka
73. Hallands södra domsaga	Halmstad
74. Hisinge, Sövedals och Kungälv's domsaga	Göteborg
75. Josse domsaga	Arvika
76. Kinds och Redvags domsaga	Ulricehamn
77. Marks domsaga	Skene
78. Mellansysslets domsaga	Karlstad
79. Vänersborgs domsaga	Vänersborg
80. Nordmarks domsaga	Ärjäng
81. Norrvikens domsaga	Strömstad
82. Orust, Tjörns och Inlands domsaga	Stenungsund
83. Sunnervikens domsaga	Uddevalla
84. Södersysslets domsaga	Säffle
85. Tossbo och Vedbo domsaga	Ämål
86. Vättle, Åle och Kullings domsaga	Älvsås
87. Älvdals och Nyeds domsaga	Karlstad
88. Östersyssellets domsaga	Kristinehamn
89. Bollnas domsaga	Bollnas
90. Härjedalens domsaga	Sveg
91. Jämtlands norra domsaga	Ostersund
92. Jämtlands västra domsaga	Ostersund
93. Jämtlands östra domsaga	Ostersund
94. Medelpads domsaga	Sundsvall

1

2

95.	Norra Halsinglands domsaga . . . . .	Hudiksvall
96.	Sydostra Halsinglands domsaga . . . . .	Soderhamn
97.	Vastra Halsinglands domsaga . . . . .	Ljusdal
98.	Solleftea domsaga . . . . .	Solleftea
99.	Angermanlands norra domsaga . . . . .	Ornskoldsvik
100.	Angermanlands sodra domsaga . . . . .	Harnosand
101.	Gallivare domsaga . . . . .	Gallivare
102.	Kalix domsaga . . . . .	Kalix
103.	Bodens domsaga . . . . .	Boden
104.	Pitea domsaga . . . . .	Pitea
105.	Tornea domsaga . . . . .	Haparanda
106.	Skelleftea domsaga . . . . .	Skelleftea
107.	Vasterbottens m-llersta domsaga . . . . .	Umea
108.	Vasterbottens va:tra domsaga . . . . .	Lycksele
109.	Vasterbottens sodra domsaga . . . . .	Umea
110.	Radhusratten i Eskilstuna . . . . .	Eskilstuna
111.	Radhusratten i Gavle . . . . .	Gavle
112.	Radhusratten i Stockholm . . . . .	Stockholm
113.	Radhusratten i Sodertalje . . . . .	Sodertalje
114.	Radhusratten i Uppsala . . . . .	Uppsala
115.	Radhusratten i Vasteras . . . . .	Vasteras
116.	Radhusratten i Orebro . . . . .	Orebro
117.	Radhusratten i Jonkoping . . . . .	Jonkoping
118.	Radhusratten i Kalmar . . . . .	Kalmar
119.	Radhusratten i Linkoping . . . . .	Linkoping
120.	Radhusratten i Motala . . . . .	Motala
121.	Radhusratten i Norrkoping . . . . .	Norrkoping
122.	Radhusratten i Vaxjo . . . . .	Vaxjo
123.	Radhusratten i Boras . . . . .	Boras
124.	Radhusratten i Goteborg . . . . .	Goteborg
125.	Radhusratten i Halmstad . . . . .	Halmstad
126.	Radhusratten i Karlstad . . . . .	Karlstad
127.	Radhusratten i Uddevalla . . . . .	Uddevalla
128.	Radhusratten i Varberg . . . . .	Varberg
129.	Radhusratten i Ostersund . . . . .	Ostersund
130.	Radhusratten i Halsingborg . . . . .	Halsingborg
131.	Radhusratten i Karlskrona . . . . .	Karlskrona
132.	Radhusratten i Lund . . . . .	Lund
133.	Radhusratten i Sundsvall . . . . .	Sundsvall
134.	Radhusratten i Malmo . . . . .	Malmo
135.	Radhusratten i Umea . . . . .	Umea
136.	Radhusratten i Lulea . . . . .	Lulea

[संख्या 5/1/70 ज्यडिशियल-1]

एम० एन० बालवेकर, उप सचिव ।

New Delhi, the 25th July 1970

S.O. 2550.—In partial modification of this Ministry's Notification No. 1/2/70-DH(S), dated the 29th May, 1970, the President is pleased to direct that para 2 thereof may be substituted by the following:—

"2. Any recruitment rules, including any rule relating to probation, confirmation, seniority and promotion, made in pursuance of this direction shall be made in consultation with the Delhi High Court."

[No. F. 1/2/70-DH(S).]

R. N. CHOPRA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 1970

एस० नो० 2550.—इस मंत्रालय की अधिसूचना सं० 1/2/70-डी० एच० (एस०) दिनांक 29 मई, 1970 के आंशिक आशोधन में, राष्ट्रपति महर्ष यह निदेश देते हैं कि उस अधिसूचना के पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाये।

2. "परिवीक्षा, पुष्टिकरण, वरीयता और पदोन्नति सम्बन्धी किसी भी नियम समेत, जो भी भर्ती नियम इस निर्देशन के अनुसरण में बनाये जायेंगे, वे दिल्ली उच्च न्यायालय के विचार विमर्श से बनाये जायेंगे।"

[संख्या एफ० 1/2/70-डी० एच० (एस०)]

र० ना० चोपड़ा उप सचिव, ।

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Banking)

New Delhi, the 18th July 1970

**S.O. 2551.**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of Section 7 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) the Central Government, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby constitutes the first Board of Directors of Central Bank of India and hereby appoints the undermentioned persons as the members of the said Board of Directors, namely:—

1. Shri N. Ramanand Rao, Custodian, Central Bank of India, Bombay.
2. Shri V. M. Dandekar, Gokhale Institute of Politics and Economics, Poona.
3. Shri A. H. Elias, Principal, State Bank of India, Staff Training College, Hyderabad.
4. Shri Brijraj Narain, Morar, Gwallor.
5. Shri G. B. Newalkar, Chairman, Maharashtra Small Scale Industries Development Corporation Ltd., Bombay.
6. Shri M. Narasimham, Secretary, Reserve Bank of India, Bombay.
7. Shri S. S. Shiralkar, Additional Secretary, Department of Banking, Ministry of Finance, New Delhi.

Shri N. Ramanand Rao, Custodian, shall preside over the meetings of the first Board of Directors.

[No. F.4(50)-BC/70.]

M. G. BALASUBRAMANIAN, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(बैंकिंग विभाग)

नयी दिल्ली, 18 जुलाई 1970

एस० नो० 2551.—बैंकिंग समवाय (उपक्रम अधिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का पांचवां) की धारा 7 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके एतद्वारा सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया -

का प्रथम निदेशक बोर्ड गठित करनी है और एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को उक्त निदेशक बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है, अर्थात्:—

1. श्री एन० रामानन्द राव, अभिरक्षक, सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया, बम्बई ।
2. श्री बी० एम० दाडेकर, गोखले, इंस्टीट्यूट आफ पालिटिक्स एण्ड इकॉनामिक्स, पुना ।
3. श्री ए० एच० इलियास, प्रिंसिपल, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, स्टाफ ट्रेनिंग कालेज, हैदराबाद ।
4. श्री बृजराज नागयण, मोरार, ग्वालियर ।
5. श्री जी० बी० नेवलकर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड, बम्बई
6. श्री एम० नरसिंहम, सचिव, भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई ।
7. श्री एम० एस० शिरालकर, अतिरिक्त सचिव, बैंकिंग विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली

श्री एन० रामानन्द राव अभिरक्षक,  
प्रथम निदेशक बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे ।

[सं० एफ० 4 (50)-बी०सी०/70]

एम० जी० बालमुब्रहमण्यम  
संयुक्त सचिव, ।

#### (Department of Banking)

New Delhi, the 18th July 1970

**S.O. 2552.**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of Section 7 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) the Central Government, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby constitutes the first Board of Directors of Bank of India and hereby appoints the undermentioned persons as the members of the said Board of Directors, namely:—

1. Shri T. D. Kansara, Custodian, Bank of India, Bombay.
2. Shri C. D. Khanna, Chairman, Industrial Finance Corporation, New Delhi.
3. Shri Manohar Singh Mehta, 208, Jawahar Marg, Indore.
4. Dr. Dharm Narain, Chairman, Agricultural Prices Commission, Krishi Bhavan, New Delhi.
5. Shri G. D. Parikh, Ganesh Bhavan, Telang Road, Mathunga, Bombay
6. Shri A. Raman, Director, Credit Planning Cell, Reserve Bank of India, Bombay.
7. Shri P. D. Kasbekar, Joint Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, New Delhi.

Shri T. D. Kansara, Custodian, shall preside over the meetings of the first Board of Directors.

[No. F.4(51)-BC/70.]

(बैंकिंग विभाग)

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 1970

एस०ओ० 2552.—बैंकिंग समवाय (उपक्रम अभिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का पांचवां) की धारा 7 की उपधारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके एतद्द्वारा बैंक आफ इण्डिया का प्रथम

निदेशक बोर्ड गठित करती है और एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को उक्त निदेशक बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है, अर्थात्:—

1. श्री टी० डी० कंसारा, अभिरक्षक, बैंक आफ इण्डिया, बम्बई ।
2. श्री सी० डी० खन्ना, अध्यक्ष, औद्योगिक वित्त निगम, नई दिल्ली ।
3. श्री मनोहर सिंह मेहता, 208 जवाहर मार्ग, इन्दौर ।
4. डा० धर्म नारायण, अध्यक्ष, कृषि मूल्य आयोग, कृषि भवन, नई दिल्ली ।
5. श्री जी० डी० पारिख, गणेश भवन, तैलांग रोड, मांदुगा, बम्बई ।
6. श्री ए० रामन, निदेशक, ऋण आयोजना कक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई ।
7. श्री पी० डी० कम कर, संयुक्त सचिव, अर्थ विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली ।

श्री टी० डी० कंसारा

प्रथम निदेशक बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे ।

[सं० एफ० 4 (51)-बी०सी०/70]

**S.O. 2553.**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of Section 7 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Central Government, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby constitutes the first Board of Directors of Indian Overseas Bank and hereby appoints the undermentioned persons as the members of the said Board of Directors, namely:—

1. Shri R. N. Chettur, Custodian, Indian Overseas Bank, Madras
2. Shri Joseph Chackola, Chackola Silk House, Broadway, Cochin.
3. Shri N. B. Prasad, Banjara Hills, Hyderabad.
4. Shri M. K. Raju, Director and General Manager, Indian Pistons Ltd., Madras.
5. Kum. M. Tyagarajan, Dy. Director, Credit Planning Cell, Reserve Bank of India, Bombay-1.
6. Shri M. G. Balasubramanian, Joint Secretary, Department of Banking, Ministry of Finance, New Delhi.

Shri R. N. Chettur, Custodian, shall preside over the meetings of the first Board of Directors.

[No. F.4(52)-BC-70.]

**एस० ओ० 2553.**—बैंकिंग समवाय (उपक्रम अभिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का पांचवां) की धारा 7 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके एतद्द्वारा इण्डियन ओवरसीज बैंक का प्रथम निदेशक बोर्ड गठित करती है और एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को उक्त निदेशक बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है, अर्थात्:—

1. श्री आर०एन० चेतूर, अभिरक्षक, इण्डियन ओवरसीज बैंक, मद्रास ।
2. श्री जोसेफ चकोला, चकोला सिल्क हाउस, ब्राडवे, कोचीन ।
3. श्री एन० बी० प्रसाद, बंजारा हिल्स, हैदराबाद ।
4. श्री एम० के० राजू, निदेशक तथा महाप्रबन्धक, इण्डियन पिस्टन्स लिमिटेड, मद्रास ।
5. कुमारी एम० त्यागराजन, उप-निदेशक, ऋण आयोजना कक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई ।
6. श्री एम०जी० बालमुब्रह्मण्यन, संयुक्त सचिव, बैंकिंग विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली ।

श्री० आर० एन० चेतूर

प्रथम निदेशक बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे ।

[सं० एफ० 4 (52)-बी०सी०/70]

**S.O. 2554.**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of Section 7 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) the Central Government, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby constitutes the first Board of Directors of Indian Bank and hereby appoints the undermentioned persons as the members of the said Board of Directors, namely:—

1. Shri G. Lakshminarayanan, Custodian, Indian Bank, Madras.
2. Shri M. A. Ramruddin, Malleable Tube Products of India, Marudharoad, Palghat.
3. Smt P. Krishnaswamy, 15, Marshalls Road, Madras.
4. Dr. B. Natarajan, 42-A/1, Harrington Road, Chetput, Madras.
5. Shri K. S. Chakrapani, Joint Chief Officer, Credit Planning Cell, Reserve Bank of India, Central Office Bombay.
6. Shri M. G. Belasubramanian, Joint Secretary, Ministry of Finance, Department of Banking, New Delhi.

Shri G. Lakshminarayanan, Custodian, shall preside over the meetings of the first Board of Directors.

[No. F.4(53)-BC/70.]

**एस० प्री० 2554.**—बैंकिंग समवाय (उपक्रम अधिग्रहण और अन्तर्गण) अधिनियम, 1970 (197 का पांचवां) की धारा 7 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके एतद्वारा इण्डियन बैंक का प्रथम निदेशक बोर्ड गठित करती है और एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को उक्त निदेशक बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है, अर्थात्:—

1. श्री जी० लक्ष्मीनारायणन्, अभिरक्षक, इण्डियन बैंक, मद्रास ।
  2. श्री एम०ए० कमरुद्दीन, मैलियुबुल ट्यूब प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया, मारुदारोड, पालघाट ।
  3. श्री पी० कृष्णास्वामी, 15, मार्शल्स रोड, मद्रास ।
  4. डा० बी० नटराजन, 42-ए/1, हैरिंगटन रोड, चेटपुत, मद्रास ।
  5. श्री के० एस० चक्रपाणि, संयुक्त मुख्य अधिकारी, ऋण आयोजना कक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, बम्बई ।
  6. श्री एम०जी० बाल सुब्रह्मण्यन्, संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, बैंकिंग विभाग, नई दिल्ली ।
- श्री जी० लक्ष्मीनारायणन्, अभिरक्षक, प्रथम निदेशक बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे ।

[सं० एफ० 4(53)—बी०सी०/70]

**S.O. 2555.**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of Section 7 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Central Government, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby constitutes the first Board of Directors of Allahabad Bank and hereby appoints the undermentioned persons as the members of the said Board of Directors, namely:—

1. Shri B. K. Mookerjee, Custodian, Allahabad Bank, Calcutta.
2. Shri M. R. Roy, Managing Director, West Bengal Financial Corporation, Calcutta.
3. Shri S. N. Srivastava, 211, Patliputra Colony, Patna.
4. Dr. M. A. Zaheer, Faculty of Commerce, Banaras Hindu University, Varanasi.
5. Shri T. Tiwari, Manager, Industrial Development Bank of India, Calcutta.
6. Shri N. Sethuraman, Deputy Secretary, Department of Banking, Ministry of Finance, New Delhi.

Shri B. K. Mookerjee, Custodian, shall preside over the meetings of the first Board of Directors.

[No. F.4(54)-BC/70.]

एस० ओ० 2555—बैंकिंग समवाय (उपक्रम अभिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का पाचवा) की धारा 7 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके एतद्द्वारा इलाहाबाद बैंक का प्रथम निदेशक बोर्ड गठित करती है और एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को उक्त निदेशक बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है, अर्थात्—

1. श्री बी० के० मुकुर्जी, अभिरक्षक, इलाहाबाद बैंक, कलकत्ता ।
2. श्री एम० आर० राय, प्रबन्ध निदेशक, पश्चिम बंगाल वित्त निगम, कलकत्ता ।
3. श्री एस० एन० श्रीवास्तव, 211 पाटलिपुत्र कालोनी, पटना ।
4. डा० एम० ए० जहीर, वाणिज्य संकाय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वारणसी ।
5. श्री टी० तिवारी, प्रबन्धक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेण्ट बैंक आफ इण्डिया, कलकत्ता ।
6. श्री एन० संतुरामन, उप-सचिव, बैंकिंग विभाग वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली ।

श्री बी० के० मुकुर्जी, अभिरक्षक, प्रथम निदेशक बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

[सं० एफ० 4(54)—बी०सी०/70]

**S.O. 2556.**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of Section 7 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Central Government, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby constitutes the first Board of Directors of Dena Bank and hereby appoints the undermentioned persons as the members of the said Board of Directors, namely:—

1. Shri R. A. Gulmohamed, Custodian, Dena Bank, Bombay.
2. Shri M. P. Chitale, M/s. M. P. Chitale and Company, Bombay.
3. Shri Krishna Raj, Editor, Economic and Political Weekly, Bombay.
4. Shri Sooryakant Parikh, General Manager, Natson Manufacturing Company Limited, Ahmedabad.
5. Shri V. V. Divatia, Adviser, Department of Statistics, Reserve Bank of India, Bombay.
6. Shri S. M. Kelkar, Deputy Secretary, Department of Banking, Ministry of Finance, New Delhi.

Shri R. A. Gulmohamed, Custodian, shall preside over the meetings of the first Board of Directors.

[No. F.4(55)-BC/70.]

एस० ओ० 2556.—बैंकिंग समवाय (उपक्रम अभिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का पांचवा) की धारा 7 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके एतद्द्वारा देना बैंक का प्रथम निदेशक बोर्ड गठित करती है और एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को उक्त निदेशक बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है, अर्थात्—

1. श्री आर० ए० गुलमोहम्मद, अभिरक्षक, देना बैंक, बम्बई ।
2. श्री एम० पी० चितले, मेसर्स एम०पी० चितले एण्ड कम्पनी, बम्बई ।
3. श्री कृष्ण राज, सम्पादक, इकोनामिक एण्ड पालिटिकल वीकली, बम्बई ।
4. श्री सूर्यकान्त पारिख, जनरल मैनेजर, नटसन मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, अहमदाबाद ।
5. श्री बी० बी० दिवाटिया, सलाहकार, सांख्यिकी विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई ।

6. श्री एस०एम० केलकर, उप सचिव, बैंकिंग विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली ।

श्री आर०ए० गुलमोहम्मद, अभिरक्षक, प्रथम निदेशक बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे ।

[सं० एफ० 4(55)—बी०सी०/70]

**S.O. 2557.**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of Section 7 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Central Government, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby constitutes the first Board of Directors of Canara Bank and hereby appoints the undermentioned persons as the members of the said Board of Directors, namely:—

1. Shri K. P. J. Prabhu, Custodian, Canara Bank, Bangalore.
2. Dr. C. H. Hanumantha Rao, Institute of Economic Growth, Dehi.
3. Shri R. C. Keshavamurthy, Pattivrampatti, Distt. Madurai.
4. Shri K. S. R. Malliah, Brahmavar, Distt. South Kanara.
5. Shri K. N. R. Ramanujam, Chief Officer, Industrial Finance Department, Reserve Bank of India, Bombay.
6. Shri K. Ramamurthy, Joint Secretary, Department of Banking, Ministry of Finance, New Delhi.

Shri K. P. J. Prabhu, Custodian, shall preside over the meetings of the first Board of Directors.

[No. F.4(56)-BC/70.]

**एस०ओ० 2557.**—बैंकिंग समवाय (उपक्रम अभिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का पांचवां) की धारा 7 की उपधारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके एतद्द्वारा कनारा बैंक का प्रथम निदेशक बोर्ड गठित करती है और एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को उक्त निदेशक बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है, अर्थात्—

1. श्री के० पी० जे० प्रभु, अभिरक्षक, कनारा बैंक, बंगलूर ।
2. डा० सी०एच० हनुमन्तराव, इंस्टीच्यूट आफ इकोनामिक प्रोथ, दिल्ली ।
3. श्री आर० सी० केशवमूर्ति, पट्टीवीरमपट्टी, जिला मद्रै ।
4. श्री के० एस० आर० मल्लिया, ब्रह्मावर, जिला दक्षिण कनारा ।
5. श्री के० एन० आर० रामानुजम, मुख्य अधिकारी, औद्योगिक वित्त विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई ।
6. श्री के० राममूर्ति, संयुक्त सचिव, बैंकिंग विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली ।

श्री के०पी०जे० प्रभु, अभिरक्षक, प्रथम निदेशक बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे ।

[सं० एफ० 4(56)—बी०सी०/70]

**S.O. 2558.**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of Section 7 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Central Government, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby constitutes the first Board of Directors of Union Bank of India and hereby appoints the undermentioned persons as the members of the said Board of Directors, namely:—

1. Shri P. F. Gutta, Custodian, Union Bank of India, Bombay.
2. Shri K. H. Parikh, General Manager, Vibhuti Glass Factory, Ramnagar, Varanasi.
3. Shri P. K. Sadanandan, XL—Sea Foods, Cochin.

4. Shri H. M. Trivedi, 'Raj Mahal', Juhu, Bombay.

5. Shri D. P. Gupta, Manager, Industrial Development Bank of India, Bombay.

6. Shri F. K. Kaul, Joint Secretary, Deptt. of Expenditure, Ministry of Finance, New Delhi.

Shri P. F. Gutta, Custodian shall preside over the meetings of the first Board of Directors.

[No. F.4(57) BC/70.]

एस० नो० 2558—बैंकिंग समवाय (उपक्रम, अभिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का पाचवा) की धारा 7 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके एतद्द्वारा यूनियन बैंक आफ इण्डिया का प्रथम निदेशक बोर्ड गठित करती है और एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को निदेशक बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है, अर्थात्—

1. श्री पी० एफ० गुप्ता, अभिरक्षक, यूनियन बैंक आफ इण्डिया, बम्बई ।
  2. श्री के० एच० पारिख, जनरल मैनेजर, विभूति ग्लास फैक्टरी, रामनगर, वाराणसी ।
  3. श्री पी० के० सदानन्दन, XL-सी फूड्स, कोचीन ।
  4. श्री एच० एम० त्रिवेदी, "राजमहल", जुहू, बम्बई ।
  5. श्री बी० पी० गुप्ता, प्रबन्धक, इन्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट बैंक आफ इण्डिया, बम्बई ।
  6. श्री पी० के० कौल, सयुक्त सचिव, व्यय विभाग, वित्त मन्त्रालय, नई दिल्ली ।
- श्री पी० एफ० गुप्ता, अभिरक्षक, प्रथम निदेशक बोर्ड का बैठका की अध्यक्षता करेंगे ।

[स० एफ० 4 (57) बी० नो०/70]

S.O. 2559.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of Section 7 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Central Government, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby constitutes the first Board of Directors of United Commercial Bank and hereby appoints the undermentioned persons as the members of the said Board of Directors, namely:—

1. Shri R. B. Shah, Custodian, United Commercial Bank, Calcutta.
2. Dr. D. Banerjee, Director, National Rubber Manufacturers Ltd., Calcutta.
3. Dr. Upen Bordoloi, Department of Economics, Gauhati University, Jhalukbari, Gauhati.
4. Shri Raghunath Mohapatra, Kosaka Farm, vill. Balugaon, P.O. Nayagarh, Dist. Puri.
5. Shri G. P. Sinha, Department of Labour & Social Welfare, University of Patna, Patna.
6. Kumari N. K. Abbegaokar, Director, Economic Department, Reserve Bank of India, Bombay.
7. Dr. Ashok Mitra, Chief Economics Adviser, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, New Delhi.

Shri R. B. Shah, Custodian, shall preside over the meetings of the first Board of Directors.

[No. F. 4(58)-BC/70.]

एस० नो० 2559—बैंकिंग समवाय (उपक्रम, अभिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम 1970 (1970 का पाचवा) की धारा 7 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके एतद्द्वारा

यूनाइटेड कमर्शियल बैंक का प्रथम निदेशक बोर्ड गठित करती है और एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को उक्त निदेशक बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है, अर्थात्—

1. श्री आर० बी० शाह, अभिरक्षक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, कलकत्ता ।
  2. डा० डी० बनर्जी, डाइरेक्टर, नेशनल रबर, मैन्यूफैक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता ।
  3. डा० उपेन बोर्दोलोइ, अर्थशास्त्र विभाग, गोहाटी विश्वविद्यालय, बालुकबाड़ी, गोहाटी ।
  4. श्री रघुनाथ मोहापत्र, कोसक फार्म, ग्राम बालूगांव, डाकखाना नयागढ़, जिला पुरी ।
  5. श्री जी० पी० सिन्हा, श्रम तथा समाज कल्याण विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना ।
  6. कुमारी एन० के० अम्बेगावकर, निदेशक, आर्थिक विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई ।
  7. डा० अशोक मित्र, मुख्य आर्थिक सलाहकार, अर्थ विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली ।
- श्री आर० बी० शाह, अभिरक्षक, प्रथम निदेशक बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे ।

[सं० एफ० 4 (58)—बी०सी०/70]

**S.O. 2560.**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of Section 7 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Central Government, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby constitutes the first Board of Directors of Bank of Baroda and hereby appoints the undermentioned persons as the members of the said Board of Directors, namely:—

1. Shri M. G. Parikh, Custodian, Bank of Baroda, Bombay.
2. Shri H. N. Bhargava, Trackparts India Ltd., Spar Press Building, The Mall, Kanpur.
3. Shri Bhubanes Chaturvedi, Advocate, Kota.
4. Shri D. K. Desai, Professor, Management in Agriculture and Co operation, Indian Institute of Management, Ahmedabad.
5. Shri H. A. Mohite, Hanmantgaon, Distt. Ahmednagar.
6. Shri C. D. Datey, Chief Officer, Agricultural Credit Department, Reserve Bank of India, Bombay.
7. Shri M. K. Venkatachalam, Joint Secretary, Department of Banking, Ministry of Finance, New Delhi.

Shri M. G. Parikh, Custodian, shall preside over the meetings of the first Board of Directors.

[No. F.4(59)-BC/70.]

**एस० ओ० 2560.**—बैंकिंग समवाय (उपक्रम अभिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का पांचवां) की धारा 7 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके एतद्वारा बैंक आफ बड़ौदा का प्रथम निदेशक बोर्ड गठित करती है और एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को उक्त निदेशक बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है, अर्थात्—

1. श्री एम० जी० पारिख, अभिरक्षक, बैंक आफ बड़ौदा, बम्बई ।
  2. श्री एच० एन० भार्गव, ट्रैकपाट्स इण्डिया लिमिटेड, स्पर प्रेस बिल्डिंग, वि माल, कानपुर ।
  3. श्री भुवनेश चतुर्वेदी, एडवोकेट, कोटा ।
  4. श्री डी० के० देसाई, प्रोफेसर, कृषि तथा सहकारिता प्रबन्ध, भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद ।
  5. श्री एच० ए० मोहिते, हनुमंतगांव, जिला अहमदनगर ।
  6. डा० सी० डी० दाते, मुख्य अधिकारी, कृषि ऋण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई ।
  7. श्री एम० के० वैकटपालम्, संयुक्त सचिव, बैंकिंग विभाग, वित्त मंत्रालय, नयी दिल्ली ।
- श्री एम० जी० पारिख, अभिरक्षक, प्रथम निदेशक बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे ।

[सं० एफ० 4 (59)—बी०सी०/70]

**S.O. 2561**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of Section 7 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Central Government, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby constitutes the first Board of Directors of Punjab National Bank and hereby appoints the undermentioned persons as the members of the said Board of Directors, namely—

- 1 Shri S C Trikha Custodian, Punjab National Bank, New Delhi.
- 2 Shri Mohamad Abdullah, Asia Crafts, Kashanah, 5, Boulevard, Srinagar.
- 3 Dr A S Kahlon Dean, College of Basic Sciences and Humanities, Punjab Agricultural University, Ludhiana.
- 4 Shri V N Kak, Managing Director, State Hotels Corporation "Vasundhara" Jaipur
- 5 Shri T S Papola Patel Institute of Economic Research, Ahmedabad.
- 6 Shri V M Jakhade, Adviser Economic Department, Reserve Bank of India, Bombay
- 7 Shri A T. Bambawale, Joint Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, New Delhi.

Shri S C. Trikha, Custodian, shall preside over the meetings of the first Board of Directors

[No. F. 4(60)-BC/70]

**एस० एम० 2561**—बैंकिंग समवाय (उपक्रम अभिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का पाचवा) की धारा 7 की उपधारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके एतद्वारा पंजाब नेशनल बैंक का प्रथम निदेशक बोर्ड गठित करती है और एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों का उक्त निदेशक बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है, अर्थात्—

- 1 श्री एस० सी० त्रिखा, अभिरक्षक, पंजाब नेशनल बैंक, नयी दिल्ली ।
- 2 श्री मोहम्मद अब्दुल्ला, एशिया क्राफ्ट्स, काशनाह, 5, बालवार्ड, श्रीनगर ।
- 3 डा० ए०एस० कहलान, डीन, कालेज आफ बेसिक साइन्सज एण्ड हुयमैनिटीज, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना ।
- 4 श्री वी० एन० काक, मैनेजिंग डायरेक्टर, स्टेट होटल कारपोरेशन, "वसुन्धरा", जयपुर ।
5. श्री टी० एस० पापोला, पटेल इन्स्टीच्यूट आफ इकोनामिक रिसर्च, अहमदाबाद ।
- 6 श्री वी० एम० जाखडे, सलाहकार, आर्थिक विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई ।
7. श्री ए० टी० बम्बावाले, सयुक्त सचिव, अर्थ विभाग, वित्त मन्त्रालय, नयी दिल्ली ।

श्री एस०सी० त्रिखा, अभिरक्षक, प्रथम निदेशक बोर्ड की बैठको की अध्यक्षता करेंगे ।

[स० एफ० 4(60)—बी०सी०/70]

**S.O. 2562**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of Section 7 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Central Government, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby constitutes the first Board of Directors of United Bank of India, and hereby appoints the undermentioned persons as the members of the said Board of Directors, namely:—

1. Shri B K Dutt, Custodian, United Bank of India, Calcutta.
- 2 Shri K P. Barua, Managing Director, Assam State Financial Corporation, Shillong
- 3 Rev Joel Lakra, Ranchi.
- 4 Shri Subrata K Sen, Sen Raleigh Ltd, Calcutta.
- 5 Shri Ghulam Ghouse, Dy Chief Officer, Credit Planning Cell, Reserve Bank of India, Bombay.
- 6 Shri D N Ghosh Director, Ministry of Finance, Department of Banking, New Delhi.

Shri B K Dutt, Custodian, shall preside over the meetings of the first Board of Directors

[No. F. 4(61)-BC/70.]

एल० ओ० 2562—बैंकिंग समवाय (उपक्रम अभिरग्रहण, और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का पांचवां) की धारा 7 की उपधारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके एतद्वारा यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया का प्रथम निदेशक बोर्ड गठित करती है और एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को उक्त निदेशक बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है, अर्थात् :—

1. श्री बी० के० दत्त, अभिरक्षक, यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया, कलकत्ता ।
2. श्री के० पी० ब्रह्मा, मैनेजिंग डाइरेक्टर, असम राज्य वित्त निगम, शिलांग ।
3. रेवरेन्ड जोयल लाकरा, रांची ।
4. श्री सुब्रत के० सेन, सैन रैले लिमिटेड, कलकत्ता ।
5. श्री गुलाम गौस, उन्मुख्य अधिकारी, ऋण आयोजना कक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई ।
6. श्री डी० एन० घोष, निदेशक, वित्त मंत्रालय, बैंकिंग विभाग, नयी दिल्ली ।

[सं० एफ० 4 (61)-बी० सी०/7.]

S.O. 2563.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of Section 7 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Central Government, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby constitutes the first Board of Directors of Bank of Maharashtra and hereby appoints the undermentioned persons as the members of the said Board of Directors, namely:—

1. Shri C. V. Joag, Custodian, Bank of Maharashtra, Poona.
2. Dr. V. S. Vyas, Head of the Department of Economics, Sardar Patel University, Vallabh Vidyanagar, via. Anand.
3. Dr. K. S. Yawalkar, Dharampeth, Nagpur.
4. Shri H. B. Shivamaggi, Director, Economic Department, Reserve Bank of India, Central Office, Bombay.
5. Dr. R. M. Honavar, Additional Economic Adviser, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, New Delhi.

Shri C. V. Joag, Custodian, shall preside over the meetings of the first Board of Directors.

[No. F.4(62) BC/70.]

एल० ओ० 2563—बैंकिंग समवाय, (उपक्रम अभिरग्रहण और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का पांचवां) की धारा 7 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके एतद्वारा बैंक आफ महाराष्ट्र का प्रथम निदेशक बोर्ड गठित करती है और एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को उक्त निदेशक बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है, अर्थात् :—

1. श्री सी० वी० जोग, अभिरक्षक, बैंक आफ महाराष्ट्र, पूना ।
2. डा० वी० एस० व्यास, अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, सरदार पटेल विश्वविद्यालय, बल्लभ विद्यानगर, वाया आनंद ।
3. डा० के० एस० यावलकर, धरमपैठ, नागपुर ।
4. श्री एच० बी० शिवमामी, निदेशक, आर्थिक विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, बम्बई ।
5. डा० आर० एम० होनावर, अतिरिक्त आर्थिक सलाहकार, अर्थ विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली ।

श्री सी० वी० जोग, अभिरक्षक, प्रथम निदेशक बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे ।

[सं० एफ० 4 (62)-बी० सी०/70.]

**S.O. 2564.**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of Section 7 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Central Government, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby constitutes the first Board of Directors of Syndicate Bank and hereby appoints the undermentioned persons as the members of the said Board of Directors, namely:—

1. Shri K. K. Pal, Custodian, Syndicate Bank, Manipal.
2. Shri B. K. Kapur, 2, Mall Road, Delhi.
3. Shri M. B. Mohanad, Puthur, Distt. South Kanara.
4. Shri Swaminatha Reddy, Managing Director, Andhra Pradesh State Financial Corporation, Hyderabad.
5. Shri V. V. Bhatt, Adviser, Economic Department, Reserve Bank of India, Bombay.
6. Shri K. Ramamurthy, Joint Secretary, Department of Banking, Ministry of Finance, New Delhi.

Shri K. K. Pal, Custodian, shall preside over the meetings of the first Board of Directors.

[No. F.4(63)-B/70.]

S. S. SHIRALKAR, Addl. Secy.

एस० ओ० 2564—बैंकिंग समवाय (उपक्रम अधिनियम और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का पाँचवा) की धारा 7 की उपधारा—धारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके एतद्वारा सिण्डीकेट बैंक का प्रथम निदेशक बोर्ड गठित करती है और एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को उक्त निदेशक बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है, अर्थात:—

- 1 श्री के० के० पै०, अभिरक्षक, सिण्डीकेट बैंक, मनिपाल ।
- 2 श्री बी० के० कपूर, 2 माल रोड, दिल्ली ।
- 3 डा० एम० बी० मोहम्मद, पुन्नूर, जिला दक्षिण कनारा ।
- 4 श्री स्वामीनाथ रेड्डी, मैनेजिंग डाइरेक्टर, आन्ध्र प्रदेश, राज्य वित्त निगम, हैदराबाद ।
- 5 श्री बी० वी० भट्ट, सलाहकार, आर्थिक विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई ।
- 6 श्री के० राममूर्ति, संयुक्त सचिव, बैंकिंग विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली ।

श्री० के० के० पै०, अभिरक्षक, प्रथम निदेशक बोर्ड की अध्यक्षता करेंगे ।

[सं० एफ० 4(63)-बी० सी०/70]

एस० एस० शिरालकर, अतिरिक्त सचिव ।

#### (Department of Expenditure)

#### CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd July 1970

**S.O. 2565.**—In the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Expenditure) No. S.O. 1705, [F.1(15)-EG.I/70] dated the 12th March, 1970 published on pages 2269-2270 of the Gazette of India, Part II-Section 3-Sub-section (ii), dated the 16th May, 1970 at page 2269, for "28th February, 1967", read "28th February, 1957".

[No. F. 1(15)-EG.I/70.]

J. B. P. SINHA, Under Secy.

**MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND MINES AND METALS****(Department of Petroleum)***New Delhi, the 30th December 1969*

**S.O. 2566.**—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals S.O. No. 4313 dated 9th October, 1969 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declare its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines;

And whereas the competent authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And whereas, the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipelines and in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from all encumbrances.

[No. 11(3)/69-Lab.&amp;Legis.]

**पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय****(पेट्रोलियम विभाग)****नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1969**

**का० आ० 2566.**—यतः पेट्रोलियम, पाइप लाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० सं० 4313 तारीख 9-10-69 द्वारा केंद्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया है।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है और उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बिलंगों से मुक्त रूप में, इस घोषण के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

[सं० 11(3)/69-लेबर एण्ड लेजिस]

New Delhi, the 16th July 1970

**S.O. 2567.**—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from the drill sites well No. 18 to Sanand Well No. 15 in the Kalol Oil-field in Gujarat State, Pipelines should be laid by the Oil and Natural Gas Commission and that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of the Section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, at Western Region, Shed No. 27, Makarpura Road, near Central Workshop, Baroda-4, in the Office of the Gujarat Pipelines (Oil and Natural Gas Commission), Baroda. Every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

## SCHEDULE

For Laying Pipeline from Sanand well No. 18 to Sanand well No. 15

State : Gujarat Dist : Mehsana Taluka : Kalol

Village	Survey No.	Hectare	Arc	P. Arc.
KHATRAJ	345 . . . . .	0	3	72
"	343 . . . . .	0	3	00
JETHALAJ	245/1 . . . . .	0	1	00
"	245/2 . . . . .	0	4	56
"	247 . . . . .	0	12	00
"	248 . . . . .	0	12	72
"	252/1 . . . . .	0	17	52
"	252/2 . . . . .	0	2	40
"	V. P. Cart Track . . . . .	0	1	20
"	272 . . . . .	0	18	72
"	273 . . . . .	0	2	76
"	270 . . . . .	0	4	80
"	277 . . . . .	0	9	07
"	276/2 . . . . .	0	1	20
"	278 . . . . .	0	5	30
"	281/2 . . . . .	0	3	96
"	281/1 . . . . .	0	6	00
"	V. P. Cart Track . . . . .	0	0	42
"	323 . . . . .	0	10	26
"	322 . . . . .	0	9	72
"	344 . . . . .	0	21	24
"	345 . . . . .	0	4	48
"	319 . . . . .	0	4	38
"	347 . . . . .	0	6	00
"	348 . . . . .	0	3	12
"	317 . . . . .	0	8	76
"	352/2 . . . . .	0	3	00
"	353/2 . . . . .	0	4	87
"	353/1 . . . . .	0	8	52
"	V. P. Cart Track . . . . .	0	0	72
"	355 . . . . .	0	10	80
"	372/1 . . . . .	0	8	92
"	372/2 . . . . .	0	3	40
"	373/4 . . . . .	0	7	92

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1970

क्र० आ० 2567.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कलोल तेल क्षेत्र में व्यवहन स्थल कुआं संख्या 18 से सानन्द कुआं संख्या 15 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए और ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपायबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः, अब, पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है ।

3. उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, गुजरात पाइपलाइन (तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग) के कार्यालय, बरोदा के पश्चिमी क्षेत्र, शेड नं० 27, मकरपुरा रोड, सैन्ट्रल वर्कशाप के पास बरोदा-4 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति निर्निदिष्टः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

### अनुसूची

सानन्द कुआं संख्या 18 से सानन्द कुआं संख्या 15 तक पाइप लाइन बिछाना

राज्य : गुजरात

जिला : महेसाना

तालुका : कलोल

गांव	सर्वेक्षण संख्या	हेक्टर	आर	पी आर
1	2	3	4	5
खटराज	345	0	3	72
"	343	0	3	00
जैठलाज	245/1	0	1	00
"	245/2	0	4	56
"	247	0	12	00
"	248	0	12	72
"	252/1	0	17	52
"	252/2	0	2	40
"	वी पी काटे ट्रैक	0	1	20
"	272	0	18	72
"	273	0	2	76
"	270	0	4	80
"	277	0	9	07
"	276/2	0	1	20
"	278	0	5	30

1	2	3	4	5
„	281/2	0	3	96
„	281/1	0	6	00
„	बी० पी० कार्ट ट्रैक	0	0	42
„	323	0	10	28
„	322	0	9	72
„	344	0	21	24
„	345	0	4	48
„	319	0	4	38
„	347	0	6	00
„	348	0	3	12
„	317	0	8	76
„	352/2	0	3	00
„	353/2	0	4	87
„	353/1	0	8	52
„	बी० पी० कार्ट ट्रैक	0	0	72
„	355	0	10	80
„	372/1	0	8	92
„	372/2	0	3	40
„	373/4	0	7	92

[संख्या 20/3/67-ग्राई० प्रो० सी०/लेबर एण्ड लेजिस]

*New Delhi, the 17th July 1970*

**S.O. 2568.**—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from the drill sites well No. SBF to Sobhasan I (GGS) in the Mehsana Oil-field, in Gujarat State, Pipelines should be laid by the Oil and Natural Gas Commission and that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (i) of the Section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, at Western Region. Shed No. 27, Makarpura Road, near Central Workshop, Baroda-4, in the Office of the Gujarat Pipelines (Oil and Natural Gas Commission), Baroda. Every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

## SCHEDULE

For Laying Pipeline from D. S. SBF to Sobhasan I (GGS)

State : Gujarat

Dist : Mehsana

Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hectare	Acre	P. Acre
PUNASAN	232 . . . . .	0	1	8
„	Cart Track . . . . .	0	02	0
„	231 . . . . .	0	8	58
„	142 . . . . .	0	7	44
„	143 . . . . .	0	13	05
„	144 . . . . .	0	9	61
„	Cart Track . . . . .	0	01	00
„	181 . . . . .	0	7	08
„	145 . . . . .	0	8	52
„	137 . . . . .	0	1	1
„	136 . . . . .	0	7	08
„	135 . . . . .	0	7	81
„	134 . . . . .	0	5	25
„	126 . . . . .	0	20	23
„	127 . . . . .	0	13	65
„	117 . . . . .	0	1	01
„	116 . . . . .	0	1	83
„	115 . . . . .	0	2	99
„	114 . . . . .	0	7	81
HEBUVA	95 . . . . .	0	2	02
„	96 . . . . .	0	23	27
„	98 . . . . .	0	11	13
„	106 . . . . .	0	6	07
„	80 . . . . .	0	6	07
„	81 . . . . .	0	9	11
„	79 . . . . .	0	10	12
„	Cart Track . . . . .	0	2	00
„	226 . . . . .	0	12	14
„	225 . . . . .	0	3	04

[No 11(1)/70-Lab &amp; Legis ].

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 1970

का० प्रा० 2568 —यत् केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में मेहसाना तेल क्षेत्र में व्यधन स्थल कुआ सख्या जी एस एस से बी एफ से मासना (जी जी एस) तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए और ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ,

अतः, अब, पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है ।

3. उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, गुजरात पाइपलाइन्स (तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग) के कार्यालय , बरोदा के पश्चिमी क्षेत्र, शेड न० 27, मकरपुरा रोड, सेट्रल वर्कशॉप के पास बरोदा-4 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगतः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

डी एस एस बी एफ से सोमासन-1 (जी जी एस) तक पार्श्वलाइन बिछाना

राज्य : गुजरात

जिला : मेहसाना

तालुका : मेहसाना

गांव	सर्वेक्षण संख्या	हेक्टर	अरर	पी अरर
पुतासन	232	0	1	8
	कार्ट ट्रैक	0	02	0
	231	0	8	32
	142	0	7	44
	143	0	13	05
	144	0	9	61
	कार्ट ट्रैक	0	01	00
	181	0	7	08
	145	0	8	52
	137	0	1	1
	136	0	7	08
	135	0	7	81
	134	0	3	25
	126	0	20	23
	127	0	13	65
	117	0	1	01
	116	0	1	83
	115	0	2	99
	114	0	7	81
हैम्बा	95	0	2	02
	96	0	23	27
	98	0	11	13
	106	0	6	07
	80	0	6	07
	81	0	9	11
	79	0	10	12
	कार्ट ट्रैक	0	2	00
	226	0	12	14
	225	0	3	04

**S.O. 2560.**—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from drill sites well No. NKJ to Kadi-I (Well head Installation) in the Mehsana Oil Field in Gujarat State, Pipelines should be laid by the Oil and Natural Gas Commission and that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (i) of the Section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, at Western Region, Shed No. 27, Makarpura Road, near Central Workshop, Baroda-4, in the Office of the Gujarat Pipelines (Oil and Natural Gas Commission), Baroda. Every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

#### SCHEDULE

#### Laying of Pipeline from Well No. NKJ to Well Head Installation KADI--I

State : Gujarat :

District : Mehsana

Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hectare	Are	P. Are
CHALASAN	Cart track between S. No. 179 & 202	0	01	01
	202	0	07	08
	203/2	0	14	16
	319	0	32	37
	2.	0	11	13
	13	0	10	12
	12	0	14	16
	11	0	04	05
	Cart track between S. No. 11 & 9	0	01	01
	9	0	11	13
	63	0	12	14
	Cart track between S. No. 63 & 64	0	00	50
	64/1	0	12	14
	60	0	04	05
	59/1	0	14	16
	59	0	03	04
	56	0	10	12
	57/1	0	00	25
	51	0	06	07
	49	0	09	11

‘[s]87128’v871-04/(1)11 ‘ON’]

का०आ० 2569.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में मेहसाना तेल क्षेत्र में व्यघन स्थल कुआं संख्या एन० के०जे० से काडी (कूप-मुख प्रतिस्थापन) तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए और ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपायबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः, अब, पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उक्त उपयोग का अधिकार अर्जित करने का आदेश आश्रय एतद्वारा घोषित किया है।

3. उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, गुजरात पाइपलाइन्स (तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग) के कार्यालय, बरौदा के पश्चिमी क्षेत्र, शेड नं० 27, मकरपुरा रोड, सैन्ट्रल वर्कशॉप के पास बड़ौदा-4 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट : यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

### अनुसूची

कुआं संख्या एन० के० जे० से कुआं मुख कूप प्रां स्थापन काड़ी-1 तक पाइपलाइन बिछाना

राज्य : गुजरात : जिला : मेहसाना तालुका : काड़ी :

गांव	सर्वेक्षण संख्या	हेक्टर	आर	पी आर
वलासन	सर्वेक्षण संख्या	0	01	01
	179 और 202 के बीच कार्ट ट्रैक			
	202	0	07	08
	203/2	0	14	16
	319	0	32	37
	2	0	11	13
	13	0	10	12
	12	0	14	16
	11	0	04	05
	सर्वेक्षण संख्या 11 और 9 के बीच कार्ट ट्रैक			
	9	0	11	13
	63	0	12	14
	सर्वेक्षण संख्या 63 और 64 के बीच कार्ट ट्रैक			
	64/1	0	12	14
	60	0	04	05
	59/1	0	14	16
	59	0	03	04
	56	0	10	12
	57/1	0	00	25
	51	0	06	07
	49	0	09	11

**S.O. 2570.**—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from the drill sites G.G.SIII to Flare Point in the Kalol Oil Field in Gujarat State, Pipelines should be laid by the Oil and Natural Gas Commission and that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of the Section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, at Western Region, Shed No. 27, Makarpura Road, near Central Workshop, Baroda-4, in the Office of the Gujarat Pipelines (Oil and Natural Gas Commission), Baroda. Every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

#### SCHEDULE

For Laying Pipeline from GGS III To Flare point

State : Gujarat

Dist : Mehsana

Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hectare	Are :	P. Are :
AMBAVPURA	127	0	8	90
„	126	0	4	49
„	124	0	10	85
VADAVSWAMI	267	0	1	25

[No. 20(3)/67-IOC/Lab.&Legis.].

का०अ० 2570:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कलोल तेल क्षेत्र में व्यघन स्थल कुआँ संख्या जी० एस० जी० 111 से फ्लेर पाइन्ट तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये और ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः, अब, पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है ।

3. उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, गुजरात पाइप लाइन्स (तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग) के कार्यालय, बरीदा के पश्चिमी क्षेत्र, शेड नं० 27, मकरपुरा रोड, मैनड्रल वर्कशॉप के पास बरीदा-4 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट : यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत : हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

**अनुसूची**

जी० जी० एस० 111 से फ्लेर पाइन्ट तक पाइपलाइन बिछाना

राज्य : गुजरात : जिला : मेहसाना तालुका : काडी

गाँव	सर्वेक्षण संख्या	हेक्टर	आर	पी आर
अम्बवपुर	127	0 2 8	8	90
	126	0 4	4	49
	124	0 10	10	85
वादवस्वामी	267	0 1	1	25

[संख्या 20(3)/67-आईओ सी/लेबर एण्ड लेजिस]

**S.O. 2571.**—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from the drill sites well No. KIF (K-141) to GGS V in the Kalol Oil-field, in Gujarat State, Pipelines should be laid by the Oil and Natural Gas Commission and that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of the Section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, at Western Region, Shed No. 27, Makarpura Road, near Central Workshop, Baroda-4, in the Office of the Gujarat Pipelines (Oil and Natural Gas Commission), Baroda. Every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

**SCHEDULE**

For Laying Pipeline from well No. KIF (K141) To G. G. S. V.

State : Gujarat

Dist : Mehsana

Taluka : Kalol

Village	S. No.	Hectare	Arc	P. Arc.
CHHATRAL	303	0	6	71
"	331	0	3	90
"	332	0	4	64

[No. 20(3)/67-IOC/Lab.&Legis.].

का० आ० 2571:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कलोल तेल क्षेत्र में व्यघन स्थल कुआँ संख्या के आईएफ (के-141) से जी जी एस 5 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये और ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः, अब, पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है ।

3. उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, गुजरात पाइपलाइन्स (तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग) के कार्यालय, बरोडा के पश्चिमी क्षेत्र, शैड नं० 27, मकरपुरा रोड, सैन्डल वर्कशॉप के पास बरोडा-4 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

#### अनुसूची

कुआं संख्या के आई एफ (के 141) से जी जी एस 5 तक पाइप लाइन छिाना

राज्य : गुजरात

जिला : मेहसाना

तालुका : कालोल

गांव	सर्वेक्षण संख्या	हेक्टर	आर	पी आर
छतराल	303	0	6	71
"	331	0	3	90
"	332	0	4	64

[संख्या 20/3/67-आई ओ सी/लेबर एण्ड लेजिस]

S.O. 2572.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from the drill sites well No. 133 to GGS VI in the Kalol Oil-field, in Gujarat State, Pipelines should be laid by the Oil and Natural Gas Commission and that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (i) of the Section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, at Western Region, Shed No. 27, Makarpura Road, near Central Workshop, Baroda-4, in the Office of the Gujarat Pipelines (Oil and Natural Gas Commission), Baroda. Every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

#### SCHEDULE

##### Laying Pipelines from Well No. 133 to G. G. S. VI

State: Gujarat

District: Mehsana

Taluka: Kadi

Village	S. No.	Hectare	Acre	P. Acre.
CHADASAN	179	0	6	83
"	187/1	0	4	51
"	186 Paiki	0	1	59

1	2	3	4	5
„	186 Paiki	0	5	86
„	186 Paiki	0	7	08
„	188	0	3	30
„	V. P. Cart Track	0	1	10
„	30 Paiki	0	5	50
„	30 Paiki	0	4	88
„	28	0	8	30
„	V. P. Cart Track	0	0	75
„	14 Paiki	0	7	81
„	14 Paiki	0	5	86

[No. 20(3)/67-IOC/Lab.&Legis.].

क्र०अ० स० 2572.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कलोल तेल क्षेत्र में व्यधन स्थल कुआं संख्या 133 में जी० जी० एस० 6 तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए और ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः अब, पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उगमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है ।

2. उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, गुजरात पाइपलाइन्स (तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग) के कार्यालय, बरौदा के पश्चिमी क्षेत्र, रोड नं० 27, मकरपुरा शेड, सेंट्रल वर्कशाप के पास बरौदा-4 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर लेकेगा । ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट : यह भी कथन करेगा कि उगकी मुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

### अनुसूची

कुआ संख्या 133 में जी० जी० एस० 6 तक पाइपलाइन बिछाना

राज्य : गुजरात

जिला : मेहसाना

तालुका : कलोल

गांव	सर्वेक्षण संख्या	हेक्टर	आर	पी आर
खयामन	179	0	6	83
„	187/1	0	4	51
„	186 पैकी	0	1	59
„	186 पैकी	0	5	86
„	186 पैकी	0	7	08
„	188	0	3	30
„	बी० पी० कार्ट ट्रैक	0	1	10
„	30 पैकी	0	5	50

1	2	3	4	5
„	30 पैकी	0	4	88
„	28	0	8	30
„	बी० पी० कार्ट ड्रैक	0	0	75
„	14 पैकी	0	7	81
„	14 पैकी	0	5	86

[संख्या 20/3/67-आई० ओ० सी०/लेबर एण्ड लेजिस.]

*New Delhi, the 18th July 1970*

**S.O. 2573.**—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from the drill sites well No. 134 (KJJ) to Flare Point in the Kalol Oil-field, in Gujarat State Pipelines should be laid by the Oil and Natural Gas Commission and that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (i) of the Section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, at Western Region, Shed No. 27, Makarpura Road, near Central Workshop, Baroda-4, in the Office of the Gujarat Pipelines (Oil and Natural Gas Commission), Baroda. Every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

## SCHEDULE

For Laying Pipeline From Well Head Installation Near Well No. 134 (KJJ) to Flare Point

State : Gujarat		Dist : Mehsana		Taluka : Kalol	
Village	S. No.	Hectare	Acre	P. Arc	
KALOL	669/P . . . . .	0	4	25	

[No. 20(3)/67-IOC/Lab.&amp;Legis.].

M. V. S. PRASADA RAU, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 1970

**का० आ० सं० 2573.**—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में तेल क्षेत्र में व्यवन स्थल कुर्मा संख्या 134 (के जे जे) से फ्लेर पाइन्ट तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये और ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः, अब पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग का अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आग्रह एतद्वारा घोषित किया है।

3. उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, गुजरात पाइपलाइन्स (तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग) के कार्यालय, बरौदा के पश्चिमी क्षेत्र, शेड नं० 27, मकरपुरा रोड, सेंट्रल वर्कशाप के पास बरौदा-4 को इस अधिमूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा। ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट: यह भी कथन करेंगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

### अनुसूची

कुआं संख्या 134 (के जे जे) के समीप कूप मुख प्रति स्थापना में फ्लेर पाइन्ट तक पाइपलाइन बिछाना

राज्य- गुजरात		जिला- मेहसाना		तालुका- कलोल	
गांव	सर्वेक्षण संख्या	हैक्टर	आर	पी आर	
कलोल	669/पी	0	4	25	

[सं 20/3/67- आई० ओ० जी०/लेबर एण्ड लेजिस]

म० वे० शिव प्रसाद राव,  
अवर सचिव।

(Department of Mines and Metals)

New Delhi, the 23rd July, 1970

S. O. 2574—Whereas by the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel, Mines and Metals (Department of Mines and Metals) S.O. 2833 dated 24th August, 1968, under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition & Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in lands measuring 3840 acres or 1555.20 Hectares (approximately) in the locality specified in the Schedule appended to that notification and reproduced in the Schedule appended hereto;

And whereas in respect of the said lands no notice under sub-section (1) of section 7 of the said Act has been given;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the said sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby specifies a further period of one year commencing from the 24th August, 1970, as the period within which the Central Government may give notice of its intention to acquire the said lands or any part of the said lands or of any rights in or over such lands.

## SCHEDULE

## URIMARI BLOCK

(South Karanpura Coalfield)

Drawing No. REV/37/67

Dated 27-11-1967

(Area notified for prospecting)

Sl. No.	Village	Thana	Thana No.	District	Area	Remarks
1	Ango . . . .	Barkagon	97	Hazaribagh		Part
2	Aswa . . . .	"	153	"		"
3	Potanga . . . .	"	154	"		"
4	Urimari . . . .	"	155	"		"
5	Jarjara . . . .	"	156	"		"
6	Garsula . . . .	"	157	"		"
Total Area:			3840 acres (approximately)			
or:			1555.20 Hectares (approximately)			

## Boundary Description

- A-B . . . . line starts from the left bank of River Damodar and goes upto Central line of River Damodar in village Ango and meets at point 'B'.
- B-C . . . . line passes along the Central line of River Damodar i.e. along the part Southern boundary of village Ango, Southern boundary of villages Aswa, Potanga, Urimari and part Southern boundary of village Garsula and meets at point 'C'.
- C-D-A . . . . lines pass through village Garsula, Jarjara, Urimari, Potanga, Aswa and Ango and meet at point 'A'.

[No. F. C 3-1(10)/70]

K. SUBRAHMANYAN, Under Secy.

(खान तथा धातु विभाग)

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1970

सं० आ० 2574—यतः कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उप धारा (1) के अधीन भारत सरकार के भूतत्त्व इस्पात, खान और धातु (खान और धातु) विभाग की अधिसूचना संख्या का० आ० 2833 दिनांक 24 अगस्त, 1968 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट तथा उससे उपाबद्ध अनुसूची में दिये गये परिक्षेत्र में 3840 एकड़ (लगभग) या 1555.20 हेक्टेयर (लगभग) भूमियों में कोयले के लिए पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी ;

और यतः उक्त अधिनियम की धारा (7) की उपधारा (1) के अधीन उक्त भूमियों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा (7) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, 24 अगस्त, 1970 को प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की और कालावधि को उस कालावधि के रूप में, जिसमें भीतर केन्द्रीय सरकार उक्त भूमियों को या उक्त भूमियों के किसी भाग को और या ऐसी भूमियों में या उन पर किसी अधिकार को अर्जित करने के अपने आशय की सूचना दे सकती है, एतद्वारा विनिर्दिष्ट करती है।

### धनुसूची

#### उरीमारी ख ड

(दक्षिण करनपुरा कोयला क्षेत्र)

ड्राइंग संख्या-राजस्व 37167

तारीख 27-11-1967

(पूर्वोक्षण के लिये अधिमूर्चित क्षेत्र)

क्रम सं०	गांव	थाना	थाना सं०	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियां
1	अन्गो	वरकागांव	97	हजारीबाग		भाग
2	अस्वा	"	153	"		"
3	पोतनगा	"	154	"		"
4	उरीमारी	"	155	"		"
5	जरजरा	"	156	"		"
6	गरमुला	"	157	"		"
कुल क्षेत्र		3840 एकड़ (लगभग)				
या :		1555.20 हेक्टेयर (लगभग)				

सीमा वर्णन :

क-ख लाइन दामोदर नदी के बायें से प्रारम्भ होती है और अन्गो गांव से दामोदर नदी की केन्द्रीय लाइन तक जाती है और बिन्दु "ख" पर मिलती है।

ख-ग लाइन दामोदर नदी की केन्द्रीय लाइन के साथ से गुजरती है अर्थात् गांव अन्गो की भागतः दक्षिणी सीमा, अस्वा, पोतनगा, उरीमारी गांवों की दक्षिणी सीमा और गरमुला गांव की भागतः दक्षिणी सीमा के साथ से गुजरती है और बिन्दु "ग" पर मिलती है।

ग-घ-क लाइने गरमुला, जरजरा, उरीमारी, से गुजरती है, और बिन्दु "क" पर मिलती है।

[सं० एक० कोयला 3-1(10)/70]

के० सुब्रह्मण्यन, अवसर सचिव।

### MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

New Delhi, the 20th July 1970

S.O. 2575.—In pursuance of sub-rule (2) of rule 3 of the Aircraft Rules, 1937, and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Transport and Aviation (Department of Aviation) No. S.O. 2304 dated the 22nd

July, 1966, the Central Government hereby authorises the officers of the Civil Aviation Department specified in column 1 of the First Schedule annexed hereto, to exercise such of the powers more specifically described in the Second Schedule thereof being powers conferred by the said rules on the Central Government, as are specified in the corresponding entries in Column 2 of the said First Schedule.

## FIRST SCHEDULE

Designation of the Officer	Powers in the Second Schedule to be exercised
1	2
Director General of Civil Aviation . . . . .	All
Deputy Director General of Civil Aviation . . . . .	1 to 65, 67 to 73, 75 to 90, 94 to 96.
Director of Regulations and Information . . . . .	1, 12.
Director of Training and Licensing . . . . .	9 to 12, 57 to 61, 65, 68 to 70, 80, 81, 94, 95.
Director of Aeronautical Inspection . . . . .	2, 3, 9 to 11, 13 to 17, 19 to 56, 62, 63, 64, 69, 75, 80, 81.
Director of Aircraft Inspection . . . . .	2, 3, 9 to 11, 13 to 16, 20, 22, 25, 27 to 31, 33 to 41, 43, 45 to 54, 56, 63, 64, 69, 75.
Director of Communication . . . . .	75, 76.
Director of Air Routes and Aerodromes (Operations) . . . . .	2, 14, 59, 60, 68, 77, 78, 82, to 84, 86 to 90.
Director of Air Routes and Aerodromes (Planning) . . . . .	82, 83, 86, 87, 88, 89, 90.
Director of Air Transport . . . . .	14.
Director of Research and Development . . . . .	27, 29, 32 to 37, 39 to 41, 52 to 56
Director of Air Safety . . . . .	2, 14, 56.
Deputy Director of Training and Licensing . . . . .	57, 59, 60, 68, 69, 81, 95.
Deputy Director, Flight Crew Standards . . . . .	57, 59, 60, 68, 69, 81, 95.
Deputy Director (Examinations) . . . . .	69 (In respect of Student Flight Engineers' and Flight Engineers' Licences).
Assistant Director of Training and Licensing . . . . .	59.
Deputy Director of Aeronautical Inspection . . . . .	2, 9, 10, 14, 15, 19, 21, 25, 26, 28, 30 to 33, 38, 40, 42 to 46, 48 to 52, 54, 62 to 64, 69, 75, 80, 81.
Deputy Director of Communication . . . . .	75, 76.
Assistant Director of Communication . . . . .	76.
Deputy Director of Air Routes and Aerodromes Operations . . . . .	2, 14, 59, 60, 68, 77, 78, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90.
Deputy Director of Air Routes and Aerodromes (Planning) . . . . .	82, 83, 86, 87, 88, 89, 90.
Deputy Director of Research and Development . . . . .	27, 29, 32 to 37, 39, 40, 41, 52 to 56.
Deputy Director of Air Safety . . . . .	2, 14, 56.
Assistant Director of Air Safety . . . . .	2, 14, 56.
Senior Air Safety Officer . . . . .	2, 14, 56.
Controller of Aerodromes . . . . .	2, 14, 59, 60, 61, 68, 77, 78, 79, 82, 89.
Senior Aerodrome Officer . . . . .	2, 14, 59, 60, 61, 78, 79, 82.
Aerodrome Officer . . . . .	2, 14, 78, 79, 82.
Assistant Aerodrome Officer Incharge of Aerodrome . . . . .	2, 14, 78, 79, 82.
Assistant Aerodrome Officer on 'Duty' . . . . .	2, 14.
Controller of Aeronautical Inspection . . . . .	2, 9, 10, 14, 15, 28, 30, 31, 38, 40, 43, 45, 46, 48, 52, 54, 56, 63, 64.
Senior Aircraft Inspector (At Headquarters) . . . . .	2, 9, 10, 14, 15, 19 to 21, 25, 28, 30 to 32, 38, 40, 43, 45, 46, 48, 52, 54, 56, 63, 64.
Senior Aircraft Inspector Incharge of Inspection Office . . . . .	2, 9, 10, 14, 15, 28, 30, 31, 38, 40, 43, 45, 46, 48, 52, 54, 56, 63, 64.
Senior Aircraft Inspector . . . . .	2, 9, 10, 14, 15, 28, 30, 31, 38, 40, 45, 46, 48, 52, 54, 56, 63, 64.

I

2

Senior Communication Officer . . . . .	76	
Communication Officer . . . . .		
Senior Technical Officer . . . . .		
Technical Officer . . . . .		
Assistant Technical Officer . . . . .		
Assistant Communication Officer . . . . .	}	
in the Aeronautical . . . . .		
Communication Organization . . . . .		
Aircraft Inspection Incharge of Inspection Office . . . . .	2, 9, [Restricted to aircraft with A.U.W. (All up weight) up to 2,000 Kgs.] 10, 14, 15, 28, 30, 31, 38, 40, 45, 52, 54, 56, 63.	
Aircraft Inspector . . . . .	2, 9 [Restricted to aircraft with A.U.W. (All Up Weight) upto 2,000 Kgs.] 10, 14, 15, 28, 30, 31, 38, (Restricted to aircraft with A.U.W. (All Up Weight) upto 2,000 Kgs.] 52, 56.	
Assistant Aircraft Inspector . . . . .	2, 14, 15, 56.	
All Customs Collectors, or other Officers of the Customs for the time being Incharge of customs aerodromes . . . . .	2	

SECOND SCHEDULE

Sl. No.	Rule by which power conferred]	Nature of Power
1	2	3
<i>General</i>		
1	Clause (c) of sub-rule (2) of rule 8	To permit carriage of arms, ammunition and other dangerous goods, by air.
2	Sub-rule (6) of rule 8 . . . . .	To cause the goods to be removed from an aircraft for detailed examination.
3	Proviso to rule 15 . . . . .	To exempt aircraft from the conditions to be complied with by aircraft in flight.
4	Clause (a) of sub-rule (3) of rule 19 . . . . .	To suspend any certificate, rating or licence, or any or all the privileges of any certificate, rating or licence, for any specified period.
5	Clause (b) of sub-rule (3) of rule 19 . . . . .	To suspend any certificate, rating or licence during the investigation of any matter.
6	Clause (c) of sub-rule (3) of rule 19 . . . . .	To cancel any certificate, rating or licence.
7	Clause (d) of sub-rule (3) of rule 19 . . . . .	To endorse any adverse remarks on any certificate, rating or licence.
8	Sub-rule (4) of rule 19 . . . . .	To cancel or vary any particulars in any licence or certificate or journey log book.
9	Sub-rule (4) of rule 19 . . . . .	To vary any particulars in a certificate of airworthiness or a certificate of registration or a journey log book.
10	Sub-rule (5) of rule 19 . . . . .	To require the surrender of any licence, certificate or other document granted or issued under the rules .
11	Sub-rule (2) of rule 25 . . . . .	To permit smoking in aircraft.
12	Rule 26 . . . . .	To permit parachute descents and dropping of articles from aircraft.
13	Clause (b) proviso to rule 27 . . . . .	To permit persons to be carried on or in any part of aircraft or anything attached thereto.
14	Clauses (a) and (d) of rule 156 . . . . .	To enter, inspect and search any place of aircraft for the purpose of exercising his powers or carrying out his duties or securing compliance with any of the rules.

- 15 Clauses (b) and (c) of rule 156 . . . . . To enter and inspect any factory or place of manufacturing, overhauling, repairing or assembling aircraft, aeroengines or parts thereof including any relevant drawings.

*Registration of Aircraft*

- 16 Proviso to rule 5 . . . . . To permit a person to fly or assist in flying an unregistered aircraft and/or without its nationality and registration marks and to specify any conditions and limitations for the purpose.
- 17 Sub-rule (I) of rule 19 . . . . . To cancel certificate of registration.
- 18 Sub-rule (I) of rule 19 . . . . . To suspend certificates of registration.
- 19 Sub-rule (4) of rule 19 . . . . . To cancel or vary any particulars in certificates of registration.
- 20 Sub-rule (5) of rule 19 . . . . . To require surrender of certificates of registration.
- 21 Sub-rule (1) of rule 30 and rule 32 . . . . . To register and grant certificates of registration.
- 22 Sub-rule (4) of rule 30 . . . . . To decline to accept an application for registration.
- 23 Sub-rule (5) of rule 30 . . . . . To decline to register aircraft.
- 24 Sub-rule (6) of rule 30 . . . . . To cancel registration of aircraft.
- 25 Sub-rule (1) (a) of rule 31 . . . . . To require particulars relating to aircraft and its ownership.
- 26 Sub-rule (1) (b) of rule 31 . . . . . To refund fees if the application is not granted.

*Airworthiness and Aircraft Maintenance Engineers*

- 27 Sub-rule (2) of rule 19 . . . . . To cancel any certificate relating to the airworthiness of aircraft.
- 28 Sub-rule (2) of rule 19 . . . . . To suspend certificates of airworthiness of aircraft.
- 29 Sub-rule (2) of rule 19 . . . . . To vary the conditions attached to any certificates relating to airworthiness.
- 30 Sub-rule (5) of rule 19 . . . . . To require the surrender of certificates of airworthiness or any documents relating thereto.
- 31 Sub-rule (5) of rule 19 . . . . . To require the surrender of Aircraft Maintenance Engineers' Licences.
- 32 Rule 49 . . . . . To issue certificates of airworthiness.
- 33 Rule 49 . . . . . To call for evidence required and to decide on the inspections and tests necessary for the issue for certificates of airworthiness.
- 34 Proviso to rule 49 . . . . . To prescribe modifications of the standards of airworthiness.
- 35 Rule 50 . . . . . To accept foreign standards of airworthiness.
- 36 Rule 52 . . . . . To decide the gauges necessary for the aircraft.
- 37 Rule 53 . . . . . To approve the types and the manner of installation of instruments and equipment specified in Section B of Schedule III to the Rules.
- 38 Rule 56 . . . . . To renew certificates of airworthiness and to require flying machines to be overhauled, inspected or tested in flight and to authorise persons for inspecting the flying machine.
- 39 Sub-rule (1) of rule 58 . . . . . To require modifications.
- 40 Sub-rules (2) and (3) of rule 58 . . . . . To approve modifications and the methods by which they are carried out.

1	2	3
41. Rule 59	.	To prescribe conditions for the technical operation, maintenance and use of aircraft, accessories or equipment.
42. Sub-rule (1) of rule 61	.	To grant Aircraft Maintenance Engineers' licence.
43. Proviso to sub-rule (5) of rule 61	.	To issue a permit in respect of an extension to an Aircraft Maintenance Engineers' licence.
44. Proviso to sub-rule (5) of rule 61	.	To grant exemption from the tests to act as Aircraft Maintenance Engineer, if the applicant holds a licence granted by a competent authority of a foreign State.
45. Sub-rule (7) of rule 61	.	To renew Aircraft Maintenance Engineers' licence.
46. Sub-rule (9) of rule 61	.	To vary entries in Aircraft Maintenance Engineers' licence.
47. Sub-rule (10) of rule 61	.	To cancel Aircraft Maintenance Engineers' licence.
48. Sub-rule (10) of rule 61	.	To suspend Aircraft Maintenance Engineer licence.
49. Sub-rule (10) of rule 61	.	To endorse Aircraft Maintenance Engineers' licence.
50. Sub-rule (11) of rule 61	.	To withhold the grant or renewal of Aircraft Maintenance Engineers' licence.
51. Sub-rule (2) of rule 62	.	To refund such portion of the sum paid as represents the cost of any examination or inspection not carried out or any licence or certificate not issued.
52. Paragraph 1(b) Section (c), Schedule III.	.	To require aircraft to be weighed.
53. Paragraph 2(1) and 2(4) Section E, Schedule III.	.	To prescribe or approve modifications of designs and approve repair schemes.
54. Paragraph 3(5), Section E, Schedule III.	.	To approve methods of treatment of metals and conversion of timber etc.
55. Paragraph 5, Section E, Schedule III.	.	To approve the firms and companies.
56. Paragraph 9, Section E, Schedule III.	.	To require delivery of defective parts.

*Personnel of Aircraft*

57. Rule 38 and sub-rule (5) of rule 19.	.	To grant, to withhold the grant and renewal and to require surrender of the following licences :— (1) Student Pilot's licence. (2) Private Pilot's licence. (3) Commercial Pilot's licence, (4) Instrument Rating. (5) Assistant Flight Instructor's Rating. (6) Glider Pilot's Licence. (7) Student Navigator's licence. (8) Flight Radio Telephone Operator's licence. (9) Flight Radio Operator's Licence.
58. Rule 38 and sub-rule (5) of rule 19.	.	To grant, to withhold the grant and renewal and to require the surrender of the following licences/ratings :— (1) Senior Commercial Pilot's licence (2) Airline Transport Pilot's licence. (3) Flight Instructor's Rating. (4) Flight Navigator's licence.
59. Rule 38	.	To renew licences (except Student Flight Engineer's and Flight Engineer's licences) and ratings of aircraft personnel.
60. Rule 38	.	To vary licences (except Student Flight Engineer's and Flight Engineer's licences) and ratings, in respect of aircraft with A. U. W. not exceeding 5,700 Kgs.

1	2	3
61. Rule 38 . . . . .		To vary licences (except Student Flight Engineer's and Flight Engineer's licences) and ratings, in respect of aircraft with A. U. W. exceeding 5,700 Kgs.
62. Rule 38 and sub-rule (5) of rule 19. . . . .		To grant, to withhold the grant and renewal of and to require the surrender of— (1) Student Flight Engineer's licence. (2) Flight Engineer's licence.
63. Rule 38 . . . . .		To renew Student flight Engineer's and Flight Engineer's licences.
64. Rule 38 and sub-rules (3) & (4) of rule 19. . . . .		To vary, endorse any adverse remarks on and to cancel on vary particulars, in— (1) Student Flight Engineer's licences ; and (2) Flight Engineer's licences.
65. Sub-rule (1) of rule 39-A . . . . .		To disqualify a person for a specified period from holding or obtaining licence.
66. Sub-rule (2) of rule 39-A . . . . .		The debar a person permanently or temporarily from holding any licence
67. First proviso to rule 41. . . . .		To exempt certain I A F. personnel from flying tests and medical or other technical examinations for the issue of Senior Commercial and Airline Transport Pilot's licences.
68. Rule 45 . . . . .		To validate foreign licences.
69. Sub-rule (5) of rule 48 . . . . .		To order refund of proportionate part of fees.
70. Sub-rules (3) and (4) of rule 19 . . . . .		(a) To suspend the following and any or all of the privileges thereof for a specified period or during the investigation of any matter ; (b) To cancel the following licences/ratings; (c) To endorse any adverse remarks thereon and (d) To cancel or vary particulars therein— (1) Student Pilot's licence. (2) Private Pilot's licence. (3) Commercial Pilots' licence, (4) Instrument Rating. (5) Assistant Flight Instructors' Rating. (6) Glider Pilots' licence (7) Student Navigators' licence (8) Flight Radio Telephone Operators' licence. (9) Light Radio Operators licence
71. Sub-rules (3) and (4) of rule 19. . . . .		(a) To suspend the following licences and any or all of the privileges thereof for a specified period or during the investigation of any matter ; (b) to cancel the following licences ; (c) to endorse any adverse remarks thereon; and (d) to cancel or vary particulars therein— (1) Senior Commercial Pilot's licence; (2) Airline Transport Pilot's licence; (3) Flight Instructor's Rating , and (4) Flight Navigator's licence.
72. Sub-rule (3) of rule 19 . . . . .		To suspend or cancel Student Flight Engineer's licence.
73. Sub-rule (3) of rule 19 . . . . .		To suspend or cancel Flight Engineer's licence.
74. Proviso in paragraph 7, under Section C (Aircrews) Schedule VIII		To exempt from any or all of the tests a pilot with long and varied experience and the requisite standard of proficiency.

1	2	3
<i>Radio Telegraph Apparatus</i>		
75. Rule 63 . . . . .		To approve the type of radio telegraph apparatus for use in aircraft.
76. Rule 63 . . . . .		To approve the installation, bonding and screening of radio telegraph apparatus in aircraft Air Route Beacons, Aero Lights and False Lights.
77. Sub-rule (1) of rule 65 . . . . .		To approve the establishment and maintenance of, or alteration in the character of the light exhibited from air route beacons or aerodrome lights and prescribe conditions for such approval.
78. Sub-rule (1) of rule 66 . . . . .		To serve a notice on the owner or person in possession of the place where a light is exhibited or upon the person having charge of the light for extinguishing or effectually screening such a light and for preventing for the future exhibition of any similar light.
79. Sub-rule (4) of rule 66 . . . . .		To enter upon the place where the light is and forthwith extinguish the same.
<i>Log Books</i>		
80. Sub-rule (4) of rule 19 . . . . .		To cancel or vary any particulars in any journey log book.
81. Sub-rule (4) of rule 19 . . . . .		To vary any particulars in any journey log book.
<i>Aerodromes</i>		
82. Rule 78 . . . . .		To determine the extent and the conditions subject to which Government aerodromes may be open to public use.
83. Rule 80 . . . . .		To licence aerodromes.
84. Sub-rule (2a) of rule 82 . . . . .		To determine the charges for space in or outside a hanger at a Government civil aerodrome, leased out to any person for housing and parking of aircraft or for other purposes and to enter into agreement with a person regarding the terms and conditions of such lease.
85. Sub-rule (3) of rule 82 . . . . .		To approve tariff of charges for landing and housing at licensed public aerodromes (where such approval may be necessary) other than Government aerodromes.
86. Sub-rules (2) and (3) of rule 86 . . . . .		To approve alterations to the landing areas, buildings or other structures or to withhold such approval.
87. Sub-rule (3) of rule 19 and sub-rule (4) of rule 86 . . . . .		To cancel aerodrome licences.
88. Sub-rule (3) of rule 19 . . . . .		To suspend aerodrome licences.
89. Sub-rule (5) of rule 86 . . . . .		To approve that the aerodrome has been maintained by the licensee in a fit state for use by aircraft and marked adequately.
90. Proviso to rule 87 . . . . .		To require the inspection of an aerodrome before the grant or renewal of a licence.
<i>Air Transport Service</i>		
91. Sub-rule (1) of rule 134 . . . . .		To permit operation of scheduled services by private operators.

## पर्यटन तथा वायु विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली 20 जुलाई, 1970

सं० छा० 2575 --वायुयान नियम, 1937 के नियम 3 के उपनियम (2) के अनुसरण में श्रीर भारत सरकार के भूतपूर्व परिवहन और विमानन मंत्रालय (विमानन विभाग) की अधिसूचना सख्या का० आ० 2304 तारीख 22 जुलाई, 1966 को अधिकाृत करने हुए केन्द्रीय सरकार इससे उपाबद्ध प्रथम अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट सिविल विमानन विभाग के अधिकारियों को उसकी द्वितीय अनुसूची में अधिक विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित, उक्त नियमों द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्रदत्त, शक्तियों में से उनके प्रयोग के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत करती है जो उक्त प्रथम अनुसूची के स्तम्भ 2 में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट है।

## प्रथम अनुसूची

अधिकारी का पद-नाम	द्वितीय अनुसूची में प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ
1	2
महा-निदेशक, सिविल विमानन	सभी
उप-महा-निदेशक, सिविल विमानन	1 से 65 तक, 67 से 73 तक, 75 से 90 तक, 94 से 96 तक।
निदेशक, विनियम और सूचना	1, 12
निदेशक, प्रशिक्षण और अनुज्ञापन	9 से 12 तक, 57 से 61 तक, 65, 68 से 70 तक, 80, 81, 94, 95
निदेशक, वायुयानों निरीक्षण	2, 3, 9 से 11 तक, 13 से 17 तक, 19 से 56 तक, 62, 63, 64, 69, 75, 80, 81
निदेशक, वायुयान निरीक्षण	2, 3, 9 से 11 तक, 13 से 16 तक, 20, 22, 25, 27 से 31 तक, 33 से 41 तक, 43, 45 से 54 तक, 56, 63, 64, 65, 75
निदेशक, संसूचना	75, 76
निदेशक, वायु-मार्ग और हवाई अड्डा (सक्रियाएं)	2, 14, 59, 60, 68, 77, 78, 82 से 84 तक, 86 से 90 तक।
निदेशक, वायु-मार्ग और हवाई अड्डा (योजना)	82, 83, 86, 87, 88, 89, 90
निदेशक, हवाई परिवहन	14
निदेशक, अनुसंधान और विकास	27, 29, 32 से 37 तक, 39 से 41 तक, 52 से 56 तक।
निदेशक, वायु क्षेत्र	2, 14, 56
उपनिदेशक, प्रशिक्षण और अनुज्ञापन	57, 59, 60, 68, 69, 81, 95
उपनिदेशक, उड्डयन कर्मिंदल मानक	57, 59, 60, 68, 69, 81, 95

1	2
उपनिदेशक (परीक्षा) . . . . .	69 (विद्यार्थी उड्डयन इंजीनियरों और उड्डयन इंजीनियरों की अनुशक्तियों के बारे में ।)
सहायक निदेशक, प्रशिक्षण और अनुज्ञापन . . . . .	59
उपनिदेशक, वायुयानों निरीक्षण . . . . .	2, 9, 10, 14, 15, 19, 21, 25, 26, 28, 30 से 33 तक, 38, 40, 42 से 46 तक, 48 से 52 तक, 54, 62 से 64 तक, 69, 75, 80, 81
उपनिदेशक, संचार . . . . .	75, 76
सहायक निदेशक, संचार . . . . .	76
उपनिदेशक, वायु-मार्ग और हवाई अड्डा (संक्रिचाएं) . . . . .	2, 14, 59, 60, 68, 77, 78, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90
उपनिदेशक, वायु-मार्ग और हवाई अड्डा (योजना) . . . . .	82, 83, 86, 87, 88, 89, 90
उपनिदेशक, अनुसंधान और विकास . . . . .	27, 29, 32 से 37 तक, 39, 40, 41, 52 से 56 तक
उपनिदेशक, वायु-क्षेत्र . . . . .	2, 14, 56
सहायक निदेशक, वायु-क्षेत्र . . . . .	2, 14, 56
ज्येष्ठ वायु-क्षेत्र अधिकारी . . . . .	2, 14, 56
निर्बंधक, हवाई अड्डा . . . . .	2, 14, 59, 60, 61, 68, 77, 78, 79, 82, 89
ज्येष्ठ हवाई अड्डा अधिकारी . . . . .	2, 14, 59, 60, 61, 78, 79, 82
हवाई अड्डा अधिकारी . . . . .	2, 14, 78, 79, 82
हवाई अड्डा का भारमाधक सहायक हवाई अड्डा अधिकारी . . . . .	2, 14, 78, 79, 82
'ड्यूटी' पर सहायक हवाई अड्डा अधिकारी . . . . .	2, 14
निर्बंधक, वायुयानों निरीक्षण . . . . .	2, 9, 10, 14, 15, 28, 30, 31, 38, 40, 43, 45, 46, 48, 52, 54, 56, 63, 64
ज्येष्ठ वायुयान निरीक्षक (मुख्यालय में) . . . . .	2, 9, 10, 14, 15, 19 से 21 तक, 25, 28, 30 से 32 तक, 38, 40, 43, 45, 46, 48, 52, 54, 56, 63, 64
निरीक्षण कार्यालय का भारमाधक ज्येष्ठ वायुयान निरीक्षक . . . . .	2, 9, 10, 14, 15, 28, 30, 31, 38, 40, 43, 45, 46, 48, 52, 54, 56, 63, 64
ज्येष्ठ वायुयान निरीक्षक . . . . .	2, 9, 10, 14, 15, 28, 30, 31, 38, 40, 45, 46, 48, 52, 54, 56, 38, 64

1

2

वायुयानी संचार संगठन में ज्येष्ठ संचार अधिकारी	}	76
संचार अधिकारी		
ज्येष्ठ तकनीकी अधिकारी		
तकनीकी अधिकारी		
सहायक तकनीकी अधिकारी		
सहायक संचार अधिकारी		
निरीक्षण कार्यालय का भारसाधक वायुयान निरीक्षक	2, 9, [2,000 किग्रा० तक ए० य० डब्ल्यू० (ग्राल ग्रप बेट) के वायुयान तक निबन्धित], 10, 14, 15, 28, 30, 31, 38, 40, 45, 52, 54, 56, 63	
वायुयान निरीक्षक	2, 9, [2,000 किग्रा० तक ए० य० डब्ल्यू० (ग्राल ग्रप बेट) के वायुयान तक निबन्धित] 10, 14, 15, 28, 30, 31, 38 [2,000 किग्रा० तक ए० य० डब्ल्यू० (ग्राल ग्रप बेट) के वायुयान तक निबन्धित], 52, 56	
सहायक वायुयान निरीक्षक	2, 14, 15, 56	
सभी सीमाशुल्क कलक्टर या तत्समच सीमाशुल्क हवाई अड्डों के भारसाधक अन्य सीमाशुल्क अधिकारी	2	

### द्वितीय अनुसूची

क्रम सं०	नियम, जिसके द्वारा शक्ति प्रदत्त की गई	शक्ति का स्वरूप
----------	--	-----------------

1

2

3

### साधारण

- नियम 8 के उपनियम (2) प्रायुध, गोना-बालूद और अन्य खतरनाक सामान को वायु-मार्ग से ले जाने की अनुज्ञा देना ।
- नियम 8 का उपनियम (6) सामान को विस्तृत परीक्षा के लिए वायुयान से हटवाना ।
- नियम 15 का परन्तुक वायुयान को वायुयान द्वारा उड़ान में अनुपालन की जाने वाली शर्तों से छूट देना ।

1

2

3

- 4 नियम 19 के उपनियम (3) का खण्ड किसी प्रमाणपत्र, रेटिंग या अनुज्ञप्ति या किसी प्रमाणपत्र, रेटिंग या अनुज्ञप्ति के किसी या सभी विशेषाधिकारों को किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए निलम्बित करना ।
- 5 नियम 19 के उपनियम (3) का खण्ड किसी मामले के अन्वेषण के दौरान किसी प्रमाणपत्र रेटिंग या अनुज्ञप्ति को निलम्बित करना ।
- 6 नियम 19 के उपनियम (3) का खण्ड किसी प्रमाणपत्र, रेटिंग या अनुज्ञप्ति की रद्द करना ।
- 7 नियम 19 के उपनियम (3) का खण्ड किसी प्रमाणपत्र, रेटिंग या अनुज्ञप्ति पर प्रतिकूल टिप्पणियाँ पृष्ठांकित करना ।
- 8 नियम 19 का उपनियम (4) . किसी अनुज्ञप्ति या प्रमाणपत्र या यात्रा लॉग-बुक में किन्हीं विशिष्टियों को रद्द करना या उसमें फेरफार करना ।
- 9 नियम 19 का उपनियम (4) . उड़न योग्यता के प्रमाणपत्र या रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र या यात्रा लॉग-बुक में किन्हीं विशिष्टियों में फेरफार करना ।
- 10 नियम 19 का उपनियम (5) . नियमों के अधीन मंजूर या जारी की गई अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज के अभ्यर्पण की अपेक्षा करना ।
- 11 नियम 25 का उपनियम (2) . वायुयान में धुआँपान की अनुज्ञा देना ।
- 12 नियम 26 . . . . . पैराशूट से उतरने की और वायुयान से बस्तूओं के गिराने की अनुज्ञा देना ।
- 13 नियम 27 के परन्तुक का खण्ड (ख) वायुयान या उसके किसी भाग पर या समे संलग्न किसी चीज पर व्यक्तियों को ले जाने की अनुमति देना ।
- 14 नियम 156 के खण्ड (क) और (घ) अपनी शक्तियों का प्रयोग या कर्तव्य पालन या नियमों में से किसी का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए किसी स्थान या वायुयान में प्रवेश करना, उसका निरीक्षण करना और उसकी तलाशी लेना ।
- 15 नियम 156 के खण्ड (ख) और (ग) वायुयान विमान-इंजन या उसके भागों, जिसमें सुसंगत रेखाचित्र सम्मिलित है, के विनिर्माण, ओवरहाल, मरम्मत या समंजन के किसी कारखाने या स्थान में प्रवेश करना और उसका निरीक्षण करना ।

1

2

3

### वायुमानों का रजिस्ट्रीकरण

- 16 नियम 5 का परन्तुक . किसी व्यक्ति को अरजिस्ट्रीकृत और / या राष्ट्रिकता और रजिस्ट्रीकरण चिह्न के बिना वायुमान उड़ाने या उड़ाने में सहायता देने के लिए अनुज्ञा देना और इस प्रयोजन के लिए कोई शर्त और परिसमाप्त विनिर्दिष्ट करना ।
- 17 नियम 19 का उपनियम (1) . रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्रों को रद्द करना ।
- 18 नियम 19 का उपनियम (1) . रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्रों को निलम्बित करना ।
- 19 नियम 19 का उपनियम (4) . रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्रों से किन्हीं विशिष्टियों को रद्द करना या उनमें फेरफार करना
- 20 नियम 19 का उपनियम (5) . रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के अभ्यर्पण की अपेक्षा करना ।
- 21 नियम 30 का उपनियम (1) और नियम 32 . रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण को रजिस्टर करना और सजूर करना ।
- 22 नियम 30 का उपनियम (4) . रजिस्ट्रीकरण का आवेदन प्रतिगृहीत करने से इन्कार करना ।
- 23 नियम 30 का उपनियम (5) . वायुमान को रजिस्टर करने से इन्कार करना ।
- 24 नियम 30 का उपनियम (6) . वायुमान का रजिस्ट्रीकरण रद्द करना ।
- 25 नियम 31 का उपनियम (1) (क) . वायुमान और उसके स्वामित्व के सम्बन्ध में विशिष्टियों की अपेक्षा करना ।
- 26 नियम 31 का उपनियम (1) (ख) . यदि आवेदन मंजूर न किया गया हो तो फीस का प्रतिदाय करना ।

### उड्डयन-योग्यता और वायुमान अनुरक्षण इंजीनियर

- 27 नियम 19 का उपनियम (2) . वायुमान की उड्डयन-योग्यता के सम्बन्ध में किसी प्रमाणपत्र को रद्द करना ।
- 28 नियम 19 का उपनियम (2) . वायुमान की उड्डयन-योग्यता का प्रमाणपत्र निलम्बित करना ।
- 29 नियम 19 का उपनियम (2) . उड्डयन-योग्यता के सम्बन्ध में प्रमाणपत्रों से संलग्न शर्तों में फेरफार करना ।
- 30 नियम 19 का उपनियम (5) . उड्डयन-योग्यता के प्रमाणपत्रों या उनसे सम्बन्ध किसी दस्तावेज के अभ्यर्पण की अपेक्षा करना ।

1	2	3
31	नियम 19 का उपनियम (5)	वायुयान अनुरक्षण इंजीनियरों की अनुशक्तियों के अभ्यर्पण की अपेक्षा करना ।
32	नियम 49	उड्डयन-योग्यता का प्रमाणपत्र जारी करना ।
33	नियम 49	उड्डयन-योग्यता का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अपेक्षित साक्ष्य मांगना और आवश्यक निरीक्षण और परीक्षण पर विनिश्चय करना ।
34	नियम 49 का परन्तुक	उड्डयन-योग्यता के मानकों के उपान्तरण विहित करना ।
35	नियम 50	उड्डयन-योग्यता के विदेशी मानक प्रतिगृहीत करना ।
36	नियम 52	वायुयान के लिए आवश्यक गैजों का विनिश्चय करना ।
37	नियम 53	नियमों की अनुसूची 3 के खण्ड ख में विनिर्दिष्ट उपकरणों और उपस्कर के संस्थापन के प्रकार और रीति का अनुमोदन करना ।
38	नियम 56	उड्डयन-योग्यता के प्रमाणपत्रों का नवीकरण करना, उड्डयन-मशीनों के ओवरहॉल निरीक्षण या उड्डयन में परीक्षण किए जाने की अपेक्षा करना और व्यक्तियों को उड्डयन मशीन के निरीक्षण के लिए प्राधिकृत करना ।
39	नियम 58 का उपनियम (1)	उपान्तरण की अपेक्षा करना ।
40	नियम 58 के उपनियम (2) और (3)	उपान्तरणों और उनके किए जाने की पद्धतियों का अनुमोदन करना ।
41	नियम 59	वायुयान, उपसाधनों या उपस्कर की तकनीकी संक्रिया, उनके अनुरक्षण और उपयोग के लिए शर्तें विहित करना ।
42	नियम 61 का उपनियम (1)	वायुयान अनुरक्षण इंजीनियर की अनुशक्ति मंजूर करना ।
43	नियम 61 के उपनियम (5) परन्तुक	वायुयान अनुरक्षण इंजीनियर की अनुशक्ति के विस्तारण के बारे में अनुज्ञा जारी करना ।
44	नियम 61 के उपनियम (5) परन्तुक	यदि आवेदक किसी विदेशी राज्य के सामक्ष प्राधिकारी द्वारा मंजूर की हुई अनुशक्ति धारण किए हुए हो तो वायुयान अनुरक्षण इंजीनियर के रूप में कार्य करने के लिए परीक्षण से छूट की मंजूरी देना ।

1

2

3

- 45 नियम 61 का उपनियम (7) . वायुयान अनुरक्षण इंजीनियर की अनुज्ञप्ति का नवीकरण करना ।
- 46 नियम 61 का उपनियम (9) . वायुयान अनुरक्षण इंजीनियर की अनुज्ञप्ति की प्रविष्टियों में फेरफार करना ।
- 47 नियम 61 का उपनियम (10) . वायुयान अनुरक्षण इंजीनियर की अनुज्ञप्ति को रद्द करना ।
- 48 नियम 61 का उपनियम (10) . वायुयान अनुरक्षण इंजीनियर की अनुज्ञप्ति को निलम्बित करना ।
- 49 नियम 61 का उपनियम (10) . वायुयान अनुरक्षण इंजीनियर की अनुज्ञप्ति को पृष्ठांकित करना ।
- 50 नियम 61 का उपनियम (11) . वायुयान अनुरक्षण इंजीनियर की अनुज्ञप्ति की मंजूरी या उसके नवीकरण को रोक लेना ।
- 51 नियम 62 का उपनियम (2) . संदत्त राशि के उस भाग का प्रतिदाय करना जो किसी न ली गई परीक्षा या न किए गए निरीक्षण या जारी न किए गए प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति की लागत को व्यपदिष्ट करता हो,
- 52 अनुसूची 3, खण्ड ग, पैरा (ख) . वायुयान के तोलने की अपेक्षा करना ।
- 53 अनुसूची 3, खण्ड ड, पैरा 2(1) और 2(4) . डिजाइनों और अनुमोदित मरम्मत स्कीमों के उपान्तरणों को विहित या अनुमोदित करना ।
- 54 अनुसूची 3, खण्ड ऊ, पैरा 3(5) . धातुओं के शोधन की पद्धतियों और काष्ठ आदि के संपरिवर्तन का अनुमोदन करना ।
- 55 अनुसूची 3, खण्ड ड, पैरा 5 . फर्मों और कम्पनियों का अनुमोदन करना ।
- 56 अनुसूची 3, खण्ड ऊ, पैरा 9 . वृत्तियुक्त भागों के परिदान की अपेक्षा करना ।

### वायुयान के कार्मिक

- 57 नियम 38 और नियम 19 का उप-नियम (5) . निम्नलिखित अनुज्ञप्तियों की मंजूरी और उनके नवीकरण को मंजूर करना, रोक लेना और उनके अभ्यर्पण की अपेक्षा करना :—
- (1) विद्यार्थी पाइलट की अनुज्ञप्ति
- (2) ग्राइवेट पाइलट की अनुज्ञप्ति

1	2	3
		(3) वाणिज्यिक पाइलट की अनुज्ञप्ति (4) उपकरण रेटिंग (5) सहायक उड्डयन अदेशनक का रेटिंग (6) ग्लाइडर पाइलट की अनुज्ञप्ति (7) विद्यार्थी नेविगेटर की अनुज्ञप्ति (8) उड्डयन रेडियो टेलिफून आपरेटर की अनुज्ञप्ति (9) उड्डयन रेडियो आपरेटर की अनुज्ञप्ति ।
58 नियम 38 और नियम 19 का उप-नियम (5)		निम्नलिखित अनुज्ञप्तियों/रेटिंगों की मंजूरी और उनके नवीकरण को मंजूर करना, रोक लेना और उनके अभ्यर्पण की अपेक्षा करना :— (1) ज्येष्ठ वाणिज्यिक पाइलट की अनुज्ञप्ति (2) हवाई परिवहन पाइलट की अनुज्ञप्ति (3) उड्डयन अनुदेशक का रेटिंग (4) उड्डयन नेविगेटर की अनुज्ञप्ति ।
59 नियम 38		वायुयान कर्मियों की अनुज्ञप्तियों (विद्यार्थी उड्डयन इंजीनियर की और उड्डयन इंजीनियर की अनुज्ञप्तियों के सिवाय) और उनके रेटिंगों का नवीकरण ।
60 नियम 38		5700 किग्रा० से अधिक ए० यू० डब्ल्यू० के वायुयान के बारे में अनुज्ञप्तियों (विद्यार्थी उड्डयन इंजीनियर की और उड्डयन इंजीनियर की अनुज्ञप्तियों के सिवाय) और रेटिंगों में फेरफार करना ।
61 नियम 38		5700 किग्रा० से अधिक ए० यू० डब्ल्यू० के वायुयान के बारे में अनुज्ञप्तियों (विद्यार्थी उड्डयन इंजीनियर की और उड्डयन इंजीनियर की अनुज्ञप्तियों के सिवाय) और रेटिंगों में फेरफार करना ।
62 नियम 38 और नियम 19 का उप-नियम (5)		निम्नलिखित की मंजूरी और उनके नवीकरण को मंजूर करना, रोक लेना और उनके अभ्यर्पण की अपेक्षा करना :— (1) विद्यार्थी उड्डयन इंजीनियर की अनुज्ञप्ति । (2) उड्डयन इंजीनियर की अनुज्ञप्ति ।

- 63 नियम 38 . . . विद्यार्थी उड्डयन इंजीनियर और उड्डयन इंजीनियर की अनुज्ञप्तियों का नवीकरण ।
- 64 नियम 38 और नियम 19 का उप-नियम (3) और (4) निम्नलिखित पर किन्हीं प्रतिकूल टिप्पणियों में फेरफार करना, उनका पृष्ठांकन करना और उनमें की विशिष्टियों को रद्द करना या उनमें फेरफार करना :—  
(1) विद्यार्थी उड्डयन इंजीनियर की अनुज्ञप्तियां; और  
(2) उड्डयन इंजीनियर की अनुज्ञप्तियां ।
- 65 नियम 39-क का उपनियम (1) . किसी व्यक्ति को अनुज्ञप्ति धारण करने या प्राप्त करने से विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए निरहित करना ।
- 66 नियम 39-क का उपनियम (2) . किसी व्यक्ति को किसी अनुज्ञप्ति के धारण करने से स्थायी या अस्थायी रूप से विवर्जित करना ।
- 67 नियम 41 का प्रथम परन्तुक . भारतीय वायुसेना के कतिपय कार्मिकों को ज्येष्ठ वाणिज्यिक और हवाई परिवहन पाइलट की अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए उड्डयन परीक्षण और स्वास्थ्य परीक्षा या अन्य तकनीकी परीक्षाओं से छूट देना ।
- 68 नियम 45 . . . विदेशी अनुज्ञप्तियों को विधिमान्य करना ।
- 69 नियम 48 का उपनियम (5) . फीस के अनुपातिक भाग के प्रतिदाय का आदेश देना ।
- 70 नियम 19 के उपनियम (3) और (4) (क) निम्नलिखित को और उनके किसी विशेषाधिकार या सभी विशेषाधिकारों को विनिर्दिष्ट कालावधि या किसी मामले के अन्वेषण के दौरान निलम्बित करना ;  
(ख) निम्नलिखित अनुज्ञप्तियों/रेटिंगों को रद्द करना ;  
(ग) उन पर कोई प्रतिकूल टिप्पणियां पृष्ठांकित करना; और  
(घ) उनमें विशिष्टियों को रद्द करना या उनमें फेरफार करना :—  
(1) विद्यार्थी पाइलट की अनुज्ञप्ति  
(2) ग्राइवेट पाइलट की अनुज्ञप्ति

1	2	3
		<p>(3) वाणिज्यिक पाइलट की अनुज्ञप्ति</p> <p>(4) उपकरण रेटिंग</p> <p>(5) सहायक उड्डयन अनुदेशक का रेटिंग</p> <p>(6) ग्लाइडर पाइलट की अनुज्ञप्ति</p> <p>(7) विद्यार्थी नेविगेटर की अनुज्ञप्ति</p> <p>(8) उड्डयन रेडियो टेलीफोन आपरेटर की अनुज्ञप्ति</p> <p>(9) उड्डयन रेडियो आपरेटर की अनुज्ञप्ति ।</p>
71 नियम 19 के उपनियम (3) और (4)	(क)	निम्नलिखित अनुज्ञप्तियों को और उनके किसी विशेषाधिकार या सभी विशेषाधिकारों को विनिर्दिष्ट कालावधि या किसी मामले के अन्वेषण के दौरान निलम्बित करना ;
	(ख)	निम्नलिखित अनुज्ञप्तियों को रद्द करना ;
	(ग)	उन पर कोई प्रतिकूल टिप्पणियां पृष्ठांकित करना ;
	(घ)	उनमें किन्हीं विशिष्टियों को रद्द करना या उनमें फेरफार करना :—
	(1)	ज्येष्ठ वाणिज्यिक पाइलट की अनुज्ञप्ति ;
	(2)	हवाई परिवहन पाइलट की अनुज्ञप्ति ;
	(3)	उड्डयन अनुदेशक का रेटिंग ; और
	(4)	उड्डयन नेविगेटर की अनुज्ञप्ति ।
72 नियम 19 का उपनियम (3)		विद्यार्थी उड्डयन इंजीनियर की अनुज्ञप्ति को निलम्बित या रद्द करना ।
73 नियम 19 का उपनियम (3)		उड्डयन इंजीनियर की अनुज्ञप्ति को निलम्बित या रद्द करना ।
74 अनुसूची 8, खण्ड (ग) (हवाई कर्मी) के अन्तर्गत पैरा 7 में का परन्तुक		किसी लम्बे और विभिन्न अनुभव और प्रवीणता के अपेक्षित स्तर रखने वाले पाइलट को किसी या सभी परीक्षणों से छूट देना ।
<b>रेडियो तार उपकरण</b>		
75 नियम 63 . . . . .		वायुयान में प्रयोग के लिए रेडियो तार उपकरण का प्रकार अनुमोदित करना ।
76 नियम 63 . . . . .		वायुयान में रेडियो तार उपकरण के संस्थापन, बंधन और प्रतिच्छादित करने का अनुमोदन करना ।

1

2

3

### वायु-मार्ग संकेतिक, हवाई अड्डा दीप और कूट दीप

- 77 नियम 65 का उपनियम (1) . वायुमार्ग संकेतिक से प्रदर्शित प्रकाश या हवाई अड्डा दीपों की स्थापना और अनुरक्षण या उनके स्वरूप में परिवर्तन का अनुमोदन करना और ऐसे अनुमोदन के लिए शर्तें विहित करना।
- 78 नियम 66 का उपनियम (1) . उस स्थान के स्वामी या कब्जाधारी व्यक्ति पर जहां प्रकाश प्रदर्शित हो या प्रकाश के भारत-साधक व्यक्ति के ऊपर ऐसे प्रकाश को बुझाने या प्रभावी रूप से प्रतिच्छादित करने के लिए और किसी समरूप प्रकाश के भाती प्रदर्शन को रोकने के लिए नोटिस तामील करना।
- 79 नियम 66 का उपनियम (4) . उस स्थान पर प्रवेश करना जहां प्रकाश है और उसे तत्काल बुझाना।

### लाँग-बुक

- 80 नियम 19 का उपनियम (4) . किसी यात्रा लाँग-बुक में किन्हीं विशिष्टियों को रद्द करना या उनमें फेरफार करना।
- 81 नियम 19 का उपनियम (4) . किसी यात्रा लाँग-बुक में किन्हीं विशिष्टियों में फेरफार करना।

### हवाई अड्डे

- 82 नियम 78 . . . . . उस परिमाण और उन शर्तों का अवधारण करना जिनके अध्याधीन सरकारी हवाई अड्डे लोक उपयोग के लिए खुले रह सकते हैं।
- 83 नियम 80 . . . . . हवाई अड्डों को अनुज्ञप्त करना।
- 84 नियम 82 का उपनियम (2क) . सरकारी सिविल हवाई अड्डे पर हेंगर के भीतर या बाहर किसी व्यक्ति को वायुयान आवासन और ठहराने के लिए या अन्य प्रयोजनों के लिए पट्टे पर दिए गए स्थान के प्रभार का अवधारण करना और ऐसे पट्टे के निबन्धनों और उसकी शर्तों के बारे में किसी व्यक्ति से करार करना।

1	2	3
85	नियम 82 का उपनियम (3)	सरकारी हवाई अड्डों से भिन्न अनुज्ञप्त लोक हवाई अड्डों पर (जहां ऐसा अनुमोदन आवश्यक हो) अवतरण और आवासन के लिए प्रभारों के टैरिफ का अनुमोदन करना ।
86	नियम 86 के उपनियम (2) और (3)	अवतरण क्षेत्रों, भवनों या अन्य संरचनाओं में परिवर्तन का अनुमोदन करना या ऐसे अनुमोदन को रोकना ।
87	नियम 19 का उपनियम (3) और नियम 86 का उपनियम (4)	हवाई अड्डा अनुज्ञप्तियों को रद्द करना ।
88	नियम 19 का उपनियम (3)	हवाई अड्डा अनुज्ञप्तियों को निलम्बित करना ।
89	नियम 86 का उपनियम (5)	यह अनुमोदन करना कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा हवाई अड्डे का वायुयान के उपयोग के लिए उचित दशा में अनुरक्षण और पर्याप्त रूप से चिह्नित किया गया है ।
90	नियम 87 का परन्तुक	अनुज्ञप्ति की मंजरी या उसके नवीकरण से पूर्व हवाई अड्डे के निरीक्षण की अपेक्षा करना ।

### हवाई परिवहन सेवा

- 91 नियम 134 का उपनियम (1) . प्राइवेट ऑपरेटरों द्वारा अनुसूचित सेवाओं के प्रचालन की अनुज्ञा देना ।
- 92 नियम 134 का उपनियम (2) . किसी वायु परिवहन उपक्रम को जिसका कारबार का प्रधान स्थान भारत के बाहर किसी देश में है, वायु परिवहन सेवा का प्रचालन करने की अनुज्ञा देना ।
- 93 नियम 134 का उपनियम (3) . अनुसूचित वायु परिवहन सेवाओं के प्रचालन की अनुज्ञा देना ।

### वायु नियम

- 94 अनुसूची 4 खण्ड 3—साधारण नियम 1 भूमि से 600 मीटर (2000 फुट) से कम पैरा 3.1' 2' 2, उप पैरा (iv) ऊंचाई पर एक्रोबैटिक्स किए जाने की अनुज्ञा देना ।
- 95 अनुसूची 4 खण्ड 3—साधारण नियम 1 किसी वस्तु के वायुयान द्वारा खिचाव के बारे में अपेक्षाएं विहित करना ।  
पैरा 3.2.3 वस्तु खिचाव

1

2

3

96 अनुसूची 4 परिशिष्ट क पैरा 5.2.2 अवतरण क्षेत्र, अवतरण क्षेत्र को पहुंच के रास्ते और अवतरण क्षेत्र की सीमा में प्रकाश करने के बारे में अपेक्षाएं विहित करना।

[फा० सं०/10-ए/8-70/ए० आर०/1937/(1) 1970]

सुरेन्द्र नाथ कौल, अवसर सचिव।

## MINISTRY OF FOREIGN TRADE

### CARDAMOM CONTROL

*New Delhi, the 24th July 1970*

**S.O. 2576.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925), the Central Government hereby adds to the Schedule to the said Act the name of the following public institution, namely:—

“The CARDAMOM BOARD established under the Cardamom Act, 1965 (42 of 1965)”.

[No. F. 29(41)Plant(B)/67.]

### विदेशी व्यापार मंत्रालय

### इलायची नियंत्रण

नई दिल्ली, 24 जुलाई 1970

फा० आ० 2576.—भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) की धारा 8 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नोक्त सरकारी संख्या का नाम जोड़ती है, अर्थात् :—

“इलायची अधिनियम, 1965 (1965 का 42) के अधीन स्थापित इलायची बोर्ड”

[सं० 29(41)प्लांट (बी)/67]

**S.O. 2577.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 8 of the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act shall apply to the Provident Fund established for the benefit of the employees of the Cardamom Board.

[No. F. 29(41)Plant(B)/67.]

M. L. GUPTA, Under Secy.

फा० आ० 2577—भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) की धारा 8 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के उपाबंध इलायची बोर्ड के कर्मचारियों के लाभार्थ स्थापित भविष्य निधि पर लागू होंगे।

[सं० 29 (41)—प्लांट (बी)/67]

एम० एल० गुप्ता, अवसर सचिव।

**DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS**

(P. and T. Board)

*New Delhi, the 23rd July 1970*

**S.O. 2578.**—In exercise of the powers conferred by section 42 and 74 of the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Post Office Rules, 1933, namely:—

1. These rules may be called the Indian Post Office (Seventh Amendment) Rules, 1970.

2. In sub-rule (1) of rule 215 of the Indian Post Office Rules, 1933, in clause (a), for the words letter and figures "the 1st December 1969," the words, letters and figures "the 1st April, 1970" shall be substituted.

[No. 20/5/70-CF.]

K. GOPALAKRISHNAN,  
Dy. Director Genl. (Mails).

**भारतीय डाक तार विभाग**

**(डाक तार महानिदेशक का कार्यालय)**

*नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1970*

**क्र० आ० 2558.**—भारतीय डाकतार अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धाराओं 42 और 74 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय डाकतार नियम, 1933 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. ये नियम भारतीय डाकतार (सातवां संशोधन) नियम, 1970 कहे जा सकेंगे।
2. भारतीय डाकतार नियम, 1933 के नियम 215 के उपनियम (1) के खण्ड (क) में "प्रथम दिसम्बर, 1969" शब्दों और अंकों के स्थान पर "प्रथम अप्रैल, 1970" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

[सं० 20/5/70-सी० एफ०]

क० गोपालाकृष्णन्

उपमहा निदेशक (डाक)

**MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION**

(Department of Agriculture)

*New Delhi, the 20th July 1970*

**S.O. 2579.**—Whereas a draft of the Chillies Grading and Marking (Amendment) Rules, 1969, was published as required by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937), at pages 4411 to 4414 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 11th October, 1969, under the notification of the Government of India in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation, (Department of Agriculture), No. S.O. 4104 dated the 3rd October, 1969, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the 2nd November, 1969;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 11th October, 1969;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Chillies Grading and Marking Rules, 1962 namely:—

1. These rules may be called the Chillies Grading and Marking (Amendment) Rules, 1970;
2. In the Chillies Grading and Marking Rules, 1962,
  - (a) in rules 3 and 4, for the words, figures and letter "Schedules I to V-A", the words, figures and letter "Schedules I to V-C" shall be substituted;

(b) for Schedule V-A, the following Schedules shall be substituted, namely:—

SCHEDULE V-A  
(See rules 3 and 4)

*Grade Designations and Definition of Quality of Chillies Varieties not covered by Schedules I, II, III, IV and V of these Rules and Produce in India*

Grade Designation	Colour	Special Characteristics Maximum limits percentage by weight						General Characteristics
		Damaged & Discoloured pods	Pods without stalk	Moisture	Loose Seeds	Foreign Matter	Broken Chillies	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Special	Characteristics of the Variety	2.0	2.0	11.5	2%	1.0	4.0	Chillies shall :— (a) be the dried ripe fruits belonging to the species <i>Capsicum annum</i> L; (b) Have the characteristics shape, colour, length pungency and seed contents normal to the variety;**
General	—Do—	4.0	3.0	11.5	3%	2.0	6.0	(c) be free from visible mould of insects and be in sound conditions and fit for human consumption; (d) be of current years crop and free from extraneous colouring matter, oil and any other harmful substance and (e) be of uniform colour in each individual consignment and that colour shall not vary from bag to bag within the consignment.
Fair	—Do—	6.0	4.0	11.5	3.0	2.0	8.0	

Discoloured Pods. Pods having brown, black, white and other coloured patches.

Foreign matter : All extraneous matter including clay pieces and loose stalks will be treated as foreign matter. A tolerance is permissible up to 0.5% in excess of the tolerance specified under Col. 7 in respect of Special and General Grades.

For accidental errors tolerance of 0.5% under Col. 3 and 1.0% under Col. 4 is permissible for both the grades, Special and General.

Moisture— A tolerance of 0.5% for moisture content will be allowed in Special and General Grade only.

\*\*Variety— The name of the Variety shall be separately stamped on the grade designation label.

## SCHEDULE V-B

(See rules 3 and 4)

*Grade designation and definition of quality of Chillies (Stalkless) Produced in India.*

Grade Designation	Trade Name	Pods with Stalk	Pods with caly	Moisture	Special Characteristics Maximum limits of Tolerance		General Characteristics
					Loose seeds	Foreign Matter	
1	2	3	4	5	6	7	8
Chillies General (Stalkless)	Stalk less Chillies	% 1.00 by count	% 5.00 by count	% 11.00	% 5.00	% 0.5	Chillies shall :— (a) be the dried ripe fruits belonging to the species <i>Capsicum annum</i> . (b) be free from visible mould or insects and is in sound, condition and fit for human consumption, and (c) be of one year's crop and free from extraneous colouring matter, oil and any other harmful substance.

Foreign matter— All extraneous matter including calyx pieces and loose stalk will be treated as foreign matter. A tolerance is permissible upto 0.25% in excess of the tolerance specified under columns 3 and 7 and 0.5% in column 4.

Moisture— A tolerance of 0.5% for Moisture content will be allowed over and above the stipulated limit.  
Stalkless Chillies means Chillies from which the Calyx together with the stalk are removed.

# SCHEDULE V-C

(See rules 3 and 4)

Grade designation and definition of quality of chillies (clipped) produced in India.

Grade Designation	Trade Name	Pods with Stalk	Pods Moisture	Special Characteristics Maximum limits of tolerance		General Characteristics
				Loose seeds	Foreign matter	
1	2	3	4	5	6	7
Chillies General (clipped)	Clipped chillies	% 1.00 by count	% 11.00	% 3.00	% 0.5	Chillies shall :— (a) be the dried ripe fruits belonging to the species <i>capsicum annum</i> . (b) be free from visible mould or insects and be in sound condition and fit for human consumption; and (c) be of one year's crop and free from extraneous colouring matter oils and any other harmful substance.

Foreign matter— All extraneous matter including Calyx pieces and loose stalk will be treated as foreign matter. A tolerance is permissible upto 0.25% in excess of tolerance specified under columns 3 and 6.  
Moisture— A tolerance of 0.5% for moisture content will be allowed over and above the stipulated limit. Clipped Chillies means Chillies having the stalks clipped from the very base but having calyx.

[No. F-13/1/70-L.A.]

R. SUBRAHMANYAM, Under Secy.

## खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 1970

का०आ० 2579 —यतः कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नन) अधिनियम 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा यथा अपेक्षित मिर्च श्रेणीकरण और चिह्नन (सशोधन) नियम, 1969 के प्रारूप को भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 11 अक्तूबर, 1969 के पृष्ठ 4411 से 4414 पर भारत सरकार के खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 4104 तारीख 3 अक्तूबर, 1969 के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया था जिसमें 2 नवम्बर, 1969 तक उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे जिनका उसमें प्रभावित होने की संभावना थी ,

और यतः उक्त राजपत्र 11 अक्तूबर, 1969 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और यतः केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रारूप पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर, विचार कर चुकी है ,

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार मिर्च श्रेणीकरण और चिह्नन नियम, 1962 में और आगे सशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् —

1. ये नियम मिर्च श्रेणीकरण और चिह्नन (सशोधन) नियम, 1970 कहे जा सकेंगे ।

2. मिर्च श्रेणीकरण और चिह्नन नियम, 1960 में—

(क) नियम 3 और 4 में “1 से 5-क तक की अनुसूचियों” शब्दों, अक्षरों और अक्षर के स्थान पर “1 से 5-ग तक की अनुसूचियों” शब्द, अक्षर और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

(ख) अनुसूची 5-क के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियां प्रति स्थापित की जाएंगी, अर्थात् —

“अनुसूची 5-क”

अनुसूची 5-क

(नियम 3 और 4 देखिय)

उन किस्मों की मिर्चों की क्वालिटी के जो इन नियमों की अनुसूची 1, 2, 3, 4 और 5 के अन्तर्गत नहीं आती और भारत में पैदा की जाती हैं, श्रेणी अभिधान और परिभाषा ।

श्रेणी अभिधान	रंग	विशेष लक्षण तौल के अनुसार प्रतिशतता की अधिकतम सीमा						साधारण लक्षण
		खराब हुई और विवर्णित फलियां	डंटल रहित फलियां	नमी	खुले बीज	बाह्य पदार्थ	टूटी हुई मिर्चें	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
विशेष	किस्म के लक्षण	2.0	2.0	11.5	2 प्रतिशत	1.0	4.0	मिर्च :— (क) लाल मिर्च जाति के सूखे पके फल होंगे ।
साधारण	यथोक्त	4.0	3.0	11.5	3 प्रतिशत	2.0	6.0	(ख) उनके लक्षण आकार, रंग लम्बाई, चरपराहट और बीज उसी प्रकार के होंगे जैसे कि प्रसामान्यतया उस किस्म के होते हैं ।
औसत दर्जे का	यथोक्त	6.0	4.0	11.5	3.0	2.0	8.0	(ग) दृश्य फफूंदी या कीड़ों से रहित होंगी और ठीक हालत में और मानव उपभोग के योग्य होंगी ।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							(घ) चालू वर्ष की उपज की और बाहरी रंजक पदार्थ, तेल और किसी अन्य उपहानिकर पदार्थ से मुक्त होंगी, और	
							(ङ) प्रत्येक परेषण में समान रंग की होंगी और वह रंग एक ही परेषण में विभिन्न थैलों में अलग-अलग नहीं होगा।	

विवर्णित फलियां :—भूरे, काले, सफेद और अन्य रंगी धब्बे फलियां।

बाह्य पदार्थ :—मिट्टी के टुकड़ों और खुले डंटलों सहित सभी बाहरी पदार्थ माने जायेंगे। विशेष और साधारण श्रेणियों के बारे में स्तम्भ 7 के अधीन विनिर्दिष्ट सहन सीमा से 0.5 प्रतिशत अधिक तक अनुज्ञेय है।

आकस्मिक मूलों के लिये विशेष और साधारण दोनों श्रेणियों के लिये स्तम्भ 3 के अन्तर्गत 0.5 प्रतिशत और स्तम्भ 4 के अन्तर्गत 1.0 प्रतिशत की सहनसीमा अनुज्ञेय है।

नमी :—केवल विशेष और साधारण श्रेणियों में नमी के लिए 0.5 प्रतिशत की सहन-सीमा अनुज्ञेय होगी।

किस्म :—किस्म का नाम, श्रेणी अभिधान लेबल पर अलग से स्टाम्पित होगा।

**अनुसूची 5-ख**

(निय : 3 और 4 देखिए)

भारत में उत्पादित मिर्च (डंठल रहित) की क्वालिटी का श्रेणी अभिधान और परिभाषा ।

श्रेणी अभिधान	व्यापार नाम	डंठल सहित फलियां	कैलक्स सहित फलियां	नमी	विशेष लक्षण अधिकतम सहन-सीमा		साधारण लक्षण
					खुले बीज	बाह्य पदार्थ	
1	2	3	4	5	6	7	8
मिर्च साधारण (डंठल रहित)	डंठल रहित मिर्च	प्रतिशत 1-00 काउन्ट के अनु- सार	प्रतिशत 5.00 काउन्ट के अनु- सार	प्रतिशत 11.00	प्रतिशत 5.00	प्रतिशत 0.5	मिर्च :— (क) लाल मिर्च जाति के सूखे पके फल होगी (ख) दृश्य फफूंदी या कीड़ों से रहित होगी और ठीक हालत में और मानव उपभोग के योग्य होगी । (ग) एक वर्ष की उपज की और बाहरी रंजक पदार्थ, तेल और किसी अन्य अपहानिकर पदार्थ से मुक्त होगी ।

बाह्य पदार्थ :—कैलक्स टुकड़ों और डुले डंठलों सहित सभी बाहरी पदार्थ बाह्य पदार्थ माने जायेंगे । स्तम्भ 3 और 7 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट सहनसीमा से 0.25 प्रतिशत अधिक तक और स्तम्भ 4 में 0.5 प्रतिशत तक अनुज्ञेय है ।

नमी :—निर्दिष्ट सीमा से आगे नमी के लिए 0.5 प्रतिशत सहन-सीमा अनुज्ञेय होगी । डंठल रहित मिर्च से ऐसी मिर्च अभिप्रेत हैं जिसमें कैलक्स को डंठल सहित हटा दिया गया हो ।

## अनुसूची 5-ग

(निम्न 3 और 4 देखिए)

भारत में उत्पादित मिर्च (कतरी हुई) की क्वालिटी का श्रेणी अभिधान और परिभाषा

श्रेणी अभिधान	व्यापार नाम	डंठल सहित फलियां	नमी	विशेष लक्षण अधिकतम सहन-सीमा		साधारण लक्षण
				खुले बीज	बाह्य बीज	
1	2	3	4	5	6	7
मिर्च साधारण कतरी हुई	कतरी हुई मिर्च	प्रतिशत 1.00 काउन्ट के अनुसार	प्रतिशत 11.00	प्रतिशत 3.00	प्रतिशत 0.5	मिर्च :— (क) लाल मिर्च जाति के सूखे पके फल होगी । (ख) दृश्य फफूंदी या कीड़ों से रहित होगी और बे ठीक हालत में और मानव उपभोग के योग्य होगी । (ग) एक वर्ष की उपज की और बाहरी रंजक पदार्थ, तेल और किसी अन्य अपहानिकर पदार्थ से मुक्त होगी ।

बाह्य पदार्थ :—कैलिकस टुकड़ों और खुले डंठलों सहित सभी बाहरी पदार्थ बाह्य पदार्थ माने जायेंगे । स्तम्भ 3 और 6 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट सहनसीमा से 0.25 प्रतिशत अधिक तक अनुज्ञेय है ।

नमी :—निर्दिष्ट सीमा से आगे नमी के लिए 0.5 प्रतिशत सहनसीमा अनुज्ञेय होगी । कतरी हुई मिर्च से ऐसी मिर्च अभिप्रेत है जिनके डंठल मूल से ही कतरे हुए हों किन्तु जिनमें कैलिकस हों ।

[सं० फा० 13-1/70-एल० ए०]

आर० सुब्रह्मण्यम्, अवर सचिव ।

**MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT**

(Transport Wing)

MERCHANT SHIPPING

*New Delhi, the 23rd July 1970*

**S.O. 2580.**—In pursuance of clause (a) of Sub-Section (1) of Section 283 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), the Central Government hereby declares that the Governments of Nauru, Hungary, Monaco and Senegal have accepted the Safety Convention as defined in clause (37) of the Section 3 of the said Act, that is to say, the Convention for the Safety of Life at Sea signed in London on the seventeenth day of June, Nineteen Hundred and Sixty, as amended from time to time.

[No. F. 46-MA(1)570.]

[No. F. 46-MA(1)/570.]

**पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय**

(परिवहन पक्ष)

(व्यापारिक पोतपरिवहन)

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1970

सां. निं० 2580—व्यापारिक पोतपरिवहन अधिनियम, 1958 (1958 क 44) की धारा 283 की उपधारा (1) के खंड (क) का अनुसरण करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि नीरू, हंगरी, मोनाको और सेनीगल सरकारों ने उक्त अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (37) में यथा परिभाषित रक्षा संगमन अर्थात् सवह जून उन्नीस सौ साठ को लंदन में हस्ताक्षरित समुद्र में जीवनरक्षा के लिए संगमन समय समय पर यथा संशोधित, को स्वीकार कर लिया है।

[सं. मि० 46 एम० ए० (1)/70.]

एच० सी० कक्कड़, अधीक्षक सचिव।

**MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS**

(Department of Industrial Development)

(Indian Standards Institution)

*New Delhi, the 20th July 1970*

**S.O. 2581.**—In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulation 1955, as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that the licence No. CM/L-495 dated 31-12-1962 particulars of which are given below, has been cancelled with effect from 1 May 1970:—

Licence No. and Date	Name and Address of the licensees	Article/Process covered by the licence cancelled	Relevant Indian Standard
CM/L-495 31-12-1962	M's. Feroke Tile Works, Feroke (Kerala State)	Salt-glazed stoneware pipes and fittings of diameter 100 mm, 150 mm and 300 mm.	IS: 651-1965 Specification for Salt-glazed stoneware pipes and fittings (Second Revision)

[No. CMD 55: 495]

A. K. GUPTA,  
Deputy Director General-

## औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

(भारतीय मानक संस्था)

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 1970

एत० क्र० 2581.—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955, के विनियम 14 के उपविनियम (4) के अनुसरणार्थ भारतीय मानक संस्था द्वारा सूचित किया जाता है कि लाइसेंस सं० सी एम/एल-495, दिनांक 31-12-1962 जिसके व्योरे नीचे दिए हैं, 1 मई 1970 से रद्द कर दिया गया है :—

लाइसेंस सं० और तारीख	लाइसेंस धारी का नाम और पता	रद्द किए लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया	तत्सम्बन्धी भारतीय मानक
सी एम०/एल-495 31-12-1962	मेसर्स फीरोक टाइल वर्क्स फीरोक (केरल राज्य)	100 मि मी, 150 मि मी और 300 मि मी व्यास के लवण-कांचाम पत्थर सामग्री के पाइप और फिटिंग और फिटिंग	IS: 651-1965 लवण कांचाम पत्थर सामग्री के पाइप और फिटिंग (दूसरा पुनरीक्षण)

[सं० सी एम 31/55:495]

ए० के० गुप्ता,

उप० हानिदेशक ।

(Deptt. of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 24th July 1970

**S.O.2582/RLIUR/18/1.**—In pursuance of rule 18 of the Registration & Licensing of Industrial Undertakings Rules, 1952, and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development and Company Affairs No. S.O. 276, RLIUR/18/1 dated the 8th January, 1968, the Central Advisory Council of Industries hereby constitutes the Reviewing Sub-Committee till the 4th March, 1972, consisting of the following members, namely :—

1. Shri Dev Kant Barooah	Chairman
2. Shri D. C. Kothari	Member
3. Shri Keshub Mahindra	Member
4. Shri S. M. Dahanukar	Member
5. Shri A. E. Faizullahoy	Member
6. Shri A. Sivasailam	Member
7. Shri K. N. Modi	Member
8. Shri G. B. Newalkar	Member
9. Dr. S. M. Patil	Member
10. Shri Pravinchandra V. Gandhi	Member
11. Shri M. N. Dastur	Member
12. Shri Basheer Ahmed Sayeed	Member
13. Shri G. Ramanujam	Member
14. Shri A. N. Buch	Member
15. Shri Kanti Mehta	Member
16. Shri Kanwar Lal Gupta, M.P.	Member
17. Shri Mahesh Desai	Member
18. Shri S. S. Mirajkar	Member

2. The functions of the Sub-Committee will be to review all licences issued, refused, varied, amended or revoked from time to time and to advise Government on the general principles to be followed in the issue of licences for establishing new undertakings or substantial expansion of the existing undertakings

[No. 11(1)/Lic.Pol./70.]

R. C. SETHI, Under Secy.

### (प्रौद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1970

एन० ओ० 2582.—आर एन आई यू आर/ 18/1—प्रौद्योगिक उपक्रमों का पंजीयन तथा लाइसेंसोकरण नियम, 1952 के नियम 18 का अनुसरण करते हुए तथा भारत सरकार के प्रौद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय के आदेश सं० एस० ओ० 276/आर एन आई यू आर/ 18/1, दिनांक 8 जनवरी, 1968 का अतिक्रमण करते हुए, उद्योग की केन्द्रीय सालाहकार परिषद् एन्ड द्वारा 4 मार्च, 1972 तक समीक्षा करने के लिए एक उप-समिति गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थातः—

1. श्री देवकांत बरुआ	अध्यक्ष
2. श्री डी० सी० कोठारी	सदस्य
3. श्री केशव महीन्द्रा	सदस्य
4. श्री एस० एम० दहनुकर	सदस्य
5. श्री ए० ई० फैजजुल्लाभाय	सदस्य
6. श्री ए० शिवशैलम	सदस्य
7. श्री के० एन० मोदी	सदस्य
8. श्री जी० बी० नेवलकर	सदस्य
9. डा० एस० एम० पाटिल	सदस्य
10. श्री प्रवीण चन्द्र वी० गांधी	सदस्य
11. श्री एम० एन० दस्तूर	सदस्य
12. श्री बशीर अहमद मईद	सदस्य
13. श्री जी० रामानुज	सदस्य
14. श्री ए० एन० बुच	सदस्य
15. श्री कांति मेहता	सदस्य
16. श्री कंवर लाल गुप्त, संसद सदस्य	सदस्य
17. श्री महेश देसाई	सदस्य
18. श्री एम० एस० मिराजकर	सदस्य

2. उप-समिति का कार्य समय समय पर जारी किये गये, अस्वीकृत, परिवर्धित संशोधन अध्याय प्रतिबंधित सभी लाइसेंसों की समीक्षा करना तथा नए प्रौद्योगिक उपक्रम स्थापित करने अथवा विद्यमान उपक्रमों का पर्याप्त विस्तार करने हेतु लाइसेंस जारी करने के मामले में सामान्य सिद्धान्तों को अपनाने के लिए सरकार को परामर्श देना होगा।

[सं० 11 (1)/एन पी/70)]

आर० सी० सेठी, अवर सचिव।

**MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION****(Department of Labour and Employment)***New Delhi, the 18th July 1970*

**S.O. 2583.**—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal, Madras, in the industrial dispute between the employers in relation to Messrs Kay Corporation, Madras and their workmen, which was received by the Central Government on the 8th July, 1970.

**BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, MADRAS.**

Thursday the 18th day of June 1970

**PRESENT:**

Thiru S. Swamikkannu, B.Sc., M.L., Industrial Tribunal, Madras.

**INDUSTRIAL DISPUTE No. 82 OF 1968**

[In the matter of the dispute for adjudication U/s. 10(1)(d) of the I.D. Act 1947 between the workmen and the management of M/s. Kay Corporation, Madras]

**BETWEEN:**

The General Secretary, Madras Port and Dock Workers Congress, 11, Phillips St., Madras.

**AND**

The Management of M/s. Kay Corporation, Basin Bridge Power House (MES). Madras-12.

**REFERENCE:**

Order No. 29(36)/68-LRIII dated the 16th September 1968 of the Ministry of Labour, Employment & Rehabilitation, (Department of Labour & Employment), Government of India, New Delhi.

This dispute having advanced to this day for final disposal upon perusing the reference, claim and counter statements and all other material papers on record and upon hearing the arguments of Thiruvalargal G. Venkataraman and A. L. Somayajee, Advocates appearing for the workmen and of Thiru V. G. Swaminathan Advocate, appearing for the Management and the parties having filed a memo of compromise and recording the same, this Tribunal made the following.

**AWARD**

This is a reference received from the Central Government in respect of an industrial dispute between the employers in relation to Messrs. Kay Corporation, Madras and their workmen in respect of the dismissal of Shri Devarajan and Bagianathan.

2. The workmen of Messrs. Kay Corporation, represented by the General Secretary, Madras Port and Dock Workers' Congress filed the claim statement on 17th December, 1968 in reply to which the management filed their counter statement on 18th March, 1969.

3. The workmen examined W.W-1 on their side and marked Exs. W-1 to W-8. On the side of the management, Exs. M-1 to M-26(a) were marked.

4. The dispute was advanced at the request of both sides to this day. The parties file a memorandum of compromise. Recorded. An award is passed in terms of the compromise. The terms of the compromise shall be an annexure to the award.

(Sd.) Illegible.

Industrial Tribunal.

**List of Witnesses Examined:****For Workmen:**

W.W-1 Thiru S. Devarajan.

**For management; None.**

*List of Documents Marked:*

*For Workmen:*

- W-1 10-2-68 Notice given by the union to the management U/s. 22(1) of the I.D. Act 1947.
- W-2 10-2-68 Letter from the management to W.W-1 about his behaviour on 9/2/68.
- W-3 15-2-68 Lay of notice.
- W-4 24-2-68 Dismissal order issued to W.W-1.
- W-5 29-2-68 Suspension order issued to Thiru Baglanathan.
- W-6 24-2-68 Letter from W.W-1 to the management requesting for enquiry proceedings.
- W-7 11-2-68 Letter by one Thiru T. Murugesan, Cleaner, to the general secretary, INTUC.
- W-8 12-2-68 Letter by one Thiru Elumalai to the general secretary, INTUC.

*For management:*

- M-1 11-4-66 Letter from National Transport Co., to Devaraj, Driver.
- M-2 13-12-66 Letter & certificate of posting from Kay Corporation to Devaraj.
- M-3 13-12-66 Letter from M.P.D.W. Congress to the Asstt. Labour Commissioner(C) Vepery, Madras 7.
- M-4 14-12-66 Letter from Regional Labour Commissioner to N.T. Co. & MPDW. Congress.
- M-5 16-12-66 Letter from Devaraj to management
- M-6 10-2-68 Letter from management to Devaraj.
- M-7 10-2-68 Charter of demands.
- M-8 19-2-68 Letter with acknowledgment & certificate of posting from management to Union.
- M-8a Postal acknowledgment.
- M-8b Signature of one Thiru Munirathinam [in Ex. M-8(a).]
- M-9 17-2-68 Record of the enquiry.
- M-10 Findings of the Enquiry Officer.
- M-11 22-2-68 Letter copy from management to Devaraj.
- M-12 9-3-68 Complaint from Devaraj to the R.L. Commissioner.
- M-13 7-5-68 Letter from Kay Corporation to Devaraj.
- M-14 7-5-68 Petition from Kay Corporation to R.L. Commissioner.
- M-15 21-5-68 } Letter from Devaraj to Kay Corporation and cheque to Devaraj.  
7-5-68 }
- M-16 16-5-68 Letter from Assistant Labour Commissioner to Kay Corporation & Devaraj.
- M-17 17-5-68 Decision of the Assistant Labour Commissioner(C).
- M-18 22-5-68 Proceedings of the Assistant Labour Commissioner.
- M-19 16-7-68 Letter from Ministry of Labour and Rehabilitation to M.P.D.W.C. and Kay Corporation and N.T. Co.
- M-20 29-2-68 Letter from Kay Corporation to Baglanathan.
- M-21 8-3-68 Evidence.
- M-22 9-3-68 Findings by Presiding Officer.
- M-23 6-4-68 Petition from Kay Corporation.
- M-24 29/30-5-68 Decision of the Assistant Labour Commissioner.
- M-25 5-4-68 Petition from Kay Corporation to Regional Labour Commissioner (Central).
- M-26 6-6-68 Memo of workmen.
- M-26(a) The signature of one Thiru Munirathinam in Ex. M-26.

*Memo of Compromise*

1. In view of the fact that management offers Rs. 2000/- to Sri Devarajan and Rs. 600/- to Sri Baglanathan whose dismissals are the subject matter of the Industrial Dispute and the Union agrees to receive, the amount offered by the management and give up all claims against the management, the Industrial Dispute is reported as settled out of Court. Sri Devarajan and Sri Baglanathan also give up the right of reinstatement in the respondent company.

2. The parties hereto pray that this compromise memo may be published along with the award, as part of the award.

Dated at Madras on this the 18th day of June 1970.

(Sd.) S. M. NARAYANAN,  
For Madras Port and Dock  
Workers Congress.

(Sd.) S. M. NARAYANAN,  
General Secretary.

(Sd.) G. VENKATARAMAN,  
Counsel for Union.

(Sd.) For management  
Respondent.  
Manager.

(Sd.) V. G. SWAMINATHAN,  
Counsel for Management.

NOTE.—The parties are directed to take return of their document/documents within six months from the date of the award.

[No. 29/36/68-LR. III/P&D.]  
C. RAMDAS, Dy. Secy.

### (Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 22nd July 1970

**S.O. 2584.**—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal (No. 3), Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Lodna Colliery (New Sandard) of Messrs Madhavji K. Varma and Sons Private Limited, Post Office Jharia, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 14th July, 1970.

#### CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 3) AT DHANBAD

REFERENCE No. 82 of 1968

#### PARTIES:

Shri Sachidanand Sinha, M.A.M.L., Presiding Officer.

#### PARTIES:

Employers in relation to the Lodna Colliery.

Vs.

Their workmen.

#### APPEARANCES:

*For employers.*—1. Shri Balal Chandra Ghose, on behalf of Sri K. C. Mukherjee and N. S. Lodna Colliery Co. Ltd.

2. None Appeared on behalf of M/s. Madhavji K. Varma & Sons.

*For workmen.*—Sri P. Burman, Secretary, Khan Mazdoor Congress.

INDUSTRY: Coal

STATE: Bihar

Dhanbad, Dated the 30th June, 1970

#### AWARD

1. The Central Government, being of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Lodna Colliery of New Standard Company Private Ltd., Post Office Jharia, District Dhanbad and their workmen, by its order No. 2/117/66-LRII dated the 23rd of January, 1967 referred to the Central Government Industrial Tribunal. Dhanbad under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication the dispute in respect of the matters specified in the Schedule annexed thereto. The Schedule is extracted below:—

#### SCHEDULE

“Whether the dismissal of Shri Satya Gopal Choudhury by the management of Lodna Colliery (New Standard) of Messrs Madhavji K. Varma and Sons Private Limited with effect from the 18th July, 1964, was an act of victimization. If so, to what relief is the workman entitled?”

2. The Central Government Industrial Tribunal, Dhanbad registered the reference as reference No. 13 of 1967. While the proceeding was pending there, the Central Government transferred the dispute to the Central Government Industrial Tribunal (No. 2) Dhanbad, by its order No. 8/25/67-LRII dated the 8th of May, 1967 and there it was registered as reference No. 211 of 1967. The Central Government, by its subsequent order No. 8/71/68-LRII dated the 13th of August, 1968 transferred the dispute to this Tribunal and here it has been re-numbered as reference No. 82 of 1968.

3. The General Secretary, Khan Mazdoor Congress filed written statement on 30th September, 1967. In the order of reference the Manager, Lodna Colliery of New Standard Co. (P) Ltd. was impleaded as party. On 17th December, 1968 the union filed a petition to the effect that from the very notification of the reference it shall be obvious that in addition to New Standard Coal Co. (P) Ltd., which is owner of Lodna Colliery, M/s. Madhavji K. Varma & Sons (P) Ltd., who was the then management of the colliery and in that capacity dismissed the concerned workman, also stands in the position of the employer, in relation to the present dispute. It was further submitted that, besides New Standard Coal Co. (P) Ltd. and M/s. Madhavji K. Varma & Sons (P) Ltd., the Special Officer, Sri K. C. Mukherjee, also stand in the position of employers *vis-a-vis* Lodna Colliery in relation to the dispute under reference. On these grounds they submitted that for the purpose of full enquiry into the subject matter of dispute, and in order to give full and comprehensive finding on the subject of reference, and also to give appropriate relief, it is necessary that Madhavji K. Varma & Sons (P) Ltd. and Special Officer Shri K. C. Mukherjee, should be joined as necessary parties in the present dispute, on the side of the employers.

4. Parties were heard on this point. By order dated 21st of July, 1969 I held that in addition to New Standard Coal Co. (P) Ltd., M/s. Madhavji K. Varma & Sons (P) Ltd. and the Special Officer Sri K. C. Mukherjee should also be joined as necessary parties in the present reference on the side of the employers and they may file additional written statement, if they so desire.

5. The General Secretary, Khan Mazdoor Congress filed amended written statement on 25th June, 1969. Their case is that the concerned workman worked as an overman at Lodna Colliery of New Standard Coal Co. (P) Ltd., for more than 21 years with a fair service record. Due to the mismanagement of the then Board of Director of the Company the working of the colliery suffered greatly, and on an application by some of the Directors of the Co. the High Court of Calcutta appointed in October, 1963 Sri K. C. Mukherjee as a Special Officer of New Standard Coal Co. to superintend the said Co., on its behalf, under the instruction of the High Court. Sri K. C. Mukherjee with the permission of the High Court, entered into an agreement on 11th February, 1964 with M/s. Madhavji K. Varma Co. (P) Ltd. for the running of Lodna Colliery. According to the agreement, the New Standard Coal Co. while retaining the sole ownership of Lodna Colliery, handed over the possession of the colliery to Madhavji K. Varma Co. on and from 11th February, 1964, on certain terms.

6. After the management of Lodna Colliery changed hand from New Standard Coal Co. to Madhavji K. Varma and Co., both the companies in connivance with the each other, began to drive out hundreds of old employees of the colliery, with the intention of depriving them of huge amount of arrears of wages due to them, approximately exceeding four lakhs of rupees.

7. On 8th December, 1963 Sri C. M. Varma one of the Director of M/s. Madhavji K. Varma & Sons (P) Ltd. who was acting as a caretaker on behalf of the Special Officer, dismissed Sri Satyagopal Choudhury from service on false, baseless and frivolous allegation for which the union known as Khan Mazdoor Congress raised the industrial dispute, which however, entered into an agreement dated 29th May, 1964 and in the said agreement the management agreed to reinstate Sri Satyagopal Choudhury with effect from 1st June, 1964 and the period of his enforced idleness from 8th December, 1963 to 31st May, 1964 was to be counted towards continuity of service and he was to be paid 50 per cent of the normal wages for the period of the enforced idleness on 15th June, 1964. Despite the agreement arrived at between the employers and the workmen referred to above the employers did not pay his back wages as agreed upon, and in order to avoid payment M/s. Madhavji K. Varma & Sons (P) Ltd issued a charge sheet against the workman containing various false, baseless, and frivolous charges therein and suspended the workman with immediate effect. The workmen replied to the charge sheet and requested the management to hold the enquiry in presence of the Conciliation

Officer, Dhanbad or any officer of the Labour Department at R.L.C. Office, as there was reign of terror and assault in the colliery and there was danger to the life of the workman from the side of the management.

8. By letter dated the 14th July, 1964, purported to have been issued by Sri C. M. Varma, Director of M/s. Madhavji K. Varma & Sons (P) Ltd. the workman came to learn that there was a departmental enquiry held in the absence of the workman on 4th July, 1964, and the alleged misconduct mentioned in the charge-sheet has been investigated and the workman stand dismissed with effect from 16th July, 1964.

9. According to the workman he did not receive any notice of enquiry and the alleged enquiry on 4th July, 1964 is nothing but a sham transaction held behind the back of the workman and not binding on him, in as much as, the workman could not get opportunity to defend himself and prove his innocence by reason of which the workman is seriously prejudiced and put to irreparable loss.

10. The Union therefore, raised an industrial dispute regarding illegal and unjustified dismissal of the workman by its letter dated 4th September, 1964 but the Assistant Labour Commissioner did not proceed with the case as Madhavji K. Varma Co. had filed an application before the Industrial Tribunal under section 33(2)(1) of the Industrial Disputes Act and the said application was registered as application No. 46 of 1964 dated 7th September, 1964. On the date of hearing the lawyer for Madhavji K. Varma Co. conceded to the point that the said application is not maintainable in view of the fact that Sri Satyagopal Choudhury was not a workman concerned in the dispute, and they do not want to proceed with the case, and do not want any adjudication. As such the legality or illegality of the dismissal of the workman was not determined by the Tribunal. The conciliation proceeding was thereafter taken up by the Assistant Labour Commissioner on a fresh representation by the union, challenging the dismissal of the workman. The management of the colliery filed the application under section 33(2)(1) of the Industrial Disputes Act, 1947 with the sole purpose delaying the conciliation proceeding before the Assistant Labour Commissioner, and to harass the workman.

11. The management of the colliery let loose reign of terror in the colliery, directed against all the old employees of the colliery; and the workman not knowing the date, time and place of the enquiry, had not opportunity to defend his case in the enquiry, alleged to have been held on 4th July, 1964. While the proceeding before the Tribunal and the Assistant Labour Commissioner, had been pending the High Court of Calcutta by a fresh order dated 25th August, 1964 directed Madhavji K. Varma Co. to hand over the possession of the colliery to the Special Officer, and by same order, placed the colliery under the joint management of the Special Officer and Madhavji K. Varma Co. Accordingly the Special Officer took over the possession of the colliery and entered into its joint management with Madhavji K. Varma Co. from 25th August, 1964. While the proceeding on the present dispute had been pending before the Tribunal, the High Court at Calcutta, by another recent order dated 13th February, 1968 entrusted the sole management of Lodna Colliery, to the Special Officer, and Sri P. Basu, one of the Directors of the New Standard Coal Co., and Madhavji K. Varma was divested of all power and responsibility of management of the colliery by the same order. Throughout these diverse proceedings from October, 1963 to the present time the New Standard Coal Co. (P) Ltd. has all along remained the sole owner of the Lodna Colliery.

12. The concerned workman was a member of the executive committee of Lodna Branch of Khan Mazdoor Congress. The dismissal of the workman is unjustified, illegal and *ab-initio* void. The dismissal of the concerned workman is also against the principles of natural justice. The dismissal of the workman is pure and simple an act of victimisation and unfair labour practice. The workman therefore, prayed that the dismissal order of the management be set aside and the workman be reinstated in his job with full back wages and adequate compensation.

13. The employers in relation to the Lodna Colliery of M/s. N. S. Lodna Colliery Co. hereinafter referred to as Coal Co. filed written statement on 31st October, 1968. In their written statement they alleged *inter alia* that the Coal Company though the owner of the property known as the New Standard Lodna Colliery, is not concerned in the present reference as the management of the colliery, at the relevant time, was vested in M/s. Madhavji K. Varma & Sons (P) Ltd. hereinafter referred to as the Varma Company. The workman concerned had been dismissed by the Varma Company, which was then his employer. There was never any dispute between the Coal Company and its workmen in the matter of the dismissal of the workman who was in fact, dismissed, by the Varma Company.

14. The management of the colliery was transferred by an agreement under the orders of the Calcutta High Court to the Varma Company from 11th February, 1964. The Varma Company continued to be in the management of the colliery till 13th February, 1968 when, in pursuance of another order of the Division Bench of the Calcutta High Court, it ceased to be in the management of the colliery. Therefore, according to the Coal Co. they were wrongly made a party to the present reference and the workman is not entitled to any claim from them.

15. The Coal Company had not dismissed the concerned workman. The workman had admitted that he was dismissed by the Varma Co. and therefore, there is no question of his being victimised by the Coal Company. According to the Coal Co. there was no industrial dispute between the Coal Company and its workmen with the result that the present reference and the proceedings *vis-a-vis* the Coal Company are bad in law and therefore, outside its jurisdiction to entertain them. The Coal Company has neither dismissed nor victimised the concerned workman and therefore, the concerned workman cannot claim any relief from it even if his dismissal by the Varma Company is held to be an act of victimisation.

16. The Coal Company has filed rejoinder on 19th March, 1969. In their rejoinder they have reiterated the point that the Varma Company were at the relevant time, i.e. on 16th July, 1964, was in complete possession and management of the colliery and in their own rights. On the 4th of July, 1964 the Varmas, as stated earlier, were in the management and control of the colliery. The Coal Company had no concern whatsoever in the matter of the alleged application under section 33(2)(1) of the Industrial Disputes Act, 1947 which had been made and then withdrawn by the Varmas as the employers of the workman concerned. Prior to 25th August, 1964 the Varmas were solely and entirely in the possession, control and management of the colliery. In the circumstances, the Company is not, in any manner, responsible for the dismissal of Sri Satya Gopal Chaudhury who was dismissed by the Varmas with effect from 16th July, 1964. The New Standard Lodna Colliery was owned by M/s. New Standard Coal Co. (P) Ltd. the Varmas had been solely and entirely in the possession, control and management of the colliery not only at the relevant time, i.e. on 16th July, 1964 but also for a considerable period thereafter. Therefore, since the Company was not in the possession, control and management of the colliery, when Sri Satyagopal Choudhury was dismissed by the Varmas, he cannot claim employment or any other relief as a matter of right from or under the Company.

17. It was again reiterated that even if the Tribunal holds that the action of the Varmas in dismissing Sri Satya Gopal Choudhury by its order was an act of victimisation, he can have no claim to be automatically retained in the service of M/s. New Standard Coal Co. (P) Ltd. on the re-transfer of the management of the colliery from the Varmas and consequently no relief can, in law, be awarded to him as against M/s. New Standard Coal Co. (P) Ltd.

18. Sri K. C. Mukherjee, Special Officer, New Standard Coal Company (P) Ltd. filed the written statement on 19th February, 1969. In their written statement they alleged *inter alia* that Sri Satyagopal Choudhury was dismissed from service on 16th July, 1964 when Madhavji K. Varma & Sons (P) Ltd. were in absolute contract and charge of the colliery, and that he had nothing to do with the dismissal of the workman. The said workman was chargesheeted and dismissed by Madhavji K. Varma & Sons (P) Ltd.

19. The Varma Co. filed their written statement on 25th February, 1969. The Varma Co. in their written statement alleged *inter alia* that by virtue of an agreement for lease dated 11th February, 1964, the charge, possession and management of the said colliery was given to M/s. Madhavji K. Varma & Sons (P) Ltd. But the lease dated 11th of February, 1964 was declared illegal by the Calcutta High Court by order dated the 25th August, 1964. Therefore, during the period from 11th of February, 1964 till 25th August, 1964 the Varma Company was in illegal possession and management of the said colliery and that during this period also for all practical and legal purposes the management would be considered to be that of Mr. K. C. Mukherjee, the Special Officer appointed by the High Court and any act committed by M/s. Madhavji K. Varma & Sons (P) Ltd. would be considered as an act of commission by the Special Officer.

20. The Varma Company had to work as joint Managers under the Special Officer in terms of the said order dated 25th August, 1964 but on 13th February, 1968 by order of the Calcutta High Court, the management of Lodna Colliery was

entrusted to Sri Pradip Basu one of the Directors of the New Standard Coal Co. (P) Ltd. Accordingly they prayed that they should not be directed to participate in the present proceeding because any award if given in favour of the workman for reinstatement, the Varma Company shall not be able to implement the same since they are completely out of the management, administration and control of the Lodna Colliery and therefore, they prayed that the Varma Company be expunged from the terms of this reference.

21. On behalf of the workman two witnesses were examined *viz.* WW-1 Sri Gopal Chandra Munshi, General Secretary of Khan Mazdoor Congress and WW-2 Sri Satyagopal Choudhury, the concerned workman and 13 items of documents were also exhibited on behalf of the workman and they are marked Ext. W-1 to W-13. One witness was examined on behalf of the management *viz.* MW-1 Sri A. N. Sarkar. He has simply proved the signature of Sri S. S. Sharma, the enquiring Officer on the enquiry report. Two items of documents have been exhibited on behalf of the management and they are marked Ext. M-1 to M-2.

22. The point for consideration is whether the dismissal of the concerned workman Sri Satyagopal Choudhury with effect from the 16th of July, 1964 by the management was an act of victimization?

23. There are certain admitted facts regarding ownership, management and possession of the Lodna Colliery of M/s. N. S. Lodna Coal Co. (P) Ltd. M/s. New Standard Coal Co. (P) Ltd. is the owner of New Standard Lodna Colliery. Some of the share-holders of the aforesaid company filed application before the High Court at Calcutta under section 30 and 402 of the Company's Act, 1956, complaining about the mismanagement and misappropriation of the Company's property and prayed to take suitable steps for safeguarding the same. In an order passed on 3rd of August, 1963 the Calcutta High Court appointed Sri K. C. Mukherjee, Bar-at-law as the Special Officer to look into the affairs of the said company. Sri K. C. Mukherjee, Special Officer was permitted by the Calcutta High Court to accept the offer of the Varma Company and consequently by an order made on the 7th of February, 1964 leave was given to Sri K. C. Mukherjee, Special Officer, to enter into an agreement for lease of the colliery to Varma Company.

24. On the 5th of May, an application was made by a former director of the company for setting aside the order made on 7th February, 1964. By an order dated 25th August, 1964 the lease dated 11th of February, 1964 was declared illegal because it had contravened certain provisions of the Mineral Concessions Rules, according to which the legal transfer would be that when the transferer seeks proper permission from the appropriate State Government and gets approval from the Central Government under provisions of Rule 37 of the Mineral Concessions Rules and then enters into an agreement with a transferee and hands over possession to them.

25. By an order dated 25th August, 1964, the Calcutta High Court directed M/s. Madhavji K. Varma & Sons (P) Ltd. to hand over possession to Sri K. C. Mukherjee, Special Officer and by the same order four Directors of Madhavji K. Varma & Sons (P) Ltd. were appointed managers to exploit the mines. Therefore, since 25th August, 1964, the colliery was placed under the joint management of the Special Officer and Madhavji K. Varma. Since 25th August, 1964 the Special Officer took over the possession of the colliery and entered into joint management with Madhavji K. Varma & Sons (P) Ltd.

26. By another order dated 13th February, 1968 Sri K. C. Mukherjee, the Special Officer was directed by the Calcutta High Court to hand over possession of the colliery to Sri Pradip Basu one of the agents for working the mines and in pursuance of that direction Sri K. C. Mukherjee, Special Officer handed over the possession of the colliery to Sri Pradip Basu on 13th February, 1968. Therefore, since 13th February, 1968 the sole management of Lodna colliery was entrusted to Sri Pradip Basu one of the Directors of the New Standard Coal Co. and Madhavji K. Varma has been divested of all power and responsibility of management of the colliery.

27. The case of the Coal Co. is that the concerned workman was dismissed from 16th July, 1964 by the Varma Co. and therefore, there is no question of the workman being victimized by the Coal Co. According to the Varma Co. the lease was executed in their favour on the 11th of February, 1964 but by the order of the High Court at Calcutta dated 25th of August, 1964 the lease was declared illegal because it contravened certain provisions of Mineral Concession Rule.

Therefore, the lease being illegal during the period 11th February, 1964 till the 25th of August, 1964 the Varma Co. had not been in the legal possession and therefore, the management of the said colliery must be deemed to be that of Mr. K. C. Mukherjee, Special Officer *vis-a-vis* the Coal Co. In short during this period the Varma Co. was only Agent of the management.

28. Ext. W-1 is an affidavit by one Sri G. C. Munshi on the 23th of June, 1964 in the High Court at Calcutta alleging that the management were creating chaos and terror amongst the old and faithful workers of the colliery and were forcing them out of employment. Ext. W-2 is the letter addressed to the Superintendent of Police, Dhanbad dated 30th June, 1964 by one Sri R. C. Mukherjee, Medical Officer, N. S. Lodna Coal Co. in which it has been alleged that the management is removing the old and permanent workers from their work and creating a reign of terror by appointing large number of goondas and Lathiyats. Ext. W-3 is the another affidavit sworn by Sri Shibu Mahato on 2nd July, 1964 before the Calcutta High Court alleging *inter alia* that the management is forcing out the old workers out of employment. Ext. W-4 is the dismissal letter dated 8th December, 1963 issued by Sri C. M. Varma to the concerned workman Sri Satyagopal Choudhury dismissing him from service from the 8th December, 1963. The Khan Mazdoor Congress took up the case of the concerned workman and a dispute was raised before the Conciliation Officer (V), Dhanbad and in that connection there were a settlement. According to the settlement Sri S. G. Choudhury was to be reinstated with effect from in June, 1964. The period of the idleness from 8th December, 1963 to 31st May, 1964 was to be counted towards his continuity of service and the concerned workman Sri Choudhury was to be paid 50 per cent of his normal wages for the aforesaid idleness period and the payment was agreed to be made by the management on or before the 5th of June, 1964 (vide Ext. W-5.)

29. The concerned workman worked for three weeks and then on 23rd June, 1964 a chargesheet was issued against the concerned workman vide Ext. W-6. The charge was that he received a bribe in official capacity from a person working under him. On 25th June, 1964 the concerned workman replied to the chargesheet denying the charges (vide Ext. W-7). Ext. W-8 to W-11 are the correspondence between the management and Sri S. G. Choudhury, the concerned workman regarding the venue of the enquiry proceeding. According to the management the enquiry was to be held in the colliery office. The concerned workman prayed that the enquiry be held in the office of the R.L.C. in presence of the Conciliation Officer or any other officer of department of Labour. This prayer of the concerned workman was ultimately not granted. Ext. W-13 is the dismissal letter dismissing the concerned workman with effect from 16th of July, 1964 (vide Ext. W-13). According to the concerned workman no enquiry was held and that was he dismissed without holding any enquiry. Accordingly the concerned workman even no *ex parte* enquiry was held. The management has filed their document and they are Ext. M-1 and M-2. Ext. M-1 has got no relevancy with the present case. Ext. M-2 is the enquiry report signed by Sri S. S. Sharma. This enquiry report is proved by one Sri A. N. Sarkar, an employee of the management. He has simply proved the signature of Sri S. S. Sharma, the enquiring Officer. In the cross-examination he admitted that he cannot say about the correctness or otherwise about the statement made in Ext. M-2. He further admitted that Sri Sharma is still in the employment of M/s. N. S. Lodna & Co. In spite of that he was not examined as a witness on the plea that on that date he was appearing in another case.

30. Therefore, in this case the Enquiring Officer Sri S. S. Sharma was not examined though he is in the employment of the management. The report Ext. M-2 is not legally proved as the enquiry officer was not examined. He did not come to the witness box to give his statement on oath and his statement was not tested by cross-examination. It was submitted before me that Sri S. S. Sharma intentionally did not appear as he was not prepared to face the cross-examination. Therefore, Ext. M-2 has not been legally proved. Moreover, Ext. M-2 is not the enquiry proceeding. It does not contain the statement of the witnesses examined by the Enquiring Officer.

31. WW-2 is Sri Satyagopal Choudhury, the concerned workman and in his examination in chief he has narrated his entire case. In the examination in chief he clearly stated that in his case no departmental enquiry was held either in his presence or even in his absence. He further stated that he was victimised because he was taking leading part in the formation of the Khan Mazdoor Congress union in this colliery and he was a leader of the old employees who were dismissed by the new employer M/s. Madhavji K. Varma. His case in chief is practically

unchallenged and only one question was put in the cross-examination for which the concerned workman gave his reply that in his case no departmental enquiry was held by the New Standard Colliery of M/s. Madhavji K. Varma. He further stated in his evidence in chief that he was an office bearer of the union. He was Assistant Secretary and leader of all the old workers who were also dismissed by the new management of M/s. Madhavji K. Varma.

32. I therefore, hold that the dismissal of the concerned workman Sri Satyagopal Choundhury with effect from the 16th July, 1964, was an act of victimization.

33. The next question for consideration is from whom the concerned workman is to get appropriate relief?

34. The Varma Co. were in the management of the colliery from 11th February, 1964 to 25th August, 1964 and the workman was dismissed on 16th July, 1964 by the Varma Co. According to the Union the Varma Co. was acting as an Agent on behalf of the Coal Co. As stated above we find that in this connection an agreement for lease was executed on the 11th of February, 1964 wherein the charge and possession of the said colliery and management was given to M/s. Madhavji K. Varma, & Sons (P) Ltd. But by the order of Calcutta High Court dated 25th of August, 1964 the aforesaid lease dated the 11th of February, 1964 was declared illegal and therefore, during this period 11th of February, 1964 till the 25th of August, 1964 M/s. Madhavji K. Varma was not in legal possession of the management and during this period the management must be deemed to be that of Coal Co. The history of the case shows that throughout the period from October, 1963 to the present time the Coal Company has all along remained the sole owner of the Lodna Colliery and the Varma Co. was in possession for the limited period on behalf of the Coal Co. Therefore, the dismissal order of Sri Satyagopal Choudhury with effect from the 16th of July, 1964 was an act of victimization and he is entitled to be reinstated in his job with full back wages by the employers in relation to the Lodna Colliery of M/s. New Standard Coal Co. referred to above as Coal Co.

35. This is my award. It may be submitted to the Central Government under section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

(Sd.) SACHIDANAND SINHA,

Presiding Officer.

[No. 2/117/66-LRII.]

**S.O. 2585.**—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal (No. 3), Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Balihari Colliery of Messrs Balihari Colliery Company (Private) Limited, Post Office Kusunda, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 14th July, 1970.

**OFFICE OF THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 3 AT DHANBAD**

**REFERENCE No. 5 OF 1969**

**PRESENT:**

Shri Sachidanand Sinha, M.A.M.L., Presiding Officer.

**PARTIES:**

Employers in relation to Balihari Colliery

Vs.

Their workmen.

**APPEARANCES:**

*For Employers*—Sarvasree S. S. Mukherjee and P. K. Bose, Advocates.

*For workmen*—Shri R. Mitra, Secretary, Bihar Koyala Mazdoor Sabha.

**INDUSTRY:** Coal

**STATE:** Bihar.

Dhanbad, dated the 5th July, 1970

Camp: Patna

**AWARD**

1. The Central Government, being of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to Balihari Colliery of Messrs Balihari Colliery Co. (P) Ltd., Post Office Kusunda, District Dhanbad and their workmen, by its order No. 2/250/68-LRII dated the 8th January, 1969 referred to this Tribunal for adjudication the dispute in respect of the matters specified in the schedule annexed thereto. The schedule is extracted below:

**SCHEDULE**

"Whether the management of Balihari Colliery of M/s. Balihari Colliery Company (Private) Limited, Post Office Kusunda, District Dhanbad, was justified in suspending Sarvashri Ghamandi Mahato, Chetlal Mahato, Dahu Bhuia, Bhuneshwar Bhuia, Girdhari Mahato and Manki Sao, Pick Miners, with effect from 22nd November, 1967, and subsequently dismissing them with effect from 20th March, 1968? If not, to what relief are these workmen entitled?"

2. The Secretary, Bihar Koyala Mazdoor Sabha filed written statement on behalf of the workmen, on 22nd July 1969. Their case is that the aforesaid workmen have been working under the management since long as permanent employees.

3. The management issued charge sheets dated 22nd November 1967 to the concerned workmen and the workmen were suspended pending enquiry. After receiving the charge sheets the workmen submitted their reply to the charge sheets on 27th November 1967 denying the charges levelled against them.

4. After receiving the reply of the workmen the management fixed up a date of enquiry on the 5th December 1967 at 9 A.M. for holding the enquiry. The concerned workmen attended the enquiry and participated in the enquiry on that date and the evidence and the statements of the managements witnesses were recorded and the said enquiry was adjourned to 7th December 1967 for further evidence. All the concerned workmen participated in the enquiry on 7th December 1967 and oral and documentary evidence were recorded by the Enquiry Officer.

5. The charges were not proved against the workmen and the enquiry officer submitted his report stating that the charge-sheeted workmen are not guilty of any charge levelled against them.

6. After the lapse of long two months the management issued another letter to the concerned workmen i.e. letter dated 6th February 1968 calling them to appear for the enquiry on 16th February 1968 at 2 p.m. at the Colliery office before an Advocate engaged by them. After receiving the above letter of enquiry, the concerned workmen submitted a joint petition dated 8th February 1968, wherein the workmen pointed out that the enquiry in question had already been completed and that no charge was proved against them and that now the management was trying to prove the charge with a clear motive to get rid of the workmen by any means. They also pointed out that the management kept them suspended illegally for more than 10 days in violation of Standing Order. The management dismissed all the six concerned workmen from their service with effect from 20th March 1968.

7. The concerned workmen are the active trade union workers and their lawful trade union activities are much disliked by the management. On these grounds the Union prayed that the concerned workmen may be reinstated with full back wages.

8. The management filed their written statement on 7th May 1969 and their rejoinder on 19th August 1969. Their case is that the concerned six miners were on duty in the 2nd shift on 21st November 1967. The cage of No. 6 pit was under repair on the above date and the fencing rod was out of order. The cage was unsafe for persons being raised or lowered. The concerned six miners during the 2nd shift of 21st November 1967 entered the defective cage of this pit with a view to go down the mine. When the aforesaid six workmen entered the defective cage, Shri P. N. Singh—the Senior Overman requested them to go down the mine through the cage of No. 5 pit as the cage of No. 6 pit was out of order. The workmen concerned refused to carry out the order of Shri P. N. Singh and Shri P. N. Singh did not allow the cage to be lowered on the ground of safety. The miners concerned came out of the cage and started abusing him in most filthy language and raised their picks, baskets and shovels with an intention to assault him. At the intervention of the stowing-in-charge and others the miners concerned were prevented from causing bodily injuries to Shri P. N. Singh. The miners also threatened to assault Shri P. N. Singh if he happened to go alone outside the Colliery.

9. For the above misconducts, individual chargesheets dated 22nd November 1967 were issued to the miners concerned and they were suspended pending enquiry. The concerned workmen submitted identical replies dated 27th November 1967 denying the charges. A departmental enquiry was held by the then Labour Officer Shri S. R. P. Singh at the Director's office on 5th December 1967 and on subsequent dates in presence of the workmen concerned. The workmen concerned fully participated in the departmental enquiry and they were given full opportunity to cross-examine the management's witnesses and produce witnesses in their defence. But before submitting the report in respect to the above departmental enquiry, Shri S. R. P. Singh the Enquiry Officer resigned from service. The employers by letter dated 6th February 1968 informed the workmen of the above facts and also further informed them that the incomplete enquiry will be continued by Shri B. Joshi, Advocate, Birapur when they will be given further opportunity to defend themselves. 16th February, 1968 was fixed for this further enquiry. The concerned workmen did not participate in the enquiry fixed for 16th February 1968 on some baseless grounds. It was therefore, completed in their absence. The Enquiry Officer on consideration of the enquiry proceedings recorded by the then Enquiry Officer Shri S. R. P. Singh and all the relevant documents and statements, came to the conclusion that the misconducts mentioned against the six miners have been satisfactorily established. The Enquiry Officer submitted his report accordingly. As the misconducts mentioned in the chargesheets dated 22nd November 1967 were satisfactorily established, the workmen concerned were dismissed by letters dated 20th March, 1968 with prior approval of the Director.

10. The suspension of the concerned workmen with effect from 22nd November 1967 pending enquiry, was justified and the delay in finalising the enquiry proceedings was to some extent due to latches of the concerned workmen. The employees were offered wages by the employers for days beyond 10 days of suspension which under some wrong advice they refused to accept. The dismissal of the workmen concerned with effect from 20th March, 1968 was *bonafide* and based on proved misconducts. The workmen, therefore, are not entitled to any relief.

11. The employers denied that the enquiry officer Shri S. R. P. Singh submitted his report holding that the workmen were not guilty or that the charges were not proved against them.

12. On behalf of the management two witnesses were examined viz. MW-1 Shri B. Joshi, Advocate who conducted the departmental enquiry. The management also exhibited 11 items of documents and they were marked Ext. M-1 to M-11. On behalf of the workmen one witness was examined viz. Shri Chetlal Mahato, one of the concerned workmen.

13. The point for consideration is whether the suspension of the concerned six workmen with effect from the 22nd November, 1967 and their dismissal with effect from 20th March, 1968, was justified?

14. On 21st November 1967 Shri P. N. Singh, Senior Overman made a complaint to the manager of the Colliery vide Ext. M-7. He reported that on the 21st November 1967 at about 5-30 p.m. in the second shift the cage of No. 6 pit was under repair as the fencing rod was out of order and as such it was quite unsafe for persons to be raised or lowered through the cage. Therefore, Shri P. N. Singh—Senior Overman instructed the concerned six workmen to go down the

mine through No. 5 pit. But they refused to carry out the instruction of Shri P. N. Singh. On the instance of Shri P. N. Singh the cage was not lowered down. Thereafter the concerned workmen came out of the cage and started abusing him in filthy language and raised picks, baskets and shovels with an intention to assault him. But they were prevented to do so by others who were present there. On the basis of that report (Ext. M-7) individual chargesheets were issued on 22nd November 1967 to the concerned six workmen (Ext. M-1 series). The concerned workmen replied to the chargesheets on 27th November 1967 denying the charges (Ext. M-2 series). Shri S. R. P. Singh was appointed the Enquiry Officer and he issued notice that the departmental enquiry will be held on the 5th December, 1967 (Ext. M-3 series). A departmental enquiry was held by Shri S. R. P. Singh on 5th December 1967. In the enquiry six witnesses were examined on behalf of the management. On behalf of the workmen Shri Ghamandi Mahato was examined. The other five concerned workmen had nothing more to say beyond that which was stated by Shri Ghamandi Mahato and they admitted his statement and in token of that they put their thumb impressions. Besides the concerned workman they also examined six witnesses (vide Ext. M-8 series).

15. According to the management their Labour Officer Shri S. R. P. Singh who conducted the enquiry left the organisation without completing the above enquiry proceedings and without submitting his enquiry report. Therefore, the management issued a fresh notice to the concerned workmen intimating that on 16th February 1968, at 2 p.m. the enquiry will be held by Shri B. Joshi, Advocate, Hirapur, Dhanbad (vide Ext. M-4). The concerned workmen by their letter dated 8th February, 1968 (Ext. M-5) refused to attend the enquiry proceeding on the ground that the enquiry proceeding had already been compelled and that the allegations levelled against them were not established.

16. Shri B. Joshi, held the enquiry on the 16th February, 1968 and submitted his report on the 18th February, 1968 (vide Ext. M-11). He perused the evidence recorded by Shri S. R. P. Singh on behalf of the management. He also perused the statements recorded by the Enquiry Officer Shri S. R. P. Singh, of the six witnesses examined on behalf of the workmen. They had stated that they were not present at six pit top where the alleged incident took place on 22nd November 1967. In short they also did not support the case of the concerned workmen. The Enquiry Officer therefore, came to the conclusion that the concerned workmen committed the misconduct levelled against them. The concerned workmen, therefore, were dismissed with effect from 20th March, 1968 (vide Ext. M-6 series).

17. WW-1 Shri Chetlul Mahato has got nothing to state against the Enquiry Officer Shri S. R. P. Singh. He has stated in his evidence that five or six witnesses appeared on their behalf as their witnesses before the Enquiry Officer and that the Enquiry Officer also recorded the statements of the aforesaid witnesses. But the witnesses examined on behalf of the workmen, have not supported them. The concerned workmen have got no grievances against the Enquiry Officer Shri S. R. P. Singh WW-1 has also stated that they had quarrel with Shri P. N. Singh on account of non-payment of wages according to Wage Board. But Shri P. N. Singh, Senior Overman has no concern with the implementation of the Wage Board. There is no evidence that Shri S. R. P. Singh held them "NOT GUILTY". The Enquiry Officer Shri B. Joshi, in order to give his finding relied on the testimony of the witnesses examined before Shri S. R. P. Singh. No fresh evidence was adduced before Shri B. Joshi. Even according to the workmen they were given the required facilities to defend themselves before Shri S. R. P. Singh.

18. In this case I find that the concerned six workmen were given full opportunity to cross-examine the witnesses. The concerned six workmen also put their testimony before the Enquiry Officer Shri S. R. P. Singh. In this case the Enquiry Officer who recorded the evidence did not submit the report as he left the Organisation. Shri B. Joshi was subsequently appointed as Enquiry Officer and he recorded his findings with reasons for coming to the conclusion.

19. In this case Shri B. Joshi was appointed by the management to complete the enquiry. In the Ananda Bazar Patrika (Pvt.) Ltd. Vs. Their employees reported in 1963 (II) L.L.J. page 429, it was held that it is open to the employer to entrust an enquiry against a workman for his misconduct in the discharge of his duties, to an outsider. There is no rule that the enquiry must be held in every case by an officer of the company and it cannot be said that an enquiry is illegal or void merely because the person who held the enquiry was an outsider and not an officer of the company. In another case of Saran Motors (Pvt.) Ltd., New Delhi Vs. Vishwanath reported in 1964 (II) L.L.J. page 139 it was held that the

person is not disqualified for merely because he is employed by the employer as lawyer to represent him in industrial disputes. It cannot be said that the enquiry officer has a bias in favour of the employer merely because he is the employer's lawyer and was previously engaged by the employer in industrial matters.

20. It is open to the management to place the employee under suspension pending enquiry where the Standing Orders permit such a course. In this case the grievance of the concerned workmen is that they were suspended for more than 10 days which was against the Standing Order. The case of the management is that the delay in finalising the enquiry proceeding is due to laches of the workmen and that they were offered wages of the period of suspension but they refused to accept and this had not been effectively challenged by the workmen.

21. Therefore, in this case I find that the concerned workmen were dismissed after a proper domestic enquiry held in accordance with the rules of natural justice and the conclusion reached by the Enquiry Officer at the enquiry is not perverse.

22. In this view of the evidence discussed above I hold that the management was justified in suspending the concerned workmen with effect from 22nd November, 1967 and subsequently dismissing them with effect from the 20th March, 1968.

23. This is my award. It may be submitted to the Central Government under Section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

(Sd.) SACHIDANAND SINHA,

Presiding Officer.

[No. 2/250/68-LRII.]

**S.O. 2586.**—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Additional Industrial Tribunal, Orissa, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs B. Patnaik Mines (Private) Limited, Barbil and their workmen, which was received by the Central Government on the 13th July, 1970.

#### ADDITIONAL INDUSTRIAL TRIBUNAL, ORISSA, BHUBANESWAR

##### PRESENT:

Shri U. N. Mishra, B.L., Presiding Officer, Additional Industrial Tribunal, Orissa, Bhubaneswar.

INDUSTRIAL DISPUTE CASE No. 3 of 1970

*Dated Bhubaneswar, the 30th June, 1970*

##### BETWEEN

Messrs B. Patnaik Mines (Private) Limited, Barbil—*First Party.*

##### AND

Their workman, Sri Rajendra Prasad Tiwari—*Second Party.*

##### AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) in their Order No. 10/3/70-LR-IV, dated 18th March, 1970, referred the following point to this Tribunal for adjudication.

"Whether the termination of Sri Rajendra Prasad Tiwari, Hospital Assistant in Seremda Hospital, with effect from the 28th November, 1969, by the management of Messrs B. Patnaik Mines (Private) Limited, is justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. Both parties were served with notices.

3. The management after filing written statement, filed a letter, dated 25th May, 1970 to the effect that the worker concerned has received all his dues from the management in full and final settlement of his claims. The worker too filed a petition after filing his written statement that he has collected the amount from the management in full and final settlement of his claims and does not like to proceed with the case.

4. The case was posted for trial. As both parties remained absent, I think under the circumstances, the dispute if any between them has been settled out of court. Hence, a no dispute award is passed. The letter sent by the Management intimating that Sri Rajendra Prasad Tiwari has received his dues in full and final settlement of his claims on 23rd May, 1970 and the letter sent by the worker that he received his dues in full and final settlement of his claims do form part of the award.

(Sd.) U. N. MISRA,

30-6-70,

Presiding Officer,

Additional Industrial Tribunal, Orissa.

Dictated and corrected by me.

(Sd.) U. N. MISRA,

Presiding Officer,

Additional Industrial Tribunal Orissa.

From.—

Sri R. P. Tewari,  
Ex Hospital Assistant  
M/s B. Patnaik Mines (P) Ltd.  
Barbil.

To

The Agent.  
M/s B. Patnaik Mines (P) Ltd.  
Barbil.

Sir,

I have collected all my dues in full and final settlement of my account with you. I therefore withdraw the case pending with the Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Bhubaneswar, in connection with the termination of my service, and instruction to this effect is sent to the Presiding Officer of the said Tribunal.

Thanking you.

Yours faithfully,

(Sd.) R. P. TEWARI.

23-5-70.

Form part of  
the Award.

(Sd.) U. N. MISRA,

Presiding Officer,

30-6-70.

Addl. Industrial Tribunal,  
Orissa, Bhubaneswar.

Cable: CALKALING.

B. PATNAIK MINES (PRIVATE) LTD.

H.O.

33, CHITTARANJAN  
AVENUE,  
Calcutta-12.

Regd. Office:

Tagore Niwas  
Tulsipur, Cuttack.

Mines:

P.O. Barbil, Kenjhar  
Orissa.

Ref. BP/70/2210

Barbil, 25th May 1970.  
By Regd. with A/D.

The Presiding Officer,

Addl. Industrial Tribunal, Orissa.

Bhubaneswar.

Re: Industrial Dispute Case No. 3 of 1970 between M/s. B. Patnaik Mines  
(P) Ltd., and their workers.

Dear Sir,

In this connection we would like to inform you that Sri Rajendra Prasad Tiwari ex-Compounder has collected his full and final settlement on 23rd May 1970 and

has also intimated the undersigned that he will be informing you to withdraw the case in connection with the termination of his service.

Copies of his letter as well as receipt for final settlement is attached. Therefore, we would request you to kindly treat the case as closed.

Thanking you,

Yours faithfully,  
for B. Patnaik Mines (P) Ltd.  
(Sd.) Illegible.  
25-5-70.  
(Agent)

Form part of the Award.

(Sd.) U. N. MISHRA,  
30-6-70.

Presiding Officer,  
Addl. Industrial Tribunal,  
Orissa, Bhubaneswar.

[No. 10/3/70-LR-IV.]

New Delhi, the 25th July 1970

**S.O. 2587.**—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Polipather Clay Mine of Perfect Pottery Company Limited, Jabalpur, and their workmen, which was received by the Central Government on the 20th July, 1970.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,  
JABALPUR.

New Delhi, the 6th July 1970

PRESENT:

Shri M. Chandra, Presiding Officer.

CASE REF. No. CGIT/LC(R) (129) of 1967

PARTIES:

Employers in relation to the Polipather Clay Mine of Perfect Pottery Company Limited, Jabalpur (M.P.)

*Versus:*

Their Workmen represented through the Perfect Pottery Mazdoor Panchayat Ganjipura, Jabalpur (M.P.)

APPEARANCES:

For employers—Sri Suganchand Chordia.

For workmen—None.

INDUSTRY: Clay Mine

DISTRICT: Jabalpur (M.P.)

#### ORDER/AWARD.

On 1st July, 1967 Perfect Pottery Company Limited, Gwarighat Road, Jabalpur closed down their business. On 16th September, 1967 the Government's reference under Sec. 10(1) (d) I.D. Act 1947 by Notification No. 36/29/67-LRI. The reference is as follows:—

"S.O. No. .—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Polipather Clay Mine of Perfect Pottery Company Limited, Jabalpur and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule herto annexed.

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Jabalpur constituted under section 7A of the said Act.

#### SCHEDULE

Whether the employers in relation to the Polipather Clay Mine of Perfect Pottery Company Limited, Jabalpur (Madhya Pradesh) were justified in closing the said mine and retrenching the following 81 workers with effect from the 1st July 1967. If not, to what relief are the workmen entitled?

Sl. No.	Name	Father's name	Ticket No.
1	Shri Ram Prasad	Mansaram	878
2	" Hiralal	Kamla Prasad	788
3	" Baredi	Badka	551
4	" Pardeshi	Bhuli	760
5	" Mannu	Mohan	871
6	" Mohan	Sodhu	880
7	" Fattej	Chhidami	819
8	" Ramesh	Ram Ratan	888
9	" Jageshwar	Ramadhar	900
10	" Kodu	Mool Chand	876
11	" Indrabhan	Ramdeo	910
12	" Mangal	Gajai	963
13	" Bhura	Sukhdeo	754
14	" Rampati	Deo Saran	797
15	" Kunware	Jugga	814
16	" Samna	Sukhdeo	815
17	" Moti Lal	Ram Kumar	867
18	" Houla Bux	Sheikh Md.	700
19	" Samna	Birbal	752
20	" Mithai Lal	Lilloo	757
21	" Shyam	Ramadhin	767
22	" Kandhilal	Sheodin	768
23	" Budai	Gayadin	770
24	" Achche Lal	Mahadeo	771
25	" Sheopal	Sheodhare	776
26	" Ayodhya Prasad	Vasudev	781
27	" Dwarka	Kamla	782
28	" Surajbhan	Ghutku	784
29	" Jodha	Bishram	785
30	" Ramdulare	Harmohan	788
31	" Charan Lal	Sujhalal	789
32	" Chhotelal	Rambas	792
33	" Bakhat Singh	Todar Singh	796
34	" Bharosa	Kallo	809
35	" Ghurai	Mangal	820
36	" Kashi	Mahadeo	832
37	" Hanuman	Ramadhin	841
38	" Jagatdeo	Girdhari	844
39	" Baijnath	Ram Manohar	445
40	" Mahesh	Rameshwar	846
41	" Sukhdeo	Baldeo	848
42	" Bishesar	Sadho	850
43	" Sonelal	Chunnalal	855
44	" Paramlal	H mraj	856
45	" Sukhlal	Mangal	858
46	" Jagdeo	Jodhan	859
47	" Daddilal	Buddha	885
48	" Shyamlal	Tylakco	866
49	" Phool Chand	Kummoo	875
50	" Ramdulare	Buddha	884
51	" Dulchand	Ghasi	887
52	" B. Phod	Baraiya	889
53	" Baboolal	Badri	891

Sl. No.	Name	Father's name	Ticket No.
54	Sbri Raghunath	Kalka	894
55	" Jugga	Danga	895
56	" Ganga Prasad	Sheobalak	899
57	" Ram Lakhan	Mouni	901
58	" Bhura	Sukhlal	905
59	" Pancham Puri	Chhote Puri	906
60	" Surajdin	Devi	907
61	" Mani	Lalla	915
62	" Ramphal	Chunni	916
63	" Vishwanath	Shanker	918
64	" Dasariya	Rama	927
65	" Tikaram	Lukai	957
66	" Bihari	Pusu	964
67	" Munne Singh	Kandhi Singh	1150
68	" Ramesh	Mahadeo	1170
69	" Gouri Shankar	Shikhtoo	1171
70	" Kishori Lal	Jamuna	1172
71	" Ramdhami	Mahabir	1176
72	" Soore	Binte	1181
73	" Murari	Binte	1184
74	" Chunnilal	Dharampal	1185
75	" Lakhenlal	Patiram	1186
76	" Amritlal	Durjan	1187
77	" Awaseri	Murli	1191
78	" Phool Chand	Mandar	1192
79	" Ram Bishal	Ganga Ram	1193
80	" Nanhelal	Jhunni	1196
81	" Teji Lal	Shankar	1197

2. Before this Tribunal the management contended that this Tribunal had no jurisdiction at all to determine the propriety of the closure or the quantum of retrenchment payable to the workmen as a result of the closure. They do not dispute their liability to pay to the workmen such retrenchment compensation as may be ascertained and determined by the appropriate authority i.e. the Labour Court in accordance with law. The employers, on the other hand, alleged that the closure was not a closure of business but an illegal lock-out under the garb of closure.

3. This Tribunal held by its order dated 3rd July 1968 that the terms of reference do not pre-suppose the closure of business as such, that the expression closing of the mine does not necessarily mean the closing of a business and that this Tribunal could consequently go into the question whether the closing of the mine and the retrenchment was an act of a closure or was calculated to be a lock-out.

4. A writ was filed against this order before the Hon'ble High Court. It was held by the Hon'ble High Court that the factum of closure was not left to the Tribunal to consider or decide since the Central Government had assumed a closure as an accomplished fact and had so worded the reference as to leave no scope for ambiguity or controversy. The order of this Tribunal was accordingly quashed and it was held that this Tribunal had no jurisdiction to enquire into the factum of closure on the terms of reference.

5. There is consequently no question of recording any evidence on, or deciding that point. So far as the quantum of retrenchment compensation is concerned that would, as contended by the management, be a matter for ascertainment and determination by the appropriate authority and not by this Tribunal. As observed by the Hon'ble High Court they do not dispute their liability to pay such retrenchment compensation as may be ascertained and determined by the Labour Court. The High Court has also observed that in law the Tribunals have no jurisdiction to question the propriety of closure.

6. The result is that the proceedings before this Tribunal cannot continue being beyond its jurisdiction and are dropped. In the circumstances of this case there is no order as to costs.

(Sd.) M. CHANDRA, Presiding Officer.  
6-7-1970.

[No. 28(29)/67-LR-IV.]

## ORDERS

New Delhi, the 22nd July 1970

**S.O. 2588.**—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Rakhikol Colliery of Messrs Shivax C. Cambata and Company, Limited, Post Office Rakhikol, District Chhindwara (Madhya Pradesh) and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed:

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, constituted under section 7A of the said Act.

### SCHEDULE

- (i) Whether the management of Rakhikol Colliery of Messrs Shivax C. Cambata and Company Limited, Post Office Rakhikol, District Chhindwara is justified in changing the weekly holiday from Sunday to any other day of the week in respect of 250 workmen from August, 1969? If not, to what relief are the workmen entitled?
- (ii) Whether the termination of employment of Shri Babookhan, Loading Mate by the management of Rakhikol Colliery of Messrs Shivax C. Cambata and Company Private Limited, Post Office Rakhikol, District Chhindwara, with effect from 13th March, 1969, is justified? If not, to what relief is he entitled?

[No. 1/8/70-LR.II.1]

### अदेश

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1970

**सं. 2588.**—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैमर्स श्यावक्ष सी० खम्भाटा एण्ड कंपनी, लिमिटेड, डाकघर राखीकोल, जिला छिदवाड़ा (मध्य प्रदेश) की राखीकोल कोयला खान के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

### अनुसूची

(i) क्या मैमर्स श्यावक्ष सी० खम्भाटा एण्ड कंपनी, लिमिटेड, डाकघर राखीकोल, जिला छिदवाड़ा की राखीकोल कोयला खान के प्रबंधन का 250 कर्मचारों के बारे में अगस्त, 1969 से साप्ताहिक अवकाश को रविवार से सप्ताह के किसी अन्य दिन में बदलना न्यायोचित है ? यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार है ?

(ii) क्या मैमर्स श्यावक्ष सी० खम्भाटा एण्ड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, डाकघर राखीकोल, जिला छिदवाड़ा की राखीकोल कोयला खान के प्रबंधन का श्री बाबूखान, लोडिंग मेट के नियोजन को 13 मार्च, 1969 से समाप्त करना न्यायोचित है ? यदि नहीं तो वह किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं. 1/8/70-एल० आर०-II]

New Delhi, the 24th July 1970

**S.O. 2589.**—Whereas an industrial dispute exists between the management of Messers Bikaner Gypsum Limited, Bikaner (hereinafter referred to as the said Company) and their workmen represented by Rashtriya Gypsum Karamchari Sangh, Jamsar (herein after referred to as the said Union);

And whereas the said company and the said Union have, by a written agreement, in pursuance of the provisions of subsection (1) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) agreed to refer the said dispute to arbitration of the person mentioned therein, and a copy of the said arbitration agreement has been forwarded to the Central Government;

Now therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (3) of section 10A of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the said arbitration agreement, which was received by it on the 6th July, 1970.

#### Agreement

(Under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947).

#### BETWEEN

#### Name of Parties:

*Representing employers.*—1. Shri M. N. Roy, Mines Superintendent, Bikaner Gypsums Limited, Bikaner.

2. Shri A. K. Mukherjee, Personnel Manager, Bikaner Gypsums Limited, Bikaner.

*Representing workmen.*—1. Shri Dilbagh Singh, Vice President, Rashtriya Gypsum Karamchari Sangh, Jamsar.

2. Shri Ramzan, Rashtriya Gypsum Karamchari Sangh, Jamsar.

It is hereby agreed between the parties to refer the following industrial dispute to the arbitration of Shri R. D. Goswami, (Personnel Officer, Rajasthan Canal Project, Shivpuri House, Bikaner):

(i) *Specific matters in dispute.*—1. Whether the demand of the workmen represented by Rashtriya Gypsum Karamchari Sangh that the Helpers working in the Workshop of the Company on various machines should be designated as Khalasies in the grade of Rs. 45—2—50—65—EB—5—100 is justified? If so, to what relief are they entitled?

2. Whether the demand of the workers represented by the Rashtriya Gypsum Karamchari Sangh that the Helpers be paid house rent allowance at Rs. 6 per month from 1st October 1967 is justified? If so, to what relief are they entitled?

(ii) *Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved.*—1. Messrs. Bikaner Gypsums Ltd., Jamsar Gypsum Mines, Jamsar.

2. The Rashtriya Gypsum Karamchari Sangh, Jamsar.

(iii) *Name of the Union, if any, representing the workmen in question.*—The Rashtriya Gypsum Karamchari Sangh, Jamsar.

(iv) *Total number of workmen employed in the undertaking effected.*—387 (appx.)

(v) *Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute*—(1) 50  
(2) 80

We further agree that the majority decision of the arbitrators shall be binding on us.

The arbitrator shall make his award within a period of two months or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case the award is not made within the period aforementioned, the reference to arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

Signature of the Parties.

Representing employer:

(Sd.) M. N. Roy, (Sd.) A. K. MUKHERJEE,

Representing workers:

(Sd.) DILBAGH SINGH, (Sd.) RAMZAN,

[No. 30/4/70-LR-IV.]

New Delhi, the 25th July 1970

**S.O. 2590.**—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Dishergarh Office of Messrs. Equitable Coal Company Limited, Post Office Dishergarh, District Burdwan and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, constituted under section 7A of the said Act.

#### SCHEDULE

“Whether the demand of the telephone clerks Grade-II of Dishergarh Office of Messrs. Equitable Coal Company Limited, Post Office Dishergarh, District Burdwan, for Grade I as per Wage Board Recommendations is justified? If so, from what date?

[No. 1/34/70-LRII.]

P. C. MISRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1970

**कां० 2590.**—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मेसर्स इक्विटेबल कोल, कम्पनी, लिमिटेड, डाकघर दिशेरगढ़, जिला बर्दवान के दिशेरगढ़ कार्यालय के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और अतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

#### अनुसूची

“क्या मेसर्स इक्विटेबल कोल कम्पनी, लिमिटेड, डाकघर दिशेरगढ़, जिला बर्दवान के दिशेरगढ़ कार्यालय के टेलीफोन लिपिक, श्रेणी 2 की मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार, श्रेणी 1 की मांग न्यायोचित है ? यदि हां, तो किम तारीख से ?”

[सं० 1/34/70-एल० आर० II.]

पि० सि० मिश्र, अवर सचिव ।

#### (Department of Labour & Employment)

New Delhi, the 23rd July 1970

**S.O. 2591.**—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal, Bombay, in the industrial dispute between the employers in relation to the Skandia Insurance Company Limited, Bombay and their workmen, which was received by the Central Government on the 13th July, 1970.

## BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, BOMBAY

REFERENCE No. CGIT-6 OF 1968

## PARTIES:

Employers in relation to the Skandia Insurance Company Ltd., Bombay.

AND

Their workmen represented by the General Insurance Employees Union, Bombay.

## PRESENT:

Shri A. T. Zambre, Presiding Officer.

## APPEARANCES:

*For the employers.*—Shri H. E. Desai, Advocate.*For the workmen.*—Shri P. S. Mehta, Group Secretary, General Insurance Employees' Union Western Zone, Bombay.

STATE: Maharashtra.

INDUSTRY: General Insurance.

Bombay, dated 24th June 1970

## AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) by their order No. 26/2/68/LR III dated 20th March 1968 have referred to this Tribunal for adjudication an industrial dispute existing between the employers in relation to the Skandia Insurance Company Ltd., Bombay and their workmen represented by the General Insurance Employees' Union, Bombay in respect of the matters specified in the following schedule:—

## SCHEDULE

*Charter or Demands*

All the demands contained herein below shall apply to all the employees employed in Skandia Insurance Co. Ltd., Bombay.

I. *Classification of Employees*

The employees will be classified into the following categories:—

- (a) Sepoy's and Head Peons shall be placed in Grade 'A'.
- (b) Drivers shall be placed in Grade 'B'.
- (c) Record clerks shall be placed in Grade 'C'.
- (d) Assistants, Telephone Operators, Typists, Receiving and Paying Cashiers, Comptometer. Machine Operators shall be placed in Grade 'D'.
- (e) Higher Grade Assistants, Special Assistants, Senior Assistants, Head Typists, Senior Cashiers, Stenographers etc. shall be placed in Grade 'E'.
- (f) Supervisory staff, variously termed as superintendents, Assistant Superintendents, Head Clerks, Sectional Heads, Branch Accounts etc. shall be placed in Grade 'F'.

II. *Scales of Pay*

- Grade A: Rs. 120—5/6—150—6/7—192—8/6—240 in 19 years.  
 Grade B: Rs. 180—6/2—192—8/6—240—10/3—270 in 11 years.  
 Grade C: Rs. 190—8/3—214—10/5—264—12/3—300—15/4—360 in 15 years.  
 Grade D: Rs. 200—10/4—240—15/5—315—20/8—475 in 17 years.  
 Grade E: Rs. 275—15/5—350—20/5—450—23/5—575 in 15 years.  
 Grade F: Rs. 350—30/6—530—40/4—690 in 10 years.

III. *Dearness Allowance*

Dearness allowance shall be paid at the rate of 1½ per cent of the basic pay for every rise of 5 points over the cost of living index figures of 360 (934=100 points) subject to a minimum of Rs. 20. The Bombay working class Consumers Price Index shall be taken as the basis for calculating the Dearness Allowances.

IV. *Adjustment*

An employee shall be fitted into the new scales on a point to point basis. The basic pay and the dearness allowance as on 31st December 1964 shall be treated as basic pay only for the purpose of adjustment of basic pay to the new scale of pay.

If any employee is drawing more basic pay than what is warranted after proper adjustment as above, shall continue to receive the excess amount as personal pay and shall be also given usual annual increments.

V. *Employee engaged in work mentioned below and/or designated as below shall be entitled to Special allowance per mensem in addition to their salaries and emoluments in the manner stated below*

(a) Bank Peons, Despatch Peons, Head Peons, Franking Machine and Duplicating Machine Operators and such other Employees Rs. 20 per month.

(b) Typists, Comptometer Operators, Telephone Operators, Paying and Receiving Cashiers and such other employees Rs. 30 per month.

VI. *Special Increments*

Besides the above the employees under Grade 'D' and 'E' shall be entitled to Special Increments for passing the following examinations on the scale shown against each examination.

On Graduation.—2 Increments.

Licentiate or A.C.I.I. Part I

A.F.I.I. Part I or A.C.I.I. Part II 1 Increment

A.F.I.I. Part I or A.C.I.I. Part III for each part.

Chartered Accountant.

N.B. A graduate appointed as an assistant shall get a higher starting salary by two increments. Those graduates Assistants who have not received the graduation increments shall also get two increments.

VII. *Other Allowances*

A. *Overtime Allowances.*—An employee working overtime shall be entitled to overtime allowance for such period of work rendered at the rate of double the hourly rate of wage inclusive of special allowances and all other allowances. No employee shall be engaged in for overtime work for more than 90 hours in a calendar year.

B. *Officiating Allowance.*—(1) If an employee is required to officiate in a higher post, he shall be entitled to an 'Acting allowance' at the rate of 20 per cent of his salary for the period for which he officiates.

(2) If an employee is required to act in a post for which special pay is provided, he shall be entitled to pro-rata special allowance for the period of such work done.

C. *House Rent Allowance.*—All the employees shall be paid as 'House Rent' a sum at the rate of 10 per cent of their Basic salary per mensem, subject to a minimum of Rs. 20.

VIII. *Amenities*

*Subsidies.*—(1) Text Books for ACII or Federation of Insurance Institute Examination shall be supplied by the Company in turn. Examination fee shall be paid by the employer after the employee passes the examination.

(2) Adequate subsidy shall be given for Sports, Recreation and Cultural Activities of the employees.

(3) All the employees shall be entitled to a Free personal Accident (Annual) policy, the premiums of which shall be borne by the Employees. The sum assured of such a policy shall be Rs. 10,000 Rs. 7,500, Rs. 5,000 and Rs. 2,500 for the employees in Grades F, E, D&C, B and A respectively.

(4) Adequate subsidy shall be given for cheap canteens for supply of wholesome food to the employees in the office premises.

All the employees shall be entitled to free medical aid for selves and their dependants. All the cost of hospitalisation, medicines and doctors' bills shall be borne by the employer.

**IX. Gratuity**

On retirement, or retrenchment or on death or on total permanent disability of an employee while in the service of the Company one month's basic salary for each year of continuous service subject to a maximum of 20 months basic salary.

On resignation from service after completion of 10 years continuous service.

One month's basic salary for each year of continuous service subject to a maximum of 20 months basic salary.

On termination of service by the Company.

One month's basic salary for each completed year of service but not more than 20 months basic salary.

The salary for the purpose of calculating Gratuity shall be the terminal basic salary drawble by the employee previous to death, disablement, retirement, resignation, retrenchment or termination of service as the case may be.

**XI. Provident Fund**

The age of retirement of an employee shall be 60 years.

**XI. Provident Fund**

1. All permanent employees shall be made members of the Provident Fund.

2. The rate of contribution should be 8.1/3 per cent of the total emoluments i.e. basic pay plus dearness allowance plus special allowance, if any, with equal contribution by the company. The employees should however, be allowed to contribute voluntarily up to 15 per cent of their salary without corresponding contribution from the Company.

3. Interest at a minimum rate of 6 per cent should be paid on the total contribution by the employees and the Company.

4. Unclaimed fund should be distributed pro-rata every three years amongst the existing employees from time to time.

5. Full benefits of the Fund should be permitted to the employees on completion of five years of service.

6. Loan from the provident Fund to the extent of 6 months salary or 100 per cent of the employees' contribution whichever is more shall be granted to the employees of a time

On the Board of Provident Fund Trust, the employees and the employers should have equal number of representatives. The employees representatives should be elected by themselves by simple majority of votes. Re-election of the employees' representative should be held every three years unless necessiated earlier by death or resignation or recall by a majority of the employees.

**XII. Leave**

*Casual Leave.*—15 days casual leave should be given in a calendar year. 6 days casual leave may be granted at a stretch. Casual leave may be prefixed and suffixed to holidays and sundays.

*Privilege (Earned) Leave.*—Privilege leave should be allowed to all employees at the rate of 1 day for every 11 calendar days. Employees should be allowed to accumulate leave upto 6 months. Return fare to the employees, his wife and dependents should be granted once in a 2 years for going anywhere in India.

*Sick Leave.*—Thirty days sick leave per year should be allowed on full pay to the employees with a maximum accumulation of 12 months. In case of prolonged illness further sick leave with half pay should be allowed upto 6 months and another 6 months without pay.

*Examination Leave.*—Employees shall be allowed adequate leave for appearing in all the recognised examinations in addition to all other leave.

*Special Leave.*—Adequate leave shall be allowed to the Union Representatives and Office Bearers of the All India Insurance Employees' Association and/or its affiliated Units to enable them to attend the meetings and conferences of the Union and their Central Organisations and to participate in the Tribunals and Conciliation Proceedings.

### XIII. *Security of Services*

No employees shall be victimised for trade Union activities.

### XIV. *Working Hours*

The working hours for employees in Grades C, D, E and F shall be 33 hours a week and 36 hours for employees in Grades A and B. A grace time of 15 minutes shall be allowed before they are marked late.

### XV. *Bonus*

Customary: Employees shall be paid 4 months Gross salary as Bonus per year.

### XVI. *Uniform to Employees in the Grades A and B.*

An employee of Grade A & B shall be provided with the following outfit annually:

1. Summer Uniform Four Sets.
2. Umbrellas One.
3. Footwear Two pairs.
4. Rain Coat, one for those who are to do outdoor duties.

### XVIII. *Recruitment*

Recruitment shall be made from amongst the retrenched employees of the General Insurance Industry, registered in the pool as demanded in the resolution adopted in the All India Convention of General Insurance Employees held on the 15th and 16th August 1960 in Bombay under the auspices of the All India Insurance Employees Association. Only in case such employees are not available in the pool, recruitment might be made through the Local Employment Exchange. In case of recruitment from among the retrenched employees, due credit shall be given to past service and all restrictions regarding educational qualifications etc. applicable to recruits shall be waived.

### XIX. *Confirmation*

Employees shall be confirmed after 3 months probationary service automatically.

### XX. *Temporary Staff*

Company may employ temporary employees performing duties of purely temporary nature. But such staff in no instance shall exceed more than 6 months in temporary service after which he shall be treated automatically in permanent service, from the date of appointment.

### XXI. *Promotions*

No direct recruitment shall be made in Grades C, D, E and F and all vacancies in these Grades shall be filled in by way of promotions shall be made on the basis of seniority and merits of the Employees in grade A & B shall be absorbed in Grade 'D' on passing the S.S.C., S.S.L.C., or equivalent examinations.

### XXII. *Transfers*

No employee shall be transferred from one place to another without his prior written consent.

### XXIII. *Date of Effect*

All benefits stated in this Charter of Demands shall have effect from 1st January, 1965 unless stated otherwise.

### XXIV. *Trade Union Rights*

The All India Insurance Employees Association and its affiliated units shall be given due recognition and such facilities as providing Trade Union Offices and holding Trading Union Meetings in Office Premises and hanging Notice Board of the Union should be granted.

### XXV. *Existing Rights and Privileges*

Nothing contained in this Charter shall adversely effect or take away from any employee or groups of employees any right, privileges or usages practice or conventions, amenities or other conditions of service that are already vested in or enjoyed by such employees or group of employees.

XXVI. *Holidays*

All the holidays come under the purview of the Negotiable Instrument Act should be treated as holidays and the following full and sectional holidays will be observed.

1. Maker Sankrant	— Half day.
2. Ashadi Ekadashi	— Half day.
3. Shravan Mondays	— Half day.
4. Anant Chaturdashi	— Half day.
5. Kartik Ekadashi	— Half day.
6. Mahashivratri	— Full day.
7. Shree Ramnavmi	— Full day.
8. Cocanaut Day	— Full day.
9. Gokul Ashtmi	— Full day.
10. Kali Chaudas	— Full day.
11. Bhai Dhuj	— Full day.
12. Jamshedji Navroz	— Full day.
13. Khordadsal	— Full day.
14. December 24th	— Half day.

3. The employer Company is a branch of the Skandia Insurance Co. Ltd., incorporated in Sweden in the year 1955 and the workers involved are the employees of the Bombay office. The employees are the members of the General Insurance Employees union. The union has by its statement of claim submitted that the service conditions of the employees were very poor and unsatisfactory and after joining the present union which is representative of the employees in the general insurance industry submitted a charter of demands to the company in July 1966. Negotiations were held from time to time but the management, refused to take into consideration the demands. It is alleged that the company is one of the biggest insurers transacting business all over the world and with the backing of tremendous resources, knowledge and experience this company has been able to make an almost enviable progress since its establishment in India in 1957. The union has given a chart of the figures of premium received by the company during the years from 1957 to 1966 and has alleged that the company's business has increased more than 18 times during a span of 9 years but the conditions of the employees have remained abnormally poor. There were no scales, no dearness allowance linked with cost of living index, and no other facilities enjoyed and hence the charter of demands.

3. The company has by its written statement opposed the demands but the proceedings had to be adjourned from time to time for negotiations. On the date of hearing the parties have arrived at a settlement and have filed terms of settlement. Both the parties have also given an application requesting the Tribunal to record the agreement under section 18 read with section 2(p) of the Industrial Disputes Act and pass an award in terms of the same.

4. The terms of settlement will show that the management has accepted the important demands of the workers and the dearness allowance has been linked with the all India consumer price index number base (1949=100) for working class. The agreement is to be brought into effect from 1st July, 1966 and will remain in force upto December 1972. The terms of the settlement are fair and reasonable and I accept the same and pass an award in terms of the settlement annexure 'A' which shall form part of this award.

No order as to costs.

(Sd.) A. T. ZAMBRE,

Presiding Officer,  
Central Government Industrial Tribunal,  
Bombay.

ANNEXURE "A"

*Memorandum of Settlement*

Skandia Insurance Company Limited 159, Churchgate Reclamation Road,  
Bombay—20.

AND

Workmen employed by Skandia Insurance Co., Ltd., In Bombay.

*Representing Employer*—Mr. Dhirubhai A. Shah, Manager, Skandia Insurance Co. Ltd., Industry House, 159, Churchgate Reclamation Road, Bombay—20.

*Representing Workmen*—(1) Mr. P. S. Kulkarni, Acting General Secretary, General Insurance Employees, Union, W. Z. Bombay-1. (2) Mr. P. S. Mehta, Group Secretary of the Skandia Insurance Employees' Group of the General Insurance Employees' Union W. Z. Bombay-1.

*Short Recital of the Case*

The Settlement made this 14th day of March 1970, between the Skandia Insurance Co. Ltd. (hereinafter called the Company) and the Workmen employed by the Company at Bombay represented by the General Secretary, General Insurance Employees' Union, (hereinafter referred to as the Union).

Whereas the Union submitted a Charter of Demands on 1st July 1966 on behalf of the Workmen employed by the Company at its Bombay Office and whereas the said Charter of Demands was referred to adjudication by the Government to the Industrial Tribunal and was marked as reference No. CGIT No. 6 of 1968 and whereas pursuant to the negotiations for settlement of the Demands contained in the said "Charter of Demands" parties have arrived at the following settlement to the intent that will be binding on the parties under Sec. 18 and read with 2 (p) of the Industrial Disputes Act, 1947

IT IS HEREBY AGREED BY AND BETWEEN THE PARTIES HERETO AS  
UNDER:

1. *Commencement and scope of the settlement*—

This settlement will apply with effect from 1st July 1966 to the Workmen employed by the Company at Bombay Office save & except where it is stated otherwise.

2. *Salary Scales*.—The following scales of pay shall be introduced by the Company at its Bombay Office.

- (a) Senior Assistants (including Sectional Heads, Accountants and Head Cashier—200-12½-250-15-340-E.B. 20-500 (in 18 years.)
- (b) Assistants (Clerks including Typists, Telephone Operator, & Cashier—150-8-198-10-258-12-330 E.B. 15-435 (in 25 years.)
- (c) Stenographers and Stenotypists—174-8-198-10-258-12-330 E.B. 15-450 (in 23 years.)
- (d) Record Clerks—110-4-138-5-163-8-235 (in 21 years.)
- (e) Drivers—130-5-155-8-195-10-255 (in 16 years.)
- (f) Peons, Watchman—85-3-115-4-135-5-165 (in 21 years.)

2. (i) The following workmen shall be classified in Senior Assistants Grade viz. Grade (a) above—

- (1) Mr. M. K. Jaggad (Marine Department).
- (2) Mr. J. V. Modi (Motor Department).
- (3) Mr. P. H. Shah (Fire Department).
- (4) Mr. S. B. Padwal (Accounts Department).
- (5) Mr. R. S. Chhedda (Head Cashier).

2. (ii) The Existing classification of other workmen into different grades shall continue as it is, till the expiry of this agreement.

*Adjustments.*—(1) The following amounts will be added to the basic pay drawn by the workmen as on 1st January 1967.

- (i) Clerical Staff—Rs. 65/-.
- (ii) Record Clerks—Rs. 50/-.
- (iii) Sub-ordinate Staff and Drivers—Rs. 50/-.

(2) After addition of Rs. 65/- or Rs. 50/- as the case may be in the basic salary of the workmen as mentioned above, the basic salary derived will be fitted in the revised pay scales as per clause 2 above in the following manner:—

- (a) Workmen who would be in receipt of basic salary which is less than the starting basic salary of the respective revised-scales shall be stepped upto the minimum of the revised scale.
- (b) Workmen who would be in receipt of basic salary which is higher than the starting Basic salary of the respective scales but which is not a step in the revised scale shall be stepped upto the next step in the revised scale.
- (c) Workmen who would be in receipt of basic salary which is in step with a step in the revised scale shall be fitted at that step in the scale.
- (d) Similarly amounts will be added to the basic salaries in respect of workmen who were appointed after 1st July 1966 till the date of this Settlement.

3. *Dearness Allowance.*—In place of the existing dearness allowance scheme, the following scheme of dearness allowance will be introduced on the basis of All India Consumer Price Index Number Base (1949=100) for working class is at 170.

Upto basic salary Rs. 100/—Rs. 60/- flat.

Between 101 and 250/—Rs. 60/- + 30% of basic salary over Rs. 100/-.

Between 251/- and 350/—Rs. 105/- + 20% of basic salary over Rs. 250/-.

Between 351/- and 400/—Rs. 125/- + 15% of basic salary over Rs. 350/-.

Between 401/- and 500/—Rs. 132.50 & 10% of basic salary over Rs. 400/-.

Above Rs. 500/—Rs. 142.50.

above Rs. 500 the D.A. will be paid as if monthly basic salary is Rs. 500 i.e. no D.A. is payable on that portion of basic salary over Rs. 500.

It is further agreed that for every rise or fall of one point in the quarterly average index number over or below 170, the D.A. Payable on the basic salary will be increased or decreased as follows:

For the first Rs. 100/- of basic salary—1%

For the balance amount of basic salary upto 500/—1/2%

PROVIDED HOWEVER, that the maximum D.A. payable including the adjustments stated above shall not exceed Rs. 350/- per month.

NOTE.—The D.A. adjustment for any quarter shall be made on the basis of the average of All India C. I. base year 1949 for the quarter last preceding the previous quarter (e.g. adjustment for first quarter of any year shall be on the basis of average of 3rd quarter of previous year). In calculating average index figure, fraction of one-third will be ignored and two-thirds will be considered as one point.

3(A) (i) For the purpose of calculating the arrears in respect of basic salary, D.A. wherever applicable and payable to workmen for the period commencing from 1st January 1967 as specified in Clause 1 hereinabove, the total monthly earnings (excluding over-time) payable under this settlement will be worked out and the total monthly earnings (including the interim relief but excluding over-time if any earned) of the respect workman for the above-mentioned period will be deducted and the balance after making deductions towards Income-tax will be paid to the respective workmen as arrears, payable under this settlement.

3(A)(ii) In view of 3A (i) above it is agreed between the parties that the arrears for the period 1st July 1966 to 31st December 1966 will not be paid separately as the payment of Interim Relief of one month's wages made under the agreement dated 5th January 1968 would be adjusted towards the payment of the arrears for the aforementioned period. In view of the agreement in this behalf the workmen shall not be entitled to the difference payable for the said period and the Company shall not be entitled to recover and/or take into consideration the said payment of one month's wages for the calculation and adjustment of the payment of arrears for the period beginning from 1st January 1967.

3(A)(iii) The Management as a special case has agreed that the workmen who are not entitled to monetary benefits after the introduction of the above scales and D.A. adjustment viz. payment of difference of emoluments does not amount to Rs. 25/- minimum, shall be paid a minimum of Rs. 25/- per month from 1st January 1969. This will be special relief and the said payment shall not be taken into account for payment of D.A. Bonus, Over-time. This special relief is applicable to the present employees only and not to the persons who may be taken in employment after 1st January 1970.

4. *House Rent Allowance*.—This demand is not pressed by the workmen and the Union till the expiry of the period of this agreement.

5. *Special Allowance*.—Special allowance payable to the Head Cashier will be Rs. 25/- per month. Peon carrying Mail to Post Office Rs. 15/- and Typist Rs. 10/-. This allowance will be payable from 1st January 1970.

6. *Special Increments*.—(i) (a) A graduate on enjoining service will be given two special increments at the start in the grade. Double graduates will be given three special increments at the start in the grade. If an existing staff member becomes a graduate he will be given two special increments. If an existing staff member who is a graduate becomes a double graduate he will be given one further special increment in his scale from the month of declaration of the results provided however, that the Company is given intimation in this respect by the workmen concerned.

The following workmen were not given Special Increments and therefore they will be given the Special Increments as stated hereunder:

(a) Mr. M. T. Shah—Two Special Increments in his grade from 1st January 1967.

(b) Mr. B. V. Mehta—One Special Increment in his grade from 1st July 1967.

(c) Mr. S. B. Kotian—One Special Increment in his grade from 1st July 1967.

(i) (b) Typists who are promoted as Stenographers will be entitled to get TWO ADDITIONAL Increments in their grade on their promotion as at present.

(ii) (a) One special increment will be given to workmen passing part I of the Associateship Examination of the Chartered Insurance Institute, London or Licensiate Examination of the Federation of Insurance Institutes (J.C. Setalvad Memorial), Bombay. Graduates and Double Graduates will not be entitled to this increment.

(b) One special increment will be given to workmen (including graduates) passing part II of the Associateship Examination of the Chartered Insurance Institute, London, or part of the Associateship Examination of the Federation of Insurance Institutes (J.C. Setalvad Memorial), Bombay.

(c) One special increment will be given to workmen (including graduates) passing Part III of the Associateship Examination of the Chartered Insurance Institute, London, or part II of the Associateship Examination of the Federation of Insurance Institutes (J.C. Setalvad Memorial), Bombay.

(d) One special increment will be given to workmen, passing the qualifying examination for Fellowship of Insurance Institutes (J.C. Setalvad Memorial), Bombay.

These special increments mentioned in Clause 6(ii) will be given from the month in which the results of the examination are officially declared and according to the grade the workman is in that particular month.

(iii) (a) One special increment will be given to those passing Part I of the following examinations: Corporation of Certified Secretaries, London, Corporation of Accountants, Glasgow and Chartered Accountants Examination, India Graduates, will not be entitled to this increments.

(b) One further special increment will also be given to those passing the above final examinations (i.e. in all two additional increments). Graduates will be entitled to only one increment.

The Special Increments referred to above shall be paid from 1st January 1970.

7. *Annual Increments*.—All permanent workmen shall be given their annual increments on 1st April every year. For the purpose of grant of increments, confirmed service of six months or more as on 1st April shall entitle a workman for the increment on 1st April but a workman who has continuous service of less than 6 months on 1st April of any year will not receive the yearly increment payable on 1st April of the year concerned.

8. *Medical Expenses*.—(i) (a) The benefits under the above Scheme will be available to all permanent workmen of the Company covered by this Settlement.

(b) The workmen must have completed one year's service to enable him/her to get the benefits under this Scheme. A workman will be entitled to join this scheme on the 1st day of January of the year following completion of his/her one year's service.

(ii) The Company will create a separate fund called the Company's Medical Aid Fund for Medical aid of the workmen by contributing to the said fund a sum of Rs. 75/- per year to the credit of each workman, to be utilised for the benefit of the workman in the manner hereinafter provided.

(iii) A workman will take medical treatment as and when he may require the same from his own Doctor who shall be a registered medical practitioner.

(iv) Any workman entitled to the benefits of the Scheme will submit his/her Bill in respect of costs of mixtures, injections, prescribed medicines, X-Rays, Pathological examinations, specialists' consultation fee but excluding dentists' Bills and maternity expenses, together with supporting vouchers at the end of every three months, viz. 31st March, 30th June, 30th September, and 31st December of every year, for medical treatment undergone by him/her to the Company who, if satisfied about the same, will reimburse the workman by paying three-fourths of the amount of the bill out of the amount standing to his/her credit in the said fund, PROVIDED THAT the amount payable to a workman shall not exceed Rs. 75/- per year.

(v) If a workman has not taken advantage of the medical benefit available to him/her under the Scheme during any year, he/she will be entitled to accumulate the unused or unspent amount lying to his/her credit for three consecutive years, i.e. to accumulate to his credit a sum of Rs. 225/- and he/she may if so necessary, be allowed to take benefit of the scheme upto Rs. 225/- for the three years, PROVIDED THAT if the amount or any part thereof is not utilized by the workman at the end of the period of three years the amount over and above Rs. 225/- shall lapse to the Company.

(vi) A workman shall take all reasonable precautions to prevent injury or illness to himself/herself and especially when any disease is prevalent in epidemic form.

(vii) If a permanent workman has to undergo hospitalisation treatment, the Company will bear and pay the expenses of such hospitalisation upto three-fourths of such expenses of hospitalisation actually incurred by the workmen on production of the Bills. The bills that will be reimbursed by the Company shall not exceed three weeks hospitalisation per year, in the manner specified below:

Three-fourths of actual charges but not exceeding:

Clerical Staff including Sectional Heads—Rs. 20/- per day as room charges.

Subordinate & Drivers—Rs. 10/- per day as room charges.

In addition to the above, operation and other medical expenses incidental to the hospitalisation, such as honoraries visit charges, operation theatre or table charges, medicines and injections will also be borne by the Company to the extent of three-fourths of the amount applicable to the class nearest to the one referred to in this paragraph.

The Company will reimburse a workman to the extent of three-fourths of hospitalisation expenses as mentioned above on production of Bill of such charges. The maximum amount that the Company will pay under this head will be Rs. 500/- per year.

(viii) Under this Scheme of Medical Aid, a workman will not be entitled to medical benefit in the following cases:

- (a) Insanity, venereal diseases or any medical treatment necessitated by workman's own negligent rash and reckless act,  
and/or
- (b) Any medical treatment other than hospitalisation taken by a workman outside the City-Town where the Office of the Company concerned is situated. (The benefit, will, however, be available to such workmen who have their place of residence outside the City/Town where the office of the Company is situated, and who attended to their work from such place of residence).

Reliefs under Clause (8) shall be available from 1st January 1970.

9. *Gratuity*.—Every workman shall be paid gratuity as follows—

1. *On retirement*.—One month's basic salary for each completed year of continuous service, subject to a maximum of 20 months basic salary.
2. *In the event of death of an employee or disability (Permanent) certified by the doctor nominated by the Company whilst in the service of the Company*.—One month's basic salary for each completed year of continuous service subject to a maximum of 20 months basic salary to be paid to the disabled workman or if he dies, to his/her heirs, executors, legal representative or assigns.
3. *In the event of resignation after 10 years service*.—Three-fourths of a month's basic salary for each completed year of continuous service but not exceeding 20 months basic salary.
4. *On termination of service by the Company*.—(a) After 5 completed years of continuous service but less than 10 years service  $\frac{1}{2}$  (half month's basic salary) for each completed year of service.  
(b) After 10 completed years of continuous service but less than 15 years of service  $\frac{3}{4}$  of a month's basic salary for each completed year of service.

After 15 completed years of continuous service 1 month's basic salary for every completed year of service subject to a maximum of 20 months' basic salary.

In the event of dismissal of a workman for gross misconduct involving financial loss to the Company, the amount of gratuity if any payable shall be reduced by the amount of the financial loss caused to the Company by misconduct resulting in the termination of the service.

The salary for the purpose of calculating gratuity will be the monthly basic salary exclusive of all allowances payable to a workman on the date the workman ceases to be in the employment of the Company.

10. *Hours of Work*.—The present practice regarding the working hours will continue.

11. *Holidays* —All public Holidays declared by the Government of Maharashtra under Negotiable Instrument Act except 30th June and 31st December or such Holidays which relate to the affairs of Bank, will be granted

12. *Overtime*.—Overtime payment for actual number of hours worked after the normal working hours by a workman will be made at the rate of  $1\frac{1}{2}$  times of his basic wage plus the Dearness Allowance. The Staff will be required to work overtime on the instruments of the Officer-in-charge of the Department.

NOTE.—It is agreed between the parties that no additional payment on account of overtime, if any, done by a workman prior to the date of signing of this settlement will be due or claimed by the workman due to revision of wages under this settlement.

13. *Provident Fund*.—The present Provident Fund Scheme will continue. The Company shall carry out necessary charges in the event of directions from the Commissioner for Provident Fund under P.F. Act.

14. *Leave*.—(a) *Privilege leave*.—For every eleven months of actual service with the Company, the workman will be entitled to 30 days' privilege leave. Such leave when due can be accumulated upto a maximum of 120 days but no workman will be allowed more than 60 days leave at a time. Accumulated leave in excess of 120 days will be deemed to lapse. Applications for privilege leave will be made 15 days in advance. Privilege leave may be prefixed or suffixed to holidays. Privilege leave when due will be granted according to the exigencies of the Company's business. If a workman is refused privilege leave when applied for, his rights in respect of such leave will be safeguarded.

A workman who is on privilege leave should not in normal course request for extension of leave. However, in case such extension is unavoidable, prior application for extension of leave should be made before the expiry of the leave already granted. Management on receipt of such application will communicate its decision on such an application. Failure to apply will result in loss of pay for the days of his absence from duty after the expiry of the sanctioned leave. The absence shall also be treated as unauthorised absence.

The workmen are not entitled to and the Company is not bound to encash the Privilege Leave. The Company may in its discretion consider individual cases where the accumulation as on 1st January 1970 is more than 120 days.

(b) *Casual Leave*.—A workman will be allowed 15 days casual leave per calendar year to meet casual and unforeseen circumstances. Not more than 3 consecutive days casual leave will be allowed at a time. Casual leave will either be prefixed or suffixed (but not both) to Sundays and Bank Holidays, but only with the previous permission of the Management.

Casual leave shall not be availed of as far as possible, unless previously applied for and sanctioned by the Management. The need for previous application can be waived only in case of absence due to illness or accident, or other urgent reason deemed reasonable by the Management.

If a workman is marked late for more than 3 days in a month, he will forfeit casual leave for one day for every 3 days late coming.

If no medical certificate from a registered medical practitioner is produced, absence due to sickness of not more than 3 days will be treated as casual leave.

(c) *Ordinary Short Sick-leave*.—A workman is entitled to a maximum of 15 days sick leave per year on full pay, subject to his producing a certificate from a registered medical practitioner. The Sick leave shall lapse at the end of each year. If no medical certificate from a registered medical practitioner is produced, absence due to sickness of not more than 3 days will be treated as casual leave. A workman will also be allowed to exhaust his sick leave first, if he is entitled to such leave and thereafter to utilise his privilege leave which may be due to him.

(d) *Prolonged Sick leave*.—A workman is entitled to 15 days of prolonged Sick Leave and which may be accumulated for 120 days on full pay. The workman will be required to produce medical certificate from a Registered Medical Practitioner to entitle him to the benefit of this leave. The Company has the option to get the workman examined by its nominated Medical practitioner and/or consultant.

(e) *Trade Union Leave*.—One member of the staff who is elected to attend the conference of the Insurance Employees' Union will be allowed special leave for a maximum period of 10 days in a year.

15. *Retirement Age*.—The Retirement age fixed is 60 years.

16. *Uniform*.—The present practice shall continue.

17. *Rules regarding Grace Time.*—The grace time allowed is 10 minutes in the morning. It will be understood that this concession is not considered as a privilege for coming to Office late regularly or very often. Adequate reasons would have to be adduced for late attendance beyond ten minutes. Any workman arriving after the grace time will mark his actual time of arrival on the muster roll.

Any workman who comes late in the office for more than three days in a month will be deemed to be absent for one day for every three days of late attendance, and such absence will be deducted from casual leave due to him. In the event, casual leave is not due, the absence shall be deducted against privilege leave, if any, due to him. If no casual leave or privilege leave is due to the workman, the absence will be treated as leave or loss of pay and necessary deduction from salary will be made.

Any workman arriving late by more than one hour but before 1.00 P.M. after the Schedule time shall loose his 1/2 day casual leave. Thereafter he will be marked absent and will not be allowed to work unless permitted by the Head of the Department.

18. (a) The probation period of six months will apply to all workman and in case the management desires to extend further the probationary period, they will have the right to extend the probationary period further not exceeding three months.

(b) No workman will be kept temporary for more than six months in any calendar year.

19. *Victimisation.*—The Company will not victimise or ill-treat any workman for his trade union activities. All trade Union activities shall be carried on outside office hours.

20. *Bonus.*—The declaration and payment of bonus will be subject to the sanction and approval of the Advisory Board and the Central Government.

21. *Period and scope of Settlement.*—This Settlement shall remain in force upto 31st December, 1972.

22. *General.*—(i) In consideration of this settlement all the demands which are subject matter of the dispute in reference C.G.I.T. No. 6 of 1968 which are not specifically covered by this settlement shall be deemed to be settled as having been withdrawn and the workmen shall not agitate the said demands during the currency of this settlement.

(ii) All payments accrued to the credit of the workman as a result of this settlement shall be paid as early as possible but not later than two months from the date of this Settlement.

(iii) Any dispute arising out of the interpretation of any clause of this Settlement shall be settled between the parties to the dispute by mutual discussions. Failing this, the parties will resort to the provisions of the Industrial Disputes Act or any other law for the time being in force.

23. This Settlement is arrived at with the sincere intention of maintaining cordial relations between the workmen and the management. The management and workmen shall carry out the terms of this Settlement in its true spirits.

24. The parties shall make an application before the Central Government Industrial Tribunal in Reference No. C.G.I.T. No. 6 of 1968 to make an award in terms of this Settlement. The parties shall also send copies of the Settlement under Section 18(1) read with Section 2(p) of the Industrial Disputes Act, 1947, to the various authorities prescribed under the Act.

In witness whereof the parties hereto have set their hands the day and the year first above written.

Signed for and on behalf of  
the Workmen by General Insurance  
Employees' Union, W.Z. Bombay.

(Sd.)

Acting General Secretary,  
General Insurance Employees' Union,  
W.Z. Bombay.

Witnesses:

- (1) Sd/- P. S. MEHTA,  
Group Secretary.
- (2) Sd/-

Signed for and on behalf of  
Skandia Insurance Company  
Limited.

(Sd.)

Manager,  
Western Division.

Witnesses:

[No. F. 26/2/68/LR-III(L.R.I.).]

New Delhi, the 25th July 1970

S.O. 2592.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the National Industrial Tribunal, New Delhi, in the matter of an application under Section 33A of the Industrial Disputes Act, 1947 filed by Shri Sanjiva Rama Palan, a Stenographer in the Life Insurance Corporation of India which was received by the Central Government on the 15th July, 1970

BEFORE THE NATIONAL INDUSTRIAL TRIBUNAL, HON'BLE SHRI D. S. DAVE,  
RETIRED CHIEF JUSTICE, RAJASTHAN.

[Reference Complaint No. Comp./NIT/4/70 under Section 33-A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) in the matter of Reference No. NIT 1 of 1969.]

BETWEEN

Shri Sanjiva Rama Palan, Stenographer, Life Insurance Corporation of India,  
Central Office, Secretarial Department, 'Yogakshema' Jeevan Bima  
Marg, Bombay—20—Complainant.

AND

Life Insurance Corporation of India, Western Zonal Office, Jeevan Kendra,  
Jamshedji Tata Road, Bombay—20—Opposite Party.

PRESENT:

Shri P. S. Khara, Advocate, with Shri N. Chakravorty on behalf of the  
complainant, Shri Sanjiva Rama Palan.

Shri B. H. Bhukhanwala, Dy. Secretary, and Shri A. W. Dharwadkar, Asstt.  
Secretary, L.I.C. Central, Bombay for the Life Insurance Corpora-  
tion of India.

AWARD

This is a complaint under Section 33-A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) by Shri Sanjiva Rama Palan, who is a stenographer at the Central Office, Secretarial Department of the Life Insurance Corporation of India at Bombay.

It is averred by him that the Life Insurance Corporation of India, which will hereinafter be referred to as 'the Corporation', had issued Administrative Instructions under Reg. 4 of the L.I.C. (Staff) Regulations, 1960 on the subject of "Procedure for Promotion of Class III and Class IV Staff". These instructions were incorporated in the Corporation's Establishment Manual, and it was provided in the Standing Order, that there would be no interview for selecting the employees possessing requisite qualifications, to the cadre of Higher Grade Assistant. The complainant's grievance is, that the Zonal Promotion Committee appointed by the Zonal Manager of the Corporation committed breach of the aforesaid Standing Orders and conducted interviews for selecting eligible employees to the cadre of Higher Grade Assistant. After the said interview, a ranking list of employees recommended by the Zonal Promotion Committee, was published by the Zonal Manager on

21st July, 1969 and promotions were elected on that basis. The complainant possessed the requisite qualifications and he was eligible for promotion to the cadre of Higher Grade Assistant as per Standing Orders without any interview and he was directed to appear before the Zonal Promotion Committee for interview and he had to act accordingly. His name was not recommended by the said Committee and, therefore, he was not promoted. It is urged by him that an industrial dispute was referred to the National Industrial Tribunal on 28th November, 1963 and thereafter the Corporation could alter the conditions of service applicable to workmen only in accordance with the Standing Orders and since the Corporation committed a breach of the Standing Orders, it has contravened the provisions of Section 33(2)(a) of the Industrial Disputes Act, 1947.

During the course of arguments, he filed an affidavit to the effect that 4 out of the 30 employees who were promoted to the Higher Grade Assistant's cadre according to the ranking list prepared by the Zonal Promotion Committee, were junior to him in length of service and, according to him, if interviews were not held and selections were made only on the basis of length of service and confidential reports, according to the Standing Orders, he would have been promoted in preference to them. It is prayed by him that the Tribunal should pass such order as it may deem fit and proper in the circumstances.

The complaint has been opposed on behalf of the Corporation. A preliminary objection has been raised to the effect that the complainant had appeared at the interview on the 4th November, 1968 while the Tribunal was constituted much later, that is, on the 28th November, 1968 and, therefore, even if the Corporation had effected any change in the conditions of service applicable to the complainant, the provisions of Section 33(2)(a) could not be invoked and the application under Section 33 A of the Act was therefore not maintainable. It is next urged that even if the eligible employees were not interviewed, the complainant could not be selected in preference to those who have been selected because he obtained less marks in their comparison on the basis of length of service and confidential reports. An affidavit of Shri Devidas Purshotamdas Jai, Assistant Secretary in the Zonal Office, Bombay, has been put in, on behalf of the Corporation, along with three lists marked Ex. 1, 2 and 3, to prove that the complainant had no chance of promotion even without an interview.

Before considering the arguments of the parties it may be pointed out that in the L.I.C. (Staff) Regulations, 1960, Reg. 7(2), which deals with promotion, runs as follows:—

"Promotion shall be based on merit, suitability of the candidate for a particular post and seniority. Merit and suitability may be judged by confidential reports and/or interviews and/or examinations".

According to this Regulation, interviews in connection with promotions were not ruled out. Regulation 4, however, provides that—

"The Chairman may, from time to time, issue such instructions or directions as may be necessary to give effect to, and carry out, the provisions of these regulations and in order to secure effective control over the staff employed in the Corporation."

In exercise of these powers instructions are issued from time to time and they are incorporated in what is known as the 'Life Insurance Corporation of India Establishment Manual'. At page 139 of the Manual, the instruction regarding promotion to the cadre of Higher Grade Assistant is given as follows:—

A "Selection for promotions to this cadre shall be made only from among employees who have passed the following examinations;

- (a) Associateship Examination of the Federation of Insurance Institutes.
- (b) Associateship Examination of the Chartered Insurance Institute.
- (c) Intermediate Examination of the Institute of Chartered Accountants.
- (d) Three subjects of the Examination of the Institute of Actuaries."

At page 142, another instruction regarding promotion to the cadre of Higher Grade Assistant is given as below:—

B "Selection to this cadre will be based on the following criteria:—

- (a) Length of service,
- (b) Confidential report, and
- (c) Availability of vacancies.

There shall, however, be no interviews for promotion to this cadre."

It is clear from the perusal of the instructions marked A that selection for promotion to the cadre of Higher Grade Assistant could be made only from among those employees of the Corporation, who had passed the examinations mentioned therein. In other words, unless an employee had acquired the qualifications mentioned therein he could not be eligible for promotion. Then, according to the next rule, marked B, noted above, if vacancies were available, only two criteria were laid down for selection to the cadre of Higher Grade Assistant the first being the length of service and the second the confidential report. Then, there was a clear instruction to the effect that there should be no interview for promotion to the cadre of Higher Grade Assistant.

In the present case, it is not denied by the Corporation that the complainant was eligible for promotion as he had acquired the requisite qualifications. It is also not in dispute that if the instructions were strictly followed there should have been no interview for selecting employees to the cadre of Higher Grade Assistant. As noted above, the complaint has been opposed on the ground of jurisdiction and also on merits. The questions for determination, therefore, are whether this Tribunal has jurisdiction to interfere on behalf of the complainant and secondly, whether any relief may be given to him.

To begin with the first question, it is not denied by the complainant that he had appeared at the interview on the 4th November, 1968 and that no reference regarding any industrial dispute was pending at that time. It is, however, argued by his learned Counsel that the ranking list was prepared after the reference (dated the 28th November 1968) on the 21st July 1969 and the results were declared thereafter. Thus the complainant was deprived of his promotion after the reference and, therefore, according to learned Counsel, the Tribunal should hold that the Corporation has contravened the provisions of Section 33(2)(a).

In reply, it is contended on behalf of the Corporation that the alleged breach of the Standing Orders, if any, had taken place long before the reference was made. No further alteration in the conditions of service was effected by the Corporation thereafter. The effect of the interview also took place on that very day. Its publication was to follow as a necessary corollary and thus the Corporation could not be said to have contravened the provisions of Section 33(2)(a) simply because the result was declared after the reference and it was not favourable to the complainant. In support of this argument, reliance has been placed on a decision of the Labour Appellate Tribunal of India in the case between Imperial Chemical Industries (India) Ltd., Amritsar and Chunni Lal, 1957 II L.L.J. 153. In that case the company had served on its employee, Shri Chunni Lal, a notice on the 5th July, 1955 terminating his services with effect from 6th August, 1955 as a measure of retrenchment. Before expiry of the said period, the company served him with another notice on 25th July, 1955 terminating his services from the 31st August 1955 instead of the earlier date. In accordance with this notice his services stood terminated on the 31st August, 1955. An industrial dispute was referred to the Industrial Tribunal, Punjab on the 16th August, 1955. On the 2nd September 1955 Chunni Lal filed a complaint under Section 33-A of the Industrial Disputes Act. The lower Tribunal negatived the contention of the employer to the effect that the discharge being made before the reference the complaint was not competent. On an appeal by the employer the Appellate Tribunal reversed this decision. After referring to a number of authorities it was observed as below:—

“Stating generally, the principle is that Section 33 of the Industrial Disputes Act as also Section 22 of the Industrial Disputes (Appellate Tribunal) Act prohibits only the doing of certain acts prejudicial to the worker pending the tribunal proceedings and does not touch the question of the effect of something already done, where that effect is automatic. In other words, only an overt act of the kind mentioned in that section, pending the tribunal proceedings, will come within the mischief of the section and not also the automatic effect of an anterior act.”

I agree with the above observation. The alleged breach of the Standing Orders in the present case also was committed as soon as the eligible candidates were called for interview. It was open to the complainant to challenge that order before a competent authority, but instead of doing so, he appeared at the interviews on the 4th November, 1968 and marks must have been allotted to him the same day. The breach of the Standing Orders in his case was thus complete before the reference was made. It cannot be justly held that the Corporation contravened the provisions of Section 33(2)(a) simply because the result was declared after the Reference. By the declaration of result, the complainant was

only intimated about the outcome of what had taken place on the 4th November 1966. The Corporation cannot be said to have contravened the provisions of Section 33(2)(a) by the declaration of result. The complaint is, therefore, not maintainable.

It may next be observed that even if this Tribunal were to hold that the complaint was competent, the only order which it could pass would have been to quash the selection proceedings and direct the Corporation to select the candidates again strictly in accordance with the Standing Orders marked A and B without holding an interview. The Tribunal could not select and promote the complainant to the cadre of Higher Grade Assistant. It may be pointed out that in the case between *Broke Bond (India) (Private) Ltd., and their Workmen*, 1966 1 L.L.J. 402, the management had promoted two employees from Grade A to Grade B. A dispute was raised by certain workmen on account of their supersession. The Tribunal went into the merits of the case and ordered that 5 employees should be promoted from Grade A to Grade B with effect from the date on which the other two persons were promoted. The case went in appeal by special leave before the Supreme Court. It was observed by their Lordships as follows:—

Generally speaking, promotion is a management function; but, it may be recognized that there may be occasions when a tribunal may have to interfere with promotions made by the management where it is felt that persons superseded have been so superseded on account of mala fides or victimization. Even so after a finding of mala fides or victimization, it is not the function of a tribunal to consider the merits of various employees itself and then decide whom to promote or whom not to promote. If any industrial tribunal finds that promotions have been made which are unjustified on the ground of mala fides or of victimization, the proper course for it to take is to set aside the promotions and ask the management to consider the cases of superseded employees and decide for itself whom to promote, except of course the person whose promotion has been set aside by the tribunal."

It may be observed that in the present case the real grievance of the complainant was only against four out of the 30 employees who were promoted to the Higher Grade Assistant's cadre, since, according to him, they were junior to him in length of service. It would have been difficult for the Tribunal to set aside the promotion of even these 4 persons because they were not impleaded as parties to the case and it would have been very unfair for the Tribunal to pass any order to their prejudice in their absence. Moreover, it appears from the perusal of Ex. 3 appended to the affidavit of Shri Devidas Purshotamdas Jai, Assistant Secretary in the Zonal Office, Bombay, referred above, that even after excluding the marks of the interview the complainant could not claim his promotion in preference to the said 4 employees, namely, Shri B. G. Nebhwani, Shri S. S. Puthran, Shri G. M. Sadalgi and Shri K. Shriraman, because even after excluding the marks of interview they had obtained more marks in comparison to the complainant on the basis of length of service and confidential reports. Thus the complainant could not get any relief even if the Tribunal were to quash the proceedings of selection.

The complaint is, therefore, not only not maintainable, but there is no substance therein even on merits. It is accordingly dismissed, but in the circumstances of the case the parties are left to bear their own costs.

*Dated, New Delhi, the 14th July, 1970*

(Sd.) D. S. DAVE,  
Presiding Officer,

National Industrial Tribunal.

[No. 40/24/70-L.R.I.]

#### ORDER

*New Delhi, the 20th July 1970*

**S.O. 2593.**—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Hongkong and Shanghai Banking Corporation and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And where, the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta constituted under section 7A of the said Act.

#### SCHEDULE

"Whether the demand for special allowance of Electrician in respect of Shri Hidayatulla Khan a workman of the Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Calcutta is justified? If not, to what relief is he entitled and from what date?"

[No. 23/47/70/LR.III.]

S. S. SAHASRANAMAN, Under Secy.

#### आदेश

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 1970

सं० प्र० 2593.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में दि हांगकांग एण्ड संधाई बैंकिंग कारपोरेशन में सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

#### अनुसूची

"क्या दि हांगकांग एण्ड संधाई बैंकिंग कारपोरेशन, कलकत्ता के एक कर्मकार, श्री हिदायतुल्ला खां के बारे में इलेक्ट्रिशियन के विशेष भत्ते की मांग न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो वह किस अनुतोष का और किस तारीख से हकदार है ?"

[सं० 23/47/70/एल० प्र० III]

एस० एस० सहस्रनामन, अवर सचिव ।